# यूनियन धारा
# Union Dhara

जिल्द 43, सं.2 Vol. XXXXIII No. 2, मुंबई

अप्रैल – जून, 2018

## हमें अपना **पैसा वापस** चाहिए!

## We want our **Money Back!**

***एनपीए प्रबंधन एवं लाभप्रदता विशेषांक***

***Special issue on NPA Management & Profitability***

गृहपत्रिका • HOUSE MAGAZINE OF यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

# अनुक्रमणिका Contents

प्रकाशन तिथि: 07-08-2018

यूनियन धारा UNION DHARA
अप्रैल - जून, 2018 April-June, 2018

महाप्रबंधक (मा.सं.)
**ब्रजेश्वर शर्मा**
General Manager (HR)
**Brajeshwar Sharma**

संपादक
**डॉ. सुलभा कोरे**
Editor
**Dr. Sulabha Kore**

संपादकीय सलाहकार
**अविनाश कुमार सिंह**
**के. पी. आचार्य**
**नितेश रंजन**
**राजेश कुमार**

Editorial Advisors
**Avinash Kumar singh**
**K. P. Acharya**
**Nitesh Ranjan**
**Rajesh Kumar**

Printed and published by Dr. Sulabha Kore on behalf of Union Bank of India and printed at SAP PRINT SOLUTIONS PVT. LTD. Lower Parel, Mumbai-400013.

and published at Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

Editor: Dr. Sulabha Kore
E-mail: sulabhakore@unionbankofindia.com

Our Address : Union Dhara, 11th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

E-mail: uniondhara@unionbankofindia.com
Mob. No. 9820468919
Tel.: 22896595 / 22896545 / 22896590

परिदृश्य ...............................3-4
संपादकीय..................................5
GM's Desk/RBI Award ............6



Legal Aspects of NPA Management........................7-9
साहित्य जगत से ...................10-11
काव्यधारा..........................12-13
भारतीय परिप्रेक्ष्य में बैंकों में एनपीए प्रबंधन......................14-15
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए में आयी अचानक बढ़ोत्तरी .........16-17
शिखर की ओर/हमें गर्व हैं/ बधाई ...............................18-19
संदिग्ध बैंक - कारण और उपाय........ 20
Process of Challenges ........... 21
वित्तीय संकट की शीघ्र पहचान ....22-23
Prudential Norms on... ....24-25
Tools & Techniques.........26-27
Proper & Timely Monitoring & Supervision of NPA ..........................28-29
Is OTS a Moral Hazard .....30-31
Sales of Assets ................31-32
Performance Always Pays Back!!.......................... 33
बासेल मानदंडों की अनुपालना ....34-35
शुभमस्तु.................................. 35
Use of Digital Technology in NPA Management........36-37
खेल जगत से ............................. 37
Retired, But Not Tired ......38-39
Legally Speaking.............40-41
Centre Spread ................42-43
UniOne ...........................44-45
Insolvency & Bankruptcy..46-49
नया क्या है?............................ 49
SARFAESI Act.................50-52
बाल प्रतिभा............................... 53
Credit Appraisal & NPA....54-55
चरक का कोना........................... 55
बैंकों की लाभप्रदता में वसूली......56-57
सफलता की कहानियां ............58-62
Impact of NPA... .................. 63
Face in UB Crowd...........64-65
नयी प्रतियोगिता.......................... 66



समाचार दर्शन ......................67-81
हेल्थ टीप्स/व्यंजन ....................... 82
आपकी पाती.............................. 83
Back Cover .......................... 84

इस पत्रिका में व्यक्त विचारों से प्रबंधन का सहमत होना अनिवार्य नहीं है

Designed and Printed at **SAP PRINT SOLUTIONS PVT. LTD.**, Lower Parel, Mumbai - 400 013.

# परिदृश्य Perspective

दोस्तों,

बैंकिंग उद्योग एक गंभीर मंथन के दौर से गुजर रहा है. विनियमन, प्रौद्योगिकी और परस्पर प्रतिस्पर्धा ने परिचालन परिस्थितियों में एक ऐसे बदलाव के प्रति हमें मजबूर किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ. भारतीय बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, बैंकिंग एक आस्ति चालित व्यवसाय रहा है. अतः जोखिम और आय के संतुलन के साथ गुणवत्तापूर्ण आस्तियों का निर्माण अनिवार्य है. क्रेडिट अंडरराइटिंग की वर्तमान संरचना अपर्याप्त साबित हुई हैं, क्योंकि ऋण आस्तियों का छठां हिस्सा दबावग्रस्त है, जिसके परिणामस्वरूप किए गए प्रावधानीकरण ने हमारी लाभप्रदता और आरक्षित पूंजी को भी भारी क्षति पहुंचायी है. मुझे खुशी है कि हमारी द्विभाषिक पत्रिका 'यूनियन धारा' ने 'आस्ति गुणवत्ता' को इस अंक के थीम के रूप में लिया है. मुझे विश्वास है कि इससे चुनौतियों के साथ–साथ उनके प्रभावी रूप से निपटान हेतु हमारी जागरूकता प्रभावी रूप से बढ़ेगी.

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन के दो पहलू हैं: 'स्टॉक' और 'फ्लो'. स्टॉक का संबंध पहले से खराब हो गए ऋण से है; या तो उधारकर्ता द्वारा कर्ज चुकौती बंद कर दी गई है या फिर अनियमित है. विनियामिकीय वर्गीकरण तनावग्रस्त आस्तियों के स्टॉक को गैर निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए) में मानता है, जहां उधारकर्ता ने 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया राशि का भुगतान न किया हो, और विशेष उल्लिखित खाते (एसएमए), जो कि एनपीए होने से पहले और भुगतान हेतु निर्धारित अवधि के बीच की अवधि में हों.

आज हमारी चिंता सिर्फ लार्ज टिकट एनपीए का उच्चस्तरीय स्टॉक ही नहीं है, जो कि इन्सोल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी) पद्धति के तहत समाधान के विभिन्न स्तरों पर हैं, बल्कि एनपीए का ताजा 'फ्लो', विशेषरूप से रिटेल, कृषि और एमएसएमई (रैम क्षेत्रों) के विविध खंडों में स्लिपेज ज्यादा चिंतनीय है. रैम पोर्टफोलियो का विश्लेषण यह दर्शाता है कि भारी मात्रा में खाते एसएमए संवर्ग में शामिल हो रहे हैं, जो शुभ संकेत नहीं है और इससे शाखाओं के उत्पादक समय का महत्वपूर्ण हिस्सा, इन खातों का वसूली प्रबंधन करने में व्यतीत हो रहा है. केवल 60 प्रतिशत उधारकर्ता अपनी बकाया राशि समय पर भर रहे हैं. ये हालात निश्चित रूप से बदलने चाहिए.

दबावग्रस्त आस्तियों के उच्च स्टॉक का निपटारा हमारी प्राथमिक अनिवार्यता रहेगी. साथ ही साथ इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम क्षमता निर्माण कर रहे हैं, जिससे नए ऋणों में दबाव का 'फ्लो', रूक जाए. क्रेडिट अंडरराइटिंग यदि सावधानीपूर्वक किया जाता है तो वह चूक की संभावना को काफी हद तक कम कर देता है. वर्तमान प्रक्रिया में, प्रोसेसिंग शाखाओं की ओर से की जाती है जबकि ऋण प्रस्ताव विभिन्न स्तरों जैसे क्षेत्र/अंचल/कॉर्पोरेट कार्यालय से

Dear Friends,

Banking industry is undergoing a serious churn with regulations, technology and competition, forcing change in operating milieu like never before. For Indian banks, particularly, the public sector banks (PSBs), banking remains an asset driven business. Building quality assets with balancing of risks and returns, therefore, is essential. The present structure of credit underwriting has proven to be inadequate, as reflected in a sixth of loan assets stressed, with consequent provisioning hurting our profitability and even draining the capital reserves. I am happy to see Union Dhara, our bilingual magazine, making asset quality as theme for this issue. I hope it will raise awareness about the challenges as well as the various tools available to tackle it effectively.

There are two aspects to the stressed asset management: 'Stock' and 'Flow'. The 'stock' is about loans already turned bad; either debt servicing by borrowers has stopped or it's errant. Regulatory classification puts the stock of stressed assets as non-performing assets (NPAs), where borrower has not paid the dues for more than 90 days, and special mention accounts (SMAs), which is for the period intervening due date of payment and before it turns NPA.

Our concern today is not just the high level of stock of large ticket NPAs, which are at varied stages of resolution in the insolvency & bankruptcy code (IBC) regime, but the fresh 'flow' of NPAs, especially, the slippages from the diversified segment of Retail, Agriculture and MSMEs (the RAM sectors). Delinquency analysis of the RAM book points towards large volume of accounts under the SMA categories, which is taking significant portion of productive time of the branches into managing collection in these accounts. Only 60 per cent of borrowers are paying their dues within time. This state of affair must change.

While resolving high stock of stressed assets will remain a near term imperative, we are simultaneously building capabilities to avert the recurrence of it, viz. the 'flow' of stress from new loans, going forward. Credit underwriting, if done diligently, reduces the chances of default significantly. However, in our system, processing used to be dispersed

होकर गुजरता है. ऐसी स्थिति में, विभिन्न स्तरों पर क्षमताओं की विविधता के अधीन गुणवत्ता को बनाए रखते हुए ऋणों की मंजूरी करने में काफी समय लगता है. 4000 से अधिक शाखाओं के प्रोसेसिंग पार्ट को चुने हुए केन्द्रों में प्रशिक्षित एवं विशेषीकृत अधिकारियों के बीच केन्द्रीकृत किया जा रहा है. यह दोनों तरह से फायदेमंद है. एक तो, शाखाओं को अनुश्रवण एवं नया बिजनेस लाने के लिए मुक्त किया जा सकेगा, दूसरे इससे प्रोसेसिंग की गुणवत्ता को सुधारने एवं ड्यू डिलिजेंस को बढ़ाने में मदद मिलेगी.

इसके अलावा 'फ्लोज' के बेहतर प्रबंधन हेतु हम अनुश्रवण, संग्रह एवं वसूली के लिए बेहतर और विभेदित संरचना स्थापित कर रहे हैं. बैंक ने पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडबल्यूएस) विकसित की है, जो आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों के 28 पैरामीटरों पर स्ट्रेस सिग्नल की पहचान करती है, जिसमें उधारकर्ता की रेटिंग एवं स्वास्थ्य गतिविधि, वित्तीय लाभप्रदता, आचरण दोष, लेनदेनों के आंकड़े एवं उनके द्वारा विनियामिकीय अपेक्षाओं के साथ–साथ नियम एवं शर्तों की अनुपालना शामिल हैं. इसमें सिबिल की सीएमआर रेटिंग जैसे बाहरी इनपुट भी शामिल किए जाएंगे. खाते के एसएमए में जाने से पहले ही ईडबल्यूएस स्ट्रेस में आने वाले खातों की जानकारी दे देगा.

हमारे यहाँ एक सिस्टम चालित एस्केलेशन मैट्रिक्स है, जो कि चेतावनी ट्रिगर और निरीक्षणों के आधार पर मामलों की जांच करने में मदद करेगी. यदि रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा कारणों के पुनर्मूल्यांकन का प्रस्ताव रखा जाता है तो ऋण विभाग मूल्यांकन करता है और अंतिम संवर्ग को मंजूरी देता है तथा समाधान के लिए विशेषीकृत टीम के साथ एक संरचनात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाती है. इसमें शामिल हैं– एसएमएस/ईमेल के माध्यम से डिजिटल चेतावनी, दूरभाष के माध्यम से कार्यवाही करना एवं जटिल मामलों में, विशेष रूप से प्रशिक्षित वसूली अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाना.

नवनिर्मित प्रणाली के परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे, जबकि बैंक के शताब्दी वर्ष में लाभप्रदता की ओर बढ़ने के लिए किसी भी अन्य चीज के अलावा सबसे महत्वपूर्ण हैं, वसूली एवं दबावग्रस्त आस्तियों के उन्नयन के लिए हमारे प्रयास! मैं प्रत्येक यूनियनाइट से अनुरोध करता हूँ कि वे बैंक की विभिन्न सेटलमेंट योजनाओं के साथ ही सरफेसिया, आईबीसी इत्यादि के अंतर्गत समय पर कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ कर एनपीए उधारकर्ताओं से वसूली हेतु संगठित प्रयास करें. उधारकर्ताओं को बातचीत के टेबल पर लाने में शीघ्रता के साथ ही दृढ़ता भी दिखाएँ. जहां भी आवश्यकता होगी, हमारी ओर से आपको पूरा समर्थन प्राप्त होगा.

आपका

**राजकिरण रै जी.**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

across branches, and proposals escalate through layers like region/zones/corporate offices. It is a time-consuming exercise, with quality subject to capabilities across different layers. Centralization helps in shifting the processing part from 4000 plus branches to trained & specialized officers in select centres. This works in both ways, by making branches free for monitoring & mobilizing new business as also improve quality of processing & enhanced due diligence.

Moreover, to manage the 'flows' better, we are instituting better and differentiated structure for monitoring, collections and recoveries. The Bank has developed its early warning systems (EWS), identifying stress signals on 28 parameters, which are inclusive of internal and external triggers. It covers movement in health & rating of borrower, financial profitability, delinquency behaviour, transactional data, and their adherence to terms & conditions including regulatory requirements. There will also be taking external inputs like CMR Rating from CIBIL. The EWS will thus pick stress even before the account goes into SMA.

There is a system driven escalation matrix which would help verify the cases based on warning triggers and observations. If re-evaluation of triggers is proposed by Relationship Manager, Credit Department evaluates and approves the final class and a structured process with specialized team for resolution gets triggered. It involves digital alerts through SMS/e-mail, follow-up through telecon, and for tough cases, physical visits by specially trained recovery officers.

While newly built systems will yield results in future, to turn our ways to profitability in the Centenary Year of the Bank, our efforts on recoveries and up-gradation of stressed assets will matter more than anything else. I urge every Unionite to make concerted efforts for recovering from NPA borrowers, utilizing different settlement schemes of the Bank as well as initiating timely legal actions under SARAFESIA, IBC, etc. Be prompt yet assertive in getting the borrowers back on negotiating table. You have our full support in whichever way you need.

Yours

**RajKiran Rai G.**
Managing Director & CEO

# संपादकीय

# Editorial

बैंकिंग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. बैंकिंग उद्योग देश के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है. निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि बैंक और वित्तीय संस्थान अपनी आस्तियों का समुचित प्रबंधन करें, परंतु यह उनके लिए अत्यंत कठिन हो रहा है. आजकल हम भारिबैं की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के बारे में काफी कुछ सुन रहे हैं, जिससे बैंकों का एनपीए निरंतर बढ़ता जा रहा है. एनपीए का बढ़ना प्रावधानीकरण को बढ़ाता है, फलस्वरूप लाभ घटता है. एक बार ऋण एनपीए हो जाने के बाद का रास्ता वसूली है.

भारिबैं ने आईबीसी के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए संशोधित फ्रेमवर्क तैयार किया है और कुछ ही दिन पहले दिनांक 12.02.2018 को इसे जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण और सुधार का एजेंडा शामिल है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यूनियन धारा 'एनपीए प्रबंधन और लाभप्रदता' पर अपना विशेषांक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है.

हमारे बैंक ने पूंजी ह्रास की तीव्र चुभन से बचने के लिए रैम क्षेत्र में अपना कारोबार बढ़ाने की रणनीति अपनायी है, जिसमें अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, बैंक एनपीए खातों के समाधान पर आक्रामक रूख अपनाए हुए है. ठीक इसी प्रकार, बैंक अग्रिम संविभाग को सुदृढ़ बनाने हेतु अनुश्रवण पद्धति में गुणात्मक परिवर्तन ला रहा है.

'यूनियन धारा' का यह विशेषांक बिल्कुल सही समय पर प्रकाशित हो रहा है. मैं ऋण वसूली विभाग और उसकी टीम के हरेक सदस्य और विधिक सेवाएं विभाग का अभिनंदन करती हूं एवं उनकी शुक्रगुज़ार हूं, जिन्होंने इस अंक के प्रकाशन में हमें अपना अमूल्य सहयोग दिया. इस अंक हेतु अपना योगदान और समर्थन देने के लिए मैं विशेष रुप से श्री डी. के. गुप्ता, उप महा प्रबंधक का आभार व्यक्त करती हूं.

मुझे विश्वास है कि यह अंक आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी देगा तथा इससे आपकी जानकारी अद्यतन होगी. मुझे यह भी विश्वास है कि यह अंक बैंक को पुनः लाभप्रदता की ओर ले जाने के प्रति आप सभी को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करेगा.

सफल ऋण वसूली प्रयासों हेतु आपको अनेकोनेक शुभकामनाएं.

The Banking industry is the backbone of a country's economy and directly affects its development. In order to ensure continued growth, it is critical that Banks and Financial Institutions are robust in managing their assets. Today one hears a lot about RBI assets quality review leading to large NPA. Rising bad loans leads to higher provisioning thereby reducing profits. Once a loan turns bad, recovery is the next step.

RBI has introduced revised framework for dealing with stressed assets through IBC and more recently – Resolution of Stressed Assets – Revised framework dated 12.02.2018 and the government's re-capitalization & reform agenda for Public Sector Banks. With the above in mind Union Dhara has come out with a special issue on managing & recovery of NPA.

Our Bank has strategically pursued capital light business in the RAM sectors to avoid severe pain of capital erosion and pursued an aggressive stand on NPA resolution. Similarly, Bank is also bringing in qualitative changes in credit underwriting an monitoring system to prevent build up of a toxic advance portfolio.

This issue of Union Dhara could not have come at more relevant time. I congratulate the Credit Recovery Department and its team, each member of team and also Legal Dept. who have supported us in bringing out this issue. I am very thankful to each and every person of this Department. My special thanks to Mr. D.K. Gupta, DGM for his support and contribution in bringing out this special issue.

I am sure, each one of us shall find valuable learning and renewed understanding from these articles, and I am sure this issue shall help in our efforts to bounce back to profitability.

Wishing you success in your recovery endeavours!

आपकी,

Yours truly,

**डॉ. सुलभा कोरे**

**Dr. Sulabha Kore**

# From Desk of GM-CRD

Dear Unionites,

During recent times, crisis of burgeoning NPAs in PSBs needs no introduction. As a part of banking sector, our Bank is also not immune to the problem. High level of delinquencies in the recent past has not only adversely affected our financials but also dented the reputation of never incurring losses.

Being a PSB, our Bank had additional responsibility of looking after growth of economy, which also involved lending to infrastructure and related sectors. After the global meltdown, these sectors were highly impacted which resulted in slippages of big ticket advances to NPA category. This also has a cascading effect resulting in failure of ancillary sectors and MSME advances.

But recent indicators suggest that we have hit the bottom and the only way is going up. There is silver lining at the horizon and things have started improving; albeit slowly. Recently, couple of accounts could be resolved through NCLT route and many more are in pipeline awaiting resolution in the current financial year. Most important thing now is to learn from our past and plan for the future in such a way that we don't end up in any precarious situation. Our endeavour now should be to control slippages and augment recovery.

The time has come for every staff member to go beyond the call of duty and contribute with full might to avert the crisis. It is the time to show our true mettle and emerge as winner in our "War against NPA".

With best regards.

**S. S. Chandrashekhar**

लगातार चौथे साल हमारे बैंक की द्विभाषिक गृहपत्रिका "यूनियन धारा" को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए आयोजित द्विभाषिक गृहपत्रिका प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. साथ ही पूर्व में लगातार तीन साल प्रथम पुरस्कार जीतने के कारण 'कूलिंग पीरियड' में रहते हुये भी वर्ष 2015-16 के लिए यूनियन धारा को 'विशेष प्रशस्तिपत्र' से सम्मानित किया गया. बैंक की हिन्दी गृहपत्रिका "यूनियन सृजन" को वर्ष 2015-16 के लिए 'प्रोत्साहन पुरस्कार' से नवाज़ा गया. दिनांक 26.06.2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. विरल आचार्य के करकमलों से पुरस्कार ग्रहण करते हुए बैंक के महाप्रबंधक (मा.सं.) श्री ब्रजेश्वर शर्मा; साथ में हैं श्री राजेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) और डा. सुलभा कोरे, संपादक, 'यूनियन धारा' एवं 'यूनियन सृजन'.

# Legal Aspects of NPA Management

## 1. Introduction:

Non Performing Asset (NPA) as a jargon had entered the banking lexicon post implementation of Narasimham Committee recommendations in 1992. Since then NPA has become a byword for spurring the bankers into action to recover loans from the borrowers who have failed to repay the loans taken from the banks on time. During the last three years NPA stock amongst the banks has assumed gargantuan proportions from a trickle in 2008 to a deluge now which may, if not contained, destroy the carefully built banking industry in our country. In that back drop, legal aspects of NPA management in general and recovery of loans by pursuing legal remedies in particular assumes enormous significance.

## 2. Tit bits of history:

It is common knowledge that NPA in its earlier avatar was simply known as bad debt recognized as such in the books of accounts of a bank. Legal framework in India for recovery of bad debt accordingly built around the same comprised traditional civil courts, where banks could initiate action for recovery by filing a suit. The process of filing suit and the manner in which the legal remedy for recovery of loan should be pursued was laid down in Code of Civil Procedure 1908, which is the oldest law for recovery of money in India. There was no separate law for recovery of loans for commercial banks. Post independence, influenced by Mahalanobis model of development, the Legal framework for revival and rehabilitation of industries as one of the methods of recovery of loans was put in place through Industries (Development & Regulation) Act. Specialized financial institution to tackle bad debts, namely, Industrial Reconstruction Bank of India was set up under special law called Industrial Reconstruction Bank of India Act, for takeover of bad loans from banks, helping distressed industries and reviving them.

Apart from the above, recovery of NPAs through liquidation of companies or by declaring individuals as insolvents was resorted to under Companies Act and Insolvency Act respectively. Adoption of socialism and economic policies built around concept of welfare state in 1970s and 80s, led to more emphasis on recovery of loans through revival and rehabilitation, than by mere liquidation of assets of the defaulting borrowers. Consequently, Sick Industries Act was enacted as a legal framework for recovery of loans. Economic liberalization in 1990s ushered in change in the economic mindset in India from closed socialistic economy to open economy not averse to private enterprise. The transition had its flipside in the form of Harshad Mehta Scam, which shook the entire banking sector. From the perspective of legal aspects of NPA management, Harshad Mehta Scam was a harbinger of change in the then existing legal framework for recovery of loans. The then government and those that came after relentlessly brought in new laws that shifted the foundation of recovery laws for banks in India.

## 3. Legal Aspects of NPA management:

We are familiar with the regulatory and accounting aspects of NPA management. Framework in that regard is fairly standardized and prescriptive, which helps the banks to implement the same. On the other hand, legal aspects of NPA management involve pursuing legal remedies under various applicable laws for recovery of loans to improve the bottom line. 'Legal aspects' is antithesis to regulatory and accounting aspects in the sense that while one improves the bottom line, the other identifies the stress in the loan book of the Bank. We can count various legal measures for recovery of loans with or without intervention of courts as a part of legal aspects of NPA management. Due to paucity of space, major laws that primarily cater to NPA management of banks are discussed here.

## 4. Recovery through Debt Recovery Tribunals

Debt Recovery Tribunals, DRTs as they popularly called were set up as special courts under special law, namely, Recovery of Debts, Bankruptcy Insolvency Resolution and Bankruptcy of Individuals and Partnership Act 1993 (RDB Act). First DRT was set up in 1996 in Mumbai and there after several DRTs came to be opened across the country. Legal Aspects of NPA management under the aegis of RDB Act in nutshell is under:

- DRTs are specialized courts that have power to entertain and decide cases filed by Banks for recovery of NPAs, where

outstanding together with interest in the NPA account is more than Rs.10 lacs. For loans of less than Rs.10 lacs, legal remedy is before the ordinary civil courts.

- DRTs follow summary procedure as opposed to full-fledged trial of cases in civil cases. RDB Act mandates that cases filed before DRTs should be decided within a period of maximum 6(six) months. The procedure involved is very simple such that if bank has all the proof, documents and evidence properly in place, then DRT is bound to grant recovery certificate quickly.
- As part of NPA management and more particularly managing NPAs through recovery by legal means, RDB Act is one of the best tools and it's up to us (bankers) to utilize the DRTs to recover NPAs. While pursuing the recovery through DRT, the following legal aspects, should be kept in mind, namely;

- We have to ensure that the application being filed before DRTs is properly filled up viz;
  - Names and addresses of the borrowers should be correct and current
  - Details of loans given, present outstanding, details of securities should be accurate
  - Certification and authentication as required under RDB Act should be done before filing the application before DRT.
  - Objections raised by the borrowers should be properly replied duly supported by proof
- RDB Act provides that any party, whether bank or the borrower, if aggrieved by the orders of DRT may file appeal. RDB law has created an appeal tribunal, namely Debt Recovery Appellate Tribunal (DRAT) to entertain, hear and decide appeals against the orders of DRT. If we carefully build the case with all the proof and documents, then we can get the decision from DRAT quickly. Method of filing appeal and getting the order from DRAT is akin to filing application before DRT.
- Once Recovery Certificate is granted by DRT, then the recovery machinery under RDB Act is activated. As a part of recovery machinery, DRTs have recovery officers whose main duty is to recover money by sale of assets of the borrower or by arrest of the borrower. If we have all the details of assets of the borrower, then recovery machinery under RDB Act can be activated and recovery can be effected by the bank quickly. In the case of hard core borrowers, we can have them arrested for recovery.

## 5. SARFAESI Act and the legal aspects surrounding the same:

Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI) was enacted in 2002 to enable banks and financial institutions to take possession of security upon default and realize the same for recovery of dues. This allowed banks and financial institutions to sell the collateral security and recover the outstanding debt without the intervention of a court or a tribunal. Apart from the above, SARFAESI law provided for a legal framework for securitization and reconstruction of loans through specialized financial entities regulated by RBI, namely; Asset Reconstruction Companies (ARCs). Salient legal aspects of NPA management under SARFAESI, in nutshell are as under:

- Under Part 1 of the SARFAESI law, banks are permitted to sell their NPAs to ARCs at mutually agreeable price. Sale to ARC will facilitate removal of NPAs from the books of banks and reduce the Gross Non Performing Assets (GNPA) in the bank.
- Sale of NPAs to ARCs involves the following legal aspects, namely;
  - We should select NPAs that we propose to sell to ARCs.
  - Once selection of NPA for sale is complete then we should obtain valuation of securities from panel valuers.
  - Valuation should be taken as the basis for fixing the minimum price below which bank should not sell.
  - Once valuation is obtained, auction of NPA should be initiated and all the ARCs should be invited to bid for takeover of NPA account.
  - ARC that's the highest bidder should be declared and the process of sale of the account should be completed.
  - SARFAESI act provides different alternatives for composition of price payable by ARCs which we should assess independently and take a view.
- Part II of the SARFAESI empowers all the banks and financial institutions to take possession and realize the securities.
- The procedure for taking possession and realizing the securities by selling them is provided elaborately under the SARFAESI and the rules. The procedure in short is:
  - Since part II of SARFAESI law is applicable only to NPA, before taking action under SARFAESI, it should be ensured that the loan account is classified as NPA as per the definition given under RBI guidelines.
  - As a first step, Bank should give a demand notice to the NPA borrower calling upon him to repay the loan. As per SARFAESI law, the borrower has 60 days time to repay from the date of receipt of demand notice.
  - If the borrower fails to pay up within 60 days, then we may go ahead take possession of the securities and initiate steps for sale of the same.

- There may be instances where borrower is not ready to give possession. In that event Bank should approach District Magistrate and request him to take possession of the securities on bank's behalf, or provide necessary assistance for taking possession.
- After possession is taken, valuation of securities should be taken and thereafter the securities can be sold by way of auction or otherwise to an interested purchaser.

## 6. Insolvency and Bankruptcy Code and what's in there for banks:

The Insolvency and Bankruptcy Code passed by the Parliament is a welcome overhaul of the existing framework dealing with insolvency of corporates, individuals, partnerships and other entities. One of the fundamental features of the Code is that it allows banks to assess the viability of a borrower after default and agree upon a plan for its revival or a speedy liquidation. The Code creates a new institutional framework, consisting of a regulator, insolvency professionals, information utilities and adjudicatory mechanisms, that will facilitate a formal and time bound insolvency resolution process and liquidation.

Banks as lenders would greatly benefit from the Code in the sense that banks have option of resolving either through sale or restructuring of business or by sale of assets through the special courts, namely National Company Law Tribunal (NCLT). Summary of the code is as under:

- Upon default by the borrower, banks can file an application before NCLT for an order on insolvency resolution. Unlike, SARFAESI Act the account need not be NPA. Even a single default is enough to start the process.
- To initiate an insolvency process, the default should be at least INR 100,000. The Code proposes two independent stages:
  - *Insolvency Resolution Process*, during which financial creditors (banks) assess whether the business is viable to continue and the options for its rescue and revival; and
  - *Liquidation*, if the insolvency resolution process fails, financial creditors (banks) may decide to wind up the business of the entity and distributes the assets of the debtor towards satisfaction of their dues.
- The procedure laid down under the Code importantly is as under:

a) *Commencement of the IRP:* A bank (for a defaulted financial debt) can initiate an IRP against a borrower at the National Company Law Tribunal (**NCLT**). The defaulting borrower, its shareholders or employees, may also initiate voluntary insolvency proceedings.

b) *Moratorium:* NCLT orders a moratorium on the debtor's operations for the period of the IRP. This operates as a 'calm period' during which no judicial proceedings for recovery, enforcement of security interest, sale or transfer of assets, or termination of essential contracts can take place against the debtor.

c) *Appointment of Resolution Professional*: NCLT appoints an insolvency professional or 'Resolution Professional' to administer the IRP. The Resolution Professional's primary function is to take over the management of the corporate borrower and operate its business as a going concern under the broad directions of a committee of creditors.

d) *Creditors Committee and Revival Plan*: The Resolution Professional identifies the financial creditors and constitutes a creditors committee. Operational creditors above a certain threshold are allowed to attend meetings of the committee but do not have voting power. Each decision of the creditors committee requires a 75% majority vote. Decisions of the creditors committee are binding on the corporate debtor and all its creditors. The creditors committee considers proposals for the revival of business of the debtor and must decide whether to proceed with a revival plan or liquidation within a period of 180 days (subject to a one-time extension by 90 days). Anyone can submit a revival proposal but it must necessarily provide for payment of operational debts to the extent of the liquidation waterfall.

*e)* *Liquidation*: Under the Code, a borrower company may be put into liquidation in the following scenarios:

- 75% majority of the creditor's committee resolves to liquidate the corporate debtor at any time during the insolvency resolution process;
- The creditor's committee does not approve a resolution plan within 180 days (or within the extended 90 days);
- The NCLT rejects the resolution plan submitted to it on technical grounds; or
- The debtor contravenes the agreed resolution plan and an affected person makes an application to the NCLT to liquidate the corporate debtor.

Once the NCLT passes an order of liquidation, a moratorium is imposed on the pending legal proceedings against the corporate debtor, and the assets of the debtor (including the proceeds of liquidation) vest in the liquidation estate.

- Implementation of the Code had been very swift and major recoveries were achieved through insolvency resolution process under the code.

## 7. Conclusion:

Apart from the major laws that are discussed here, there are many laws under which remedies are available to the banks for recovery of NPAs as part of management of NPAs. Legal aspects each of those laws and the procedure to be followed are elaborately provided in under the Recovery Manual of the Bank. I urge each one of the readers to refer to Recovery Manual and various circulars of recovery department of the Bank to gain insight into varied legal aspects of NPA management.

***P. R. Rajgopal***
*Legal Dept., C.O.*

# कहानी की आंख से जीवन को आंकने वाले कथाकार 'संजीव'

प्रेमचंद और फणीश्वरनाथ रेणु की जनवादी एवं लोकप्रिय परंपरा को बीसवीं सदी के उतरार्ध में एक नई भावभूमि को साथ लेकर उभरे संजीव का जन्म 7 जुलाई, 1947 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बांगर कला नामक गाँव में हुआ था. संजीव के अनुसार ये जन्म तारीख पाठशाला के मास्टर जी ने स्कूल में दाखिला लेते वक्त स्वयं ही लिख दिया था, तब से यही तारीख पड़ गयी वरना, जिस गरीबी और लाचारी के माहौल से संजीव का 20-25 लोगों का परिवार गुजर-बसर कर रहा था वहाँ एक और सदस्य के जन्म पर उस तारीख को हर वर्ष याद रखने की गुंजाइश ही नहीं होती है. इनके कई नाम हैं जैसे संजीवन, सजेवन, साजन और संजीव. संजीव अपने नामकरण के बारे में स्वयं लिखते हैं -

"जीवन के निर्बंध, व्याकरण ने कितनी ही संज्ञाएँ दी – संजीवन, सजीवन, सजेवन, साजन, सजावन और संजीव. इन तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज नामों के साथ राम और प्रसाद के उपसर्ग प्रत्यय और मास्टर का सर्वनाम–विशेषण. जन्म की तिथि हमारे जैसे परिवार के लिए कोई महत्व की बात नहीं थी, अतः पाँचवी कक्षा में नाम लिखने के लिए हेडमास्टर साहब को ही आविष्कृत करनी पड़ी – 6 जुलाई, 1947."

संजीव का जीवन अनेक संघर्षमय प्रसंगों से भरा पड़ा मिलता है. ठाकुरों और ब्राह्मणों के वर्चस्व वाले इस गाँव में घृणा और भेदभाव को वे बचपन से अनुभव करते आए हैं. कुल्टी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के पिछड़े औद्योगिक कस्बे में जब संजीव के काका उन्हें गाँव से निकालकर शहर लाए तब तक उन्होंने एक मनमौजी ढंग से स्वतंत्र हुड़दंग मचाते बच्चे सी जिंदगी जी थी. यह गरीबी और बेफिक्री का सामंजस्य संजीव को बचपन से ही जिज्ञासु बनाए रखता है. उनके परिवार में संपत्ति के नाम पर डेढ़ बीघा उपजाऊ और 4 बीघा ऊसर जमीन थी, जिस पर पूरा परिवार (20–25) निर्भर था. जमीन के अतिरिक्त दशहरे के अवसर पर देवी–देवताओं की अनगढ़ मूर्तियाँ बनाना इनका पारिवारिक पेशा था.

संजीव की प्रारम्भिक शिक्षा कुल्टी में एक पीपल के पेड़ के नीचे शिवजी के चौरा पर चलने वाली रामेश्वर गुरुजी की पाठशाला में अक्षर ज्ञान से शुरू होती है. वे लिखते हैं – "बालक राम संजीवन यदि कुल्टी न आया होता तो किसी की हरवाही कर रहा होता या चारा ढ़ो रहा होता." मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से पास कर संजीव के कॉलेज के दिन शुरू हुए और न चाहते हुए भी बड़े भईया के कारण जबरदस्ती विज्ञान के छात्र बना दिए गए. बड़े भईया बनाना चाहते थे डॉक्टर, इंजीनियर लेकिन संजीव पर बचपन से ही साहित्य के प्रति रुझान बढ़ने लगा था. वे लिखते हैं –

"इच्छा के विरुद्ध विज्ञान का छात्र बना दिया गया. भाषा के प्रति मोह बढ़ रहा था. प्रकृति के रूपों में उलझा–उलझा मन. पंत प्रिय कवि प्रेमचंद, सुदर्शन, शिवपूजन सहाय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचनाओं से अनुप्रेरित होकर पहली हृदय – परिवर्तन की कहानी हस्तलिखित पत्रिका पल्लव में मौसमी लेखन में कविता, कहानी, निबंध के पुरस्कार और भैया बनाना चाहते थे डॉक्टर इंजीनियर. पैसे की औकात रत्ती भर की नहीं थी और फिर मुझे मेंढक, मछलियों को देखकर घृणा आती, काटना तो दूर, छूना भी गवारा नहीं. इंजीनियरिंग में टेस्ट की जगह अपनी दूसरी परीक्षाएं ध्यान खींच ले जाती. मार्क्स के आधार पर दो–एक जगह संभावना जगी

तो आयु आड़े आ गयी. खैर सत्रह साल की आयु में बी.एस.सी. डिस्टिंक्शन से पास कर भईया ने मुझे दिल्ली भेजा ए.एम.आई.ई. पढ़ने. पायजामे से निकालकर पैंट की दुनिया. अधखाए परिवार के पेट पर एक इंजीनियर खड़ा करने की कोशिश."

संजीव का विवाह बचपन में ही करा दिया गया था. पत्नी और पाँच संतानों का खर्च वहन करने के लिए संजीव पढ़ाई के साथ-साथ 'आयरन स्टील कंपनी' में केमिस्ट की नौकरी करते और ट्यूशन भी पढ़ाते थे. इस ट्यूशन जीवन की पीड़ा संजीव के कहानी में देखने को मिलती हैं. कुछ दिन एलआईसी एजेंट की नौकरी की तो बीमा कंपनी के नाम से एक कहानी लिख दी.

कहने का अर्थ है कि संजीव का साहित्य उनके जीवन संघर्ष की गाथा है. संजीव की पहली रचना 'अपराध' कहानी थी और अपराध के प्रकाशन के साथ ही संजीव ने हिन्दी साहित्य जगत में अपनी पैठ बनाने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी. टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सारिका सर्वभाषा कहानी प्रतियोगिता में अपराध कहानी के लिए इन्हें 'प्रथम पुरस्कार' मिला और तब से अनवरत ढंग से रचनाएँ करने लगे. इनकी प्रमुख कहानी संग्रहों में – 'तीस साल का सफरनामाँ', 'आप यहाँ हैं', 'दुनिया की सबसे हसीन औरत', 'प्रेतमुक्ति', 'ब्लैकहोल' आदि शामिल हैं. संजीव ने डेढ़ सौ से अधिक और दर्जन भर उपन्यास लिखे हैं. इसके अलावा कविता नाटक और यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में भी संजीव अपनी लेखनी चला चुके हैं. संजीव का पहला उपन्यास 'किसनगढ़ ले अहेरी' था जो कि 1984 में प्रकाशित हुआ. बाद में 2014 में 'अहेर' नाम का संशोधित रूप पुनर्प्रकाशित हुआ. इसके अलावा 'सर्कस', 'धार', 'सावधान! नीचे आग है', 'जंगल जहां शुरू होता है', 'सूत्रधार', 'पाँव तले की दूब', 'आकाश-चम्पा', 'रह गई दिशाएँ', 'इसी पार' आदि कुछ प्रमुख उपन्यास हैं. ये अपनी रचना के माध्यम से समाज में घट रही सच्चाईयों को अपने पाठक के सामने ना ही सिर्फ रखते हैं बल्कि उन्हें उन सच्चाईयों को महसूस करने पर बाध्य भी करते हैं. संजीव ऐसी विषयों को अपनी रचना में लाते हैं जो अब तक हाशिए पर थे. संजीव की 'अपराध' कहानी आज़ाद भारत की भ्रष्ट और शोषणकारी व्यवस्था को आईना दिखाती नज़र आती है. 'मरोड़' कहानी के मास्टर दीनानाथ निर्धनता की समस्या से जकड़े हुए हैं, इसके माध्यम से संजीव यही तो दिखाना चाहते है कि समाज को सुविकसित बनाने वाले, उन्हें ऊंचाई पर पहुँचाने वाले मास्टर की अंतर्दशा कितनी गंभीर है. ये हमारे समाज की विडम्बना नहीं तो और क्या हैं. इसके अलावा संजीव के उपन्यासों में भी हमें अनोखे संदर्भ देखने को मिलते हैं. 'किसनगढ़ ले अहेरी' संजीव का पहला उपन्यास है, जिसमें किसन गढ़ के माध्यम से पिछले अंचल में हो रहे शोषण को हमारे सामने रखते हैं. वहीं, 'सावधान! नीचे आग है' में बढ़ते हुए औद्योगीकरण क्षेत्र तथा कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी को हमारे सामने रखते हैं. तो अपने उपन्यास 'सर्कस' में लोककला, लोकमनोरंजन की आड़ में वहाँ काम करने वाली लड़कियों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है कि किस प्रकार से ऊंचे और प्रतिष्ठित पद के लोगों के पास उन लड़कियों का सौदा किया जाता है और उन लड़कियों को कठपुतलियों की तरह प्रयोग किया जाता है. इस उपन्यास को पढ़ने के बाद पाठक के मन में सर्कस से घृणा होना लाज़मी है. संजीव ने अपने एक अन्य उपन्यास, 'जंगल जहां शुरू होता है' में जनजाति जीवन के अलग संघर्ष को उजागर किया है, इसमें थार आदिवासियों की त्रासदी और डाकू समस्या का चित्रण किया है. आज जब विज्ञान इतनी प्रगति कर गई है और हर तरफ विज्ञान का बोलबाला है ऐसे में विज्ञान को विषय बना कर लिखा गया संजीव का उपन्यास, 'रह गई दिशायें इसी पार' में संजीव ने बालक के मन का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है. आज टेस्ट ट्यूब बेबी का दौर है. उस बच्चे की माँ एक कामकाजी महिला है और उसके पास बच्चे के लिए वक़्त भी नहीं है. ऐसे में उसकी नानी उसको जन्म देती है और वह बच्चा फिर समाज में लोगों के सामने उपहास का विषय बन जाता है. संजीव ऐसे रचनाकार हैं जो समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं. संजीव का सबसे नवीनतम उपन्यास 'फाँस' 2015 में प्रकाशित हुआ. संजीव को उनकी रचनाओं के लिए अनेक राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें इन्दु शर्मा अन्तर्राष्ट्रीय कथा सम्मान (लंदन) 2011, भिखारी ठाकुर लोक सम्मान 2003, प्रेमचंद सम्मान 2002, आदि सम्मिलित हैं. संजीव 'हंस' पत्रिका के कार्यकारी का

पद भी कई वर्षों तक संभाल चुके हैं तथा अक्षरपर्व प्रकाशन एवं रेमाधव प्रकाशन के संपादक के रूप में भी कुछ समय तक कार्यरत रहे.

'पहले जीवन की आँख से कहानी को आँकता था, अब कहानी की आँख से जीवन को आँकता हूँ' संजीव का यह कथन उनके समस्त रचना-संसार का सार है. उनकी रचनाएँ उनके जीवन और संघर्ष की प्रतिबिम्ब रही हैं. उन्होंने अपनी रचनाओं में दलित, दमित, पिछड़े, उपेक्षित वर्ग की व्यथा को वाणी प्रदान की है तथा साथ ही एक आंचलिक कथाकार के रूप में रेणु की आंचलिकता की परंपरा को भी आगे बढ़ाने का काम किया है. संजीव साहित्य में भिन्न-भिन्न विषयों के अवगाहनकर्ता हैं. 'सर्कस', 'रह गयी दिशाएँ', 'इसी पार', 'फाँस' उपन्यास के माध्यम से संजीव ने ऐसे-ऐसे अनछुए संदर्भों को अपने साहित्य में स्थान दिया है जो अब तक हिन्दी साहित्य की परंपरा में अछूते रहे हैं. कहना न होगा कि संजीव का व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व एक दूसरे के पूरक हैं. संजीव को देखना हो तो उनकी रचनाओं को देखें, वे साफ नज़र आएंगे.

*तनीषा शर्मा*
*के.का., मुंबई*

# जनसंख्या विस्फोट

तिल रखने की जगह नहीं, संसाधनों से जूझ रहे।
एक खाने की थाली में, दस–दस जन टूट रहे।।
किसी ने कहा बुलेट ट्रेन से अच्छा, कुछ बोगी बढ़ा देते।
कम से कम हर यात्री को, उसकी ट्रेन में तो चढ़ा देते।।
बढ़ाओ तुम कहाँ–कहाँ, क्या–क्या बढ़ाओगे ?
अस्पताल जाओगे तो, वहाँ भी बेड कम पाओगे।
एक सरकारी नौकरी, हजारों की मारा मारी है।
बैंक में घुसोगे तो भीड़, धक्का मुक्की, लाचारी है।।
पढ़ने निकलोगे तो, एक सीट पर हजारों अभ्यर्थी हैं।
श्मशान घाट पर भी लाइन है, जलाने को कई अर्थी हैं।।
अरे मूर्खों, तुम कहाँ पर क्या–क्या बढ़ाओगे ?
जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कब अपनाओगे।।
जब घरों के बोझ से, फसल बोने को मैदान ना बचेंगे।
या इंसान को ही खाकर, जब इंसान ना बचेंगे।।
गर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को देश में ना बसने देते।
अपनी जर जमीन को, घुसपैठियों के हाथ ना बिकने देते।।
तो यकीं मानो, ये कहीं कुछ बढ़ाने की जरूरत ना होती।
हमें अपने ही देश में सुकूँ से, जीने में शामत ना होती।।

*अनूप कुमार वर्मा*
*अमेठी शाखा*

# काले -काले मेघा जब पानी की बूंद गिराते

**काले -काले मेघा, जब पानी की बूंद गिराते,**
**तब वे मुझको मेरे बचपन की याद दिलाते ।**
**याद आते वो साथी संगी,**
**जिनसे मिलने को हम घर से छुप-छुप कर जाते ।।**
**नदी सी बहती धारा में और,**
**समुंदर से लगते रस्तों पर,**
**हम कितना शोर मचाते,**
**काले -काले मेघा, जब पानी की बूंद गिराते...**
**दुनिया की सुध भूलकर**
**हम खूब नाचते-गाते ।**
**नभ से गिरते मोती को**
**हाथों मे लेकर हम कितना सुख पाते**
**काले -काले मेघा जब पानी की बूंद गिराते...**
**जिसे काले मेघ को देख घर में छुपती है दुनिया**
**हम उससे आनंद पाते.**
**काले -काले मेघा जब पानी की बूंद गिराते**
**तब वे मुझको मेरे बचपन की याद दिलाते.**

*गौरव*
*वरुड शाखा, क्षे.का., नागपुर*

# जीवन की कश्ती

ख्वाहिशें कश्ती पर सवार करके
मेहनत की चप्पू चलाये जा
बहते पानी की धारा की ओर
मंजिल अपनी बनाए जा ।
न मिले जो मंजिल, धारा की ओर
धारा के विपरीत ही बहे जा
पर मंजिल अपनी बनाये जा ।
जीवन की कश्ती पर ख़्वाहिशें उतनी ही रख
जितना कश्ती संभाल सके
ख़्वाहिशों से खुशियां ना सही
सफर में मौज किये जा.
तूफ़ान बवंडर तो आएंगे
डर कर लौटने का प्रश्न कहाँ?
थोड़ा दम भर, चप्पू को मजबूत पकड़
डर की आँख से, आँख मिलाये जा
जीवन की कश्ती बलिदान नहीं
संघर्ष और साहस मांगती है
दिल साफ रख और आगे बढ़
उन ख़्वाहिशों को पाये जा ।
डर लगे कभी, अगर डर से
फिर भी निडरता से चुनौतियाँ पार किये जा
चुनौतियाँ हैं, कोई भूत नहीं
अपनी हिम्मत को भी आजमाए जा.
मिल जाए जो मंजिल, तो पीछे मुड़कर देख
वो सागर उन अथाह संघर्षों का...
हृदय के स्पंदनों में उस गति को महसूस कर जायेगा
के मंजिल की अहमियत तुझे रोज याद दिलाएगा.

***भरत परिहार***
*सांसरोद शाखा, बड़ौदा*

# ऐ नशा, हमें बर्बाद न कर

ऐ नशा, हमें बर्बाद न कर, गुजरी रातें भूल याद न कर
पहले ही बर्बाद है हम, अब तू हमें ना शाद न कर
किस्मत का सितम नशा कम हो, ताजा नशा ईजाद न कर
यूँ जुल्म न कर, बेदाद न कर
ऐ नशा, हमें बर्बाद न कर

जिस दिन से मिली तुम, जीने का चैन गया, आराम आ गया
चेहरों से बहारें गुम हुई, आँखों को शाम आ गया
हाथों से खुशी का जाम छूटा, होठों पर खुशी का नाम आया
अधर्मी न बन नाशाद न कर
ऐ नशा, हमें बर्बाद न कर

वो राज गम में नशा, जिसे पा जाए तो खैर नहीं
आँखों से आँसू बहते हैं मौत आ जाए तो खैर नहीं
जालिम है, नशा दुनिया, दिल को भा जाए तो खैर नहीं
है जुल्म, मगर फरियाद न कर
ऐ नशा, हमें बर्बाद न कर

दुनियाँ का नशा देख लिया, तमाशा मुमकिन बेताब सी है
उम्मीद नहीं यहाँ, बस इक बहस सी है
तस्वीर यहाँ इक ख्वाब सी है
दुनियाँ खुशी का नाम नहीं, दुनियाँ में खुशी नायाब सी है
दुनियाँ में खुशी को याद न कर
ऐ नशा, हमें बर्बाद न कर

***रामबीर सिंह***
*गुना शाखा, क्षे.का., ग्वालियर*

# Mother

She knew me even before I was born
She nurtured me for nine months.....
In her womb, so warm !!

Ever since then,
she hears my loud n silent cries,
She reads my every action,
even without sighs !!

Though now an adult,
for her I am a child,
Only she forgives,
when I'm impatient n wild !!

She is sacrifice, patience,
love n care personified,
On every caste n creed,
her status is dignified !!

There is no comparison for this .....
ULTIMATE ALMIGHTY CREATION,

Best above all, is the
MOTHER N CHILD relation !!

***Umesh Pedgaonkar***
*Baner Branch, Pune*

# The Earth is Crying...!

Every morning the sea roars and breaks onto the sea-shore
As if it cries but says nothing as so
Cradling the world and many life forms in it
Unfathomable mysteries there lie beneath
Our mother Earth too cries as we do
Though she cannot shed tears like us
But she does feel the agony and pain
We have polluted Earth time and again
With vast stretches of land to the endless sky
We humans have destroyed it that we cannot deny
A mother in no way will harm her child
She drives all threats away and keeps them aside
Let us not just sleep and keep silent
For our mother is in a lot of pain
Though she gives us food and clothing
And blesses us with the heavenly rain
It is we who have to realize our fault
Many have come and gone all the while
We have to care our Earth and preserve her
So that she replies a "Thank you" and smiles

***Prannoy Roy***
*RO, Siliguri*

# भारतीय परिप्रेक्ष्य में बैंकों में एनपीए प्रबंधन

**अनर्जक परिसंपत्तियां–** अनर्जक परिसंपत्तियां या एनपीए बैंकों के द्वारा दिया गया एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसके मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि तक बकाया हो. बैंक अनर्जक परिसंपत्तियां को अवमानक, संदिग्ध व घाटे की संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करती है.

**अवमानक परिसंपत्ति (Substandard assets)–** कोई भी ऐसी संपत्ति जो 12 महीनों तक अनर्जक परिसंपत्तियां बनी रहें उसे अवमानक संपत्ति कहते हैं.

**संदिग्ध परिसंपत्ति (Doubtful assets)–** कोई भी ऐसी संपत्ति जो 12 महीनों तक अवमानक परिसंपत्ति की श्रेणी में बनी रहे तो उसे संदिग्ध परिसंपत्ति कहते हैं.

**घाटे की परिसंपत्ति (Loss assets)–** जब किसी सम्पत्ति के बारे में RBI या कोई मान्य लेखा परीक्षक यह घोषणा कर दे कि इस संपत्ति की वसूली सम्भव नही है तो उसे घाटे की परिसंपत्ति कहते हैं.

## एनपीए - विस्तृत अध्ययन

कोई व्यावसायिक योजना चाहे वह एक विनिर्माण उद्योग हो, एक व्यापारिक व्यवसाय या एक सेवा उद्यम, परियोजना की तकनीक और आर्थिक अध्ययन के माध्यम से इसे लागू करने के लिए परियोजना की उचित योजना और निष्पादन के माध्यम से एक विस्तृत प्रक्रिया होती है. बुनियादी ढ़ांचा उपलब्ध होने पर उपयोगिताओं, जनशक्ति, रसद और विपणन भी शामिल किए जाते हैं. इसलिए, ऋण की आवश्यकता का आकलन और मूल्यांकन व्यापार उद्यम की वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जनता से जमा स्वीकार करना और उत्पादक उद्देश्यों के लिए उधार देना बैंकों के ये दो प्राथमिक कार्य हैं. चूंकि वे सार्वजनिक धन के संरक्षक हैं, इसलिए जनता के हितों की रक्षा करने के लिए बैंकों की ज़िम्मेदारी सर्वोपरि है.

## उधार (ऋण) देने के बुनियादी सिद्धांत

**उधारकर्ता:** उधारकर्ता का चरित्र, क्षमता और क्रेडिट योग्यता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा पता लगाया जाना चाहिए. इस संबंध में क्रेडिट रेटिंग कंपनियों और बैंक द्वारा उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग उधारकर्ता की पृष्ठभूमि का आकलन करने के लिए एक उपकरण साबित हो सकती है. इसके अलावा कोर प्रबंधन टीम जिस पर उधारकर्ता व्यवसाय के उद्देश्यों के वास्तविक एहसास के लिए निर्भर होने जा रहा है, मूल्यांकन प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

**ऋण का उद्देश्य और व्यवसाय की प्रकृति:** व्यवसाय की प्रकृति ऋण के उद्देश्य को निर्देशित करती है. नकदी उत्पादन के आधार पर समय-समय पर भुगतान ऋण के माध्यम से भूमि, भवन, पौधे, मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियों की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण दिया जाता है. ऋण को एक विशेष अवधि के बाद नवीनीकृत किया जाता हैं जो आम तौर पर वित्त प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष है. इसके अलावा, ऋण को फंड आधारित ऋण और गैर-निधि आधारित ऋण जैसे बैंक गारंटी, क्रेडिट पत्र आदि में भी वर्गीकृत किया जा सकता है. बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा दिए गए ऋण का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिनके लिए उन्हें दिया जाता है. उनका दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है.

**ऋण की राशि:** ऋण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि और उचित प्रकार के ऋण स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता होती है. परियोजना के वित्त पोषण के तहत कोई भी परियोजना पूरी करने में लागत, बढ़ोतरी और देरी हो सकती है जो कि उधारकर्ता की चुकौती और अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता को प्रभावित कर सकती है. इसी प्रकार वित्त पोषण भी अच्छा नहीं है क्योंकि धन का दुरुपयोग किया जा सकता है और उधारकर्ता द्वारा मुख्य गतिविधि की लाभप्रदता को प्रभावित किया जा सकता है.

**ऋण की अवधि:** बैंकों के लिए ऋण की अवधि बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जमाकर्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए बैंकों के तरलता कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो संपत्ति देयता मिलान पर आधारित है. दीर्घकालिक वित्त निधि को अवरुद्ध करता है जहां कामकाजी पूंजी, निधि मांग पर अल्पकालिक होते हैं. दीर्घकालिक वित्त में भी अधिक जोखिम शामिल हैं क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्थिति विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में वित्त अवधि के दौरान बदल सकती है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है. इसलिए, किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यक देखभाल की जानी चाहिए और देयता के प्रति ईमानदार रहना चाहिए.

**सुरक्षा:** प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण स्वीकृत किया जाता है क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से बैंक अपनी देनदारियों को समझने के लिए सुरक्षा की बिक्री का सहारा ले सकते हैं. अधिकतर बैंक बुरे प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हैं और परिणामस्वरूप एनपीए का जन्म होता है. इससे बैंक की क्रेडिट निगरानी में प्रसन्नता गायब और उदासीनता हावी हो जाती है. बैंक की साख गिर जाती है.

**जोखिम आकलन:** जोखिम को 'हानि की संभावना' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो छवि या प्रतिष्ठा को 'वित्तीय हानि' या 'हानि' हो सकती है. किसी भी अन्य वाणिज्यिक संगठन की तरह बैंक भी जोखिम लेने का इरादा रखते हैं जो कि जरूरी भी है, क्योंकि इससे किसी भी व्यवसाय में लाभ निहित होता है. ज्यादा लाभ मतलब साख का बढ़ना. लेकिन उच्च जोखिमों के परिणामस्वरूप उच्च नुकसान भी हो सकता है. हालांकि, बैंक माप और मूल्य जोखिम की पहचान करने के लिए पर्याप्त समझदार हैं और किसी भी स्थिति की देखभाल करने के लिए

उपयुक्त पूंजी बनाए रखते हैं. सामान्य रूप से संदर्भित बैंकिंग व्यवसाय या 'बैंकिंग जोखिम' में प्रमुख जोखिम है–

(i) तरलता जोखिम (ii) ब्याज दर जोखिम (iii) बाजार जोखिम (iv) क्रेडिट या डिफ़ॉल्ट जोखिम (v) परिचालन जोखिम.

शामिल जोखिमों के अध्ययन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एनपीए में परिवर्तित खाते की घटनाओं से बचने के लिए शामिल जोखिमों का पूर्ण विश्लेषण और आकलन करना होता है.

**उद्योग अध्ययन:** इसी तरह के उद्योगों/व्यवसायों का एक तुलनात्मक अध्ययन पिछले प्रदर्शन, वर्तमान बाजार की स्थिति और ऐसे उद्योगों के भविष्य की संभावनाओं को अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा ताकि ऐसे उद्योगों के बारे में बेहतर और व्यावहारिक दृष्टिकोण के अनुमान से ऋण जारी किया जा सके. इसी क्रम में व्यापार लक्ष्यों के अनुरूप इन प्रवृत्तियों का जवाब देने के लिए एक रणनीति विकसित की जा सकती है. व्यापार में गैर–निष्पादित संपत्ति यानि एनपीए बनने और बढ़ने से रोकने के लिए सही दिशा में व्यापार में किए जाने वाले निर्णयों के बारे में विचार किया जाता हैं. ट्रेंड विश्लेषण का उपयोग व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद के लिए निम्न प्रकार से किया जा सकता है.

1. उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां व्यवसाय का प्रदर्शन अच्छा रहा है ताकि यह सफलता को जारी रख सके.
2. उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां व्यवसाय का प्रदर्शन कम रहा है जिसको आधारभूत संरचना में लाकर लाभ कमाया जा सके.
3. निर्णय लेने की क्षमता और सुविधा के लिए मजबूत प्रबंधन.

**उधारकर्ता और उसकी आवश्यकताओं को समझना:** वर्तमान में बैंक और उधारकर्ता के दृष्टिकोण ने उनके बीच एक विभाजन बनाया है जिससे गलतफहमी हो रही है और बैंकिंग सुधारों के कारण पेश किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों ने बैंकों के प्रदर्शन और लाभप्रदता पर अधिक दबाव पैदा किया है. मूल समस्या यह है कि जब बैंक सोचता है कि उधारकर्ता एनपीए बनने के लिए ज़िम्मेदार है, तो दूसरी तरफ उधारकर्ता का मानना है कि बैंक के कई गलत काम उसके खाते के एनपीए बनने के कारण हैं. इस प्रकार संबंधित सोच में एकरूपता नहीं होती है. इस तरह के अलग विचारों का कारण क्या हैं? मूल कारण बैंक और उधारकर्ता के बीच प्रभावी संचार की कमी है. संचार एक रिश्ता बना भी सकता हैं और तोड़ भी सकता है. संचार बैंक और ग्राहक के बीच विश्वास का निर्माण भी करता हैं और विध्वंस भी. अंतिम विश्लेषण में, बैंक को ग्राहकों की आदतों से मेल खाने के लिए अपने ग्राहकों के प्रति अपने दृष्टिकोण को दोबारा बदलना होगा. बैंकर को एक मोहक सेवा के साथ ग्राहक की सेवा करने और प्रतिक्रिया के आधार पर और नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेना पड़ता है. ग्राहक, विशेष रूप से उधारकर्ता अपने वास्तविक दृष्टिकोण में उनकी भूमिका और कर्तव्यों को समझकर बैंकों के साथ सक्रिय और अनुकूल असर डालते हैं.

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एनपीए के प्रबंधन में बिगड़ती प्रवृत्ति में सुधार करने के लिए बैंकों द्वारा सबसे पहला कदम एक कुशल और प्रभावी प्रबंधन प्रणाली और जानकार पेशेवरों का निर्माण करना हैं और आकलन और मूल्यांकन के लिए प्रभावी नियम और कायदे लागू करना है. इसके अलावा, उधारकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं और बाजार भविष्यवाणियों को समझना भी हैं. यदि बैंक मूल्यांकन के इस तरह के अभ्यास करने में विफल रहते हैं तो उधारकर्ताओं के परामर्श से मूल्यांकन किया जा सकता हैं और शुरुआत से ही गैर निष्पादित खातों का निर्माण होने से बचा सकता है.

## एनपीए से बचने के लिए सरकारी संस्थाएं

1. **ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी):** नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट 1991 ने मामलों को सुलझाने के लिए आवश्यक समय को कम करने के लिए विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की सिफारिश की. सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) की स्थापना की गई. 22 डीआरटी और 5 डेब्ट रिकवरी अपीलीय न्यायाधिकरण हैं. यह भारत जैसे देश में हो रही एनपीए की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है.
2. **सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2002:** वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा, पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन का बहुत प्रयोग किया जाता है. यह अधिनियम बैंकों द्वारा डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी करने में सक्षम बनाता है जिन्हें 60 दिनों के भीतर ऋण का भुगतान करना पड़ता है. एक बार नोटिस जारी होने के बाद उधारकर्ता ऋणदाता की सहमति के बिना संपत्ति बेच या निपटान नहीं कर सकता है. सिक्योरिटाइजेशन एक्ट बैंक को कंपनी की परिसंपत्तियों और प्रबंधन के कब्जे को लेने का अधिकार देता है. उधारकर्ता संपत्ति बेचकर या फर्म के प्रबंधन को बदलकर बकाया राशि वसूल सकते हैं. यह अधिनियम एनपीए वसूली करने के लिए और संपत्ति पुनर्निर्माण को भी सक्षम बनाता है.
3. **लोक–अदालतें:** लोक अदालतों को छोटे ऋण की वसूली के लिए उपयुक्त पाया गया है. 2001 में जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार वे लोक–अदालत के माध्यम से एनपीए वसूली का रास्ता अपना सकते हैं. सामान्यतः आम आदमी लोक अदालत जैसी कानूनी प्रक्रिया से बचकर रहने का प्रयास करता है जो कि ऋण की किस्तों को समय पर भुगतान करने को मज़बूर करता है. आरबीआई दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद मात्र कुछ ही दिनों में 40 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था.
4. **समझौता:** समझौता या निपटान योजना एनपीए की वसूली के लिए एक सरल तंत्र प्रदान करती है. इसमें दायर मामलों, अदालतों और डीआरटी (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) के साथ लंबित मामलों को शामिल किया गया है. विलुप्त डिफ़ॉल्ट और धोखाधड़ी के मामलों को इससे बाहर रखा गया था.
5. **क्रेडिट सूचना ब्यूरो:** ऋण को एनपीए में बदलने से रोकने के लिए एक अच्छी सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है. यदि कोई उधारकर्ता एक बैंक के लिए डिफॉल्टर है, तो यह जानकारी सभी बैंकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वे उसे उधार देने से बच सकें. एक क्रेडिट सूचना ब्यूरो डेटा बैंक को बनाए रखने में मदद कर सकता है जिसका मूल्यांकन सभी उधार संस्थानों द्वारा किया जा सकता है.

## क्या कर सकते हैं बैंक और सरकार–

1. बैंक समय–समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला सकते हैं. इन्ही योजनाओं में एनपीए हुए पैसे को वसूलने का कार्य किया जा सकता है.
2. बैंक अधिकारियों को यह अधिकार दिया जाय कि वह ऋणी की स्थिति के अनुसार एनपीए हुए ऋण को एक सीमा तक वसूला सके और बाकी बचे हुए पैसे को सरकार द्वारा वहन किया जाय.
3. ब्याज दर कम करके राशि वसूली जा सकती है.
4. सरकार को चाहिए की वह ऋण को एक नियत सीमा तक ही माफ करे जिससे ऋण लेने वालों के मन में यह भय बना रहे कि ऋण माफ होने की संभावना कम है.
5. सरकार को चाहिए कि वह ऋणियों के मन से यह बात निकाले कि 'चुनाव आने वाले हैं, ऋण माफ हो जाएगा, किस्तें भरने का कोई फायदा नहीं हैं'.
6. बैंक एनपीए वसूली कैंप का नियमित आयोजन करें जिससे वसूली करके भी एनपीए कम किया जा सकता है.

***सुभाष चन्द्र***
*क्षे. का., मदुरै*

# सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए में आयी अचानक बढ़ोत्तरी के कारण

यदि हम तुलना करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्रेडिट वृद्धि में गिरावट की दर निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में काफी ज्यादा है. यह प्रवृत्ति सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र के ऋणों में भी झलकती है. तो प्रश्न यह उठता है कि इसके क्या कारण हैं? क्या क्रेडिट की मांग नहीं है? या इकाइयां निवेश नहीं कर रही हैं? तत्काल निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि कुछ ऐसी बात है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रेडिट प्रवाह पर असर डाल रही है. फिर भी यदि व्यक्तिगत ऋण एवं गृह ऋण की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह निजी क्षेत्र के बैंकों के आस पास है. पूंजी की कमी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता. ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण की कमी का मुख्य कारण मध्यम एवं बड़े उद्योग क्षेत्र के ऋणों में गिरावट है. इसका मुख्य कारण अतीत में दिये गए ऋण के दबावग्रस्त होने का बढ़ता संकट है.

व्यथित या दबावग्रस्त ऋण के मुख्यतः दो स्त्रोत हैं: ऋणी की मौलिक स्थिति अच्छी नहीं है या ऋण वसूली करने की ऋण दाता की क्षमता कमजोर है. वर्तमान संकट के दोनों ही कारण हैं.

## दबावग्रस्त ऋण के स्त्रोत : ऋणी की कमजोर मौलिक स्थिति

वर्तमान के खराब ऋणों में काफी संख्या में ऐसे ऋण हैं जो ऐसे समय में दिये गए जब आर्थिक विकास दर अच्छी थी एवं असीमित संभावनाएं दिखाई दे रही थीं. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा पूंजी की वृद्धि दर तेज थी एवं कई आधारिक संरचना या बुनियादी ढांचों की परियोजनाएं जैसे बिजली संयन्त्रों के कम समय पर एवं बजट के अंदर पूरे हो रहे थे. यही वह समय था जब बैंकों से गलतियाँ हुईं. अतीत के प्रदर्शन को भविष्य में भी निरंतर कायम रहने के अनुमान लगाकर वित्त पोषण किए गए, जिसके कारण परियोजनाओं को प्रमोटर द्वारा कम इक्विटी के बावजूद ज्यादा वित्त पोषण के लिए स्वीकार किया गया. कुछ मामलों में प्रमोटर के 'निवेश बैंक' के द्वारा परियोजना रिपोर्ट जमा किए जाने के बावजूद बिना ड्यू डिलिजेन्स के वित्त पोषण किए गए तथा कुछ मामलों में प्रमोटर को कहा गया कि 'बताएं, कितना वित्त पोषण चाहिए?' यह तर्कहीन अधिकता की ऐतिहासिक घटना, चक्र के एक चरण में पूरे भारतवर्ष में दोहराई गयी.

समस्या यह है कि विकास दर हमेशा वैसी नहीं रहती है जैसा अनुमान लगाया गया हो. मजबूत वैश्विक विकास के वर्षों के बाद आया वैश्विक वित्तीय संकट और उसके बाद मंदी के दिन आए, जिसका असर भारत में भी महसूस किया गया. विभिन्न परियोजनाओं के लिए मजबूत मांग का अनुमान, अंतर्देशीय मांग में गिरावट के साथ धराशायी होने लगा. इसके अतिरिक्त विविध शासन समस्याओं के साथ-साथ जांच के डर से नौकरशाही फैसला काफी धीमा हो गया तथा बुनियादी ढांचों की परियोजनाओं के लिए अनुमति मिलना मुश्किल हो गया. ठप परियोजनाओं की लागत बढ़ती चली गयी तथा ये ब्याज एवं मूल राशि चुकता करने में असमर्थ होते चले गए.

ऐसा नहीं है कि दुराचारी गतिविधियों से ऋणपोषण नहीं हुए. देश की जांच एजेंसियां उन मामलों की तहक़ीक़ात कर रही हैं जहां अवांछित प्रभाव के द्वारा ऋण उपलब्ध कराये गए. वास्तविक धोखाघड़ी के द्वारा फ़ंड को डाइवर्ट करके कंपनी से बाहर ले जाया गया, चालान में अधिक कीमत दिखा कर प्रमोटर के सहायक कंपनी से सामानों का आयात किया गया, संबन्धित शैल कंपनी को निर्यात किया गया और दावा करने पर चूक सामने आयी इत्यादि. आम तौर पर, दुराचारी गतिविधियों के अलावा कई कारक थे जिनके कारण कई वास्तविक प्रतिबद्ध प्रमोटर भी कठिनाइयों से घिर गए.

## दबावग्रस्त ऋण के स्त्रोत : खराब अनुश्रवण एवं संग्रह

सच्चाई यह है कि समझदारी से ऋण पोषण के बावजूद भी ऋण दबावग्रस्त हो सकते हैं, चूक हो सकती है. एक बैंकर, जो यह सोच कर ऋण देता है कि कभी और किसी स्थिति में भी चूक न हो, वह अति रूढ़िवादी है या अति संकुचित विचार का है जिसके फलस्वरूप वह काफी कम परियोजनाओं में वित्तपोषण करेगा तथा इसका असर विकास पर होगा. समझदारी से ऋण पोषण का अर्थ है कि परियोजनाओं के भविष्य का सावधानीपूर्वक अग्रिम मूल्यांकन करना लेकिन इसमें हानि पहुँचती है. तर्कहीन उत्साह एवं दूसरों के द्वारा मूल्यांकन पर अत्यधिक निर्भरता से. मूल्यांकन में कमी को ऋण वितरण के पश्चात सावधानीपूर्वक निगरानी या अनुश्रवण, अच्छे दस्तावेजीकरण, संपार्श्विक प्रबंधन, प्रमोटर की गारंटी इत्यादि के द्वारा दूर किया जा सकता है. दुर्भाग्यवश, कई परियोजनाएं कमजोर अनुश्रवण एवं लागत में बढ़त के चपेटे में आ गयी. संघ वित्त (Consortium finance) में बैंकों ने नेतृत्व बैंक से उपर्युक्त ड्यू डिलिजेन्स की उम्मीद रखी लेकिन यह हमेशा नहीं हो पाया. इसके अतिरिक्त जब ऋण दबावग्रस्त होते गए, निजी बैंकों ने जहां चुस्ती दिखाते हुए अतिरिक्त संपार्श्विक प्रबंधन किया या बाहर निकालने का विकल्प देखा वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नए एवं अतिरिक्त ऋण के द्वारा परियोजनाओं को जीवित करने की कोशिश करते रहे. प्रमोटर चतुराई से नयी इक्विटी लाना बंद कर दिये और कभी-कभी परियोजनाओं को पटरी पर लाने की कोशिश भी छोड़ दिये.

सरफेसीया (sarfaesia) कानून होने के बावजूद वसूली की प्रक्रिया लंबी, जटिल एवं महंगी होने लगी. यह जानते हुए कि बैंकों के द्वारा वसूली करना बहुत मुश्किल है, कुछ प्रमोटर्स परियोजनाओं के परिमाण को बदल कर दूसरे यूनिट के नाम पर अतिरिक्त ऋण ले लेते थे जबकि पहली यूनिट से ऋण चुकता करना मुश्किल था.

बेशक, कुछ बेशर्म प्रमोटर्स निधि को परियोजनाओं से बाहर ले जाते रहे, कभी ऋण को बढ़ाकर, कभी तुलन पत्र की समस्याओं को बढ़ाकर. अप्रभावी ऋण वसूली प्रक्रिया प्रमोटर्स को जबरदस्त शक्ति प्रदान करता है ऋण दाता के ऊपर मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ने में. वे न केवल एक बैंक को दूसरे बैंक के विरोध में प्रयोग करते हैं बल्कि बैंक द्वारा ज्यादा ऋण उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में पैसे न लौटाने की धमकी भी दे डालते हैं, खासकर तब जब बैंक को लगता है कि खाता एनपीए हो जाएगा. कभी–कभी प्रमोटर काफी कम पैसे में ओटीएस का आग्रह कर बैंक की अप्रभावी ऋण वसूली प्रक्रिया का मजा लेते हैं. प्रभावी रूप से, ऐसी प्रणाली में ऋण ने एक अंतर्निहित इक्विटी का रूप ले लिया है जहां कठोर प्रमोटर उल्टे समय का सीधा मजा लेते हैं और बैंकों को हानि एवं नुकसान अवशोषित करने के लिए मजबूर करते हैं.

## बैंक के तुलन पत्र [Balance sheet] पर संकट :

प्रारम्भिक संकट के तीन प्रमुख नियम हैं :

i) व्यवहार्यता (viability) बकाया ऋण पर नहीं बल्कि आर्थिक मूल्य पर निर्भर करती है :

बकाया ऋण को वहाँ तक कम किए जाने की जरूरत है जहां तक व्यवहार्यता (viability) होती है. बदले परिवेश में मांग कम होने के कारण परियोजना का नकदी प्रवाह अनुमान से काफी कम हो सकता है. परियोजना पूर्ण होने पर इसका आर्थिक मूल्य होता है क्योंकि तब कार्यशील नकदी प्रवाह सकारात्मक होता है. जब ऋण के ऊपर लगने वाला ब्याज, सकारात्मक कार्यशील नकदी प्रवाह से कम होता है तब ऋण को कम करने की जरूरत होती है. प्रमोटर को जब अनुमान होता है कि वह नकदी प्रवाह से ब्याज नहीं चुका सकता है तो उसका परियोजना से लगाव कम होता चला जाता है. अंततः निरंतर अनदेखी होने से नकदी प्रवाह बंद हो जाता है और आस्ति का मूल्य तीव्र गति से कम होता जाता है.

ii) व्यवहार्य (viable) परियोजनाएं पूरी की जानी चाहिए भले ही अतिरिक्त कोष की जरूरत हो: ठप परियोजना से किसी का भला नहीं होता है. यदि कुछ अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराने से परियोजना पूरी होती है, खास कर तब जब प्रमोटर के पास पैसे न हों, तो ऐसा करने में भलाई है. अतिरिक्त ऋण सकारात्मक कार्यशील नकदी प्रवाह कर सकता है जिससे पूरा नहीं तो कुछ को चुकाया जा सकता है.

iii) नकदी प्रवाह एवं लोन चुकता करने के अविश्वसनीय आश्वासन की वजह से अच्छे निधि को खराब निधि के ऊपर नहीं लगाना चहिये :

यह बिन्दु संख्या (ii) के विपरीत है. यदि परियोजना व्यवहार्य (viable) नहीं है तो आकार दुगुना करने से लाभ नहीं हो सकते. वे प्रमोटर्स जिन्होंने जरूरत से ज्यादा ऋण ले रखे हैं वो अक्सर परियोजना के आकार को बढ़ाने का प्रस्ताव देते हैं जिससे बैंक का पहले का बकाया और नए लोन का बकाया चुकता करने की क्षमता हो सके. यदि अक्षम एवं अविश्वसनीय प्रोमोटर हैं, तो परियोजना का आकार बदलने से भी परिणाम एक जैसे ही आएंगे.

**पुनर्संरचना पर आस्तियों की स्थिति:** विभिन्न बैंकों द्वारा अव्यवहार्य (non–viable) परियोजना अथवा व्यथित या दबावग्रस्त ऋण को पुनर्संरचना (restructuring) करके एनपीए होने से बचाया जा रहा था. 1 अप्रैल, 2015 से पुनर्संरचना (restructuring) करके एनपीए से खातों को बचाने के औज़ार बैंकों से वापस ले लिए गए. इस प्रस्तावना के बाद, पुनर्संरचना (restructuring) करके भी आस्तियाँ एनपीए होने लगीं. बैंकों द्वारा खराब या दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्संरचना (restructuring) करके एनपीए होने से बचाने की प्रवृति खत्म हो गयी जिसके कारण भी छुपाए हुए एनपीए, वास्तविक एनपीए के रूप में बाहर आने लगे.

(₹ करोड़ में)

| | मार्च–2015 | मार्च–2016 | मार्च–2017 | मार्च–2018 |
|---|---|---|---|---|
| Std. restructured accounts (o/s) | 13658 | 8572 | 5696 | 3736 |
| Gross NPA | 13031 | 24171 | 33712 | 49370 |
| Gross NPA (%) | 4.96 | 8.70 | 11.17 | 15.73 |

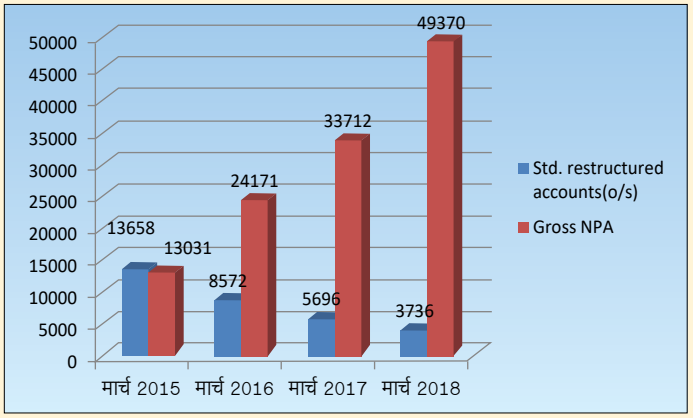


*Figure 2:* ***यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एन पी ए एवं पुनर्संरचित निष्पादित आस्तियों की तुलना***

उपर्युक्त सारणी से यह साफ परिलछित होता है कि 1 अप्रैल, 2015 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाये गए आस्ति वर्गीकरण के बदलाव से मार्च–2016 के आंकड़ों पर स्पष्ट असर पड़ा है. पुनर्संरचित निष्पादित आस्तियां (restructured standard assets) कम होने लगीं और वास्तविक एनपीए तेजी से बढ़ने लगे.

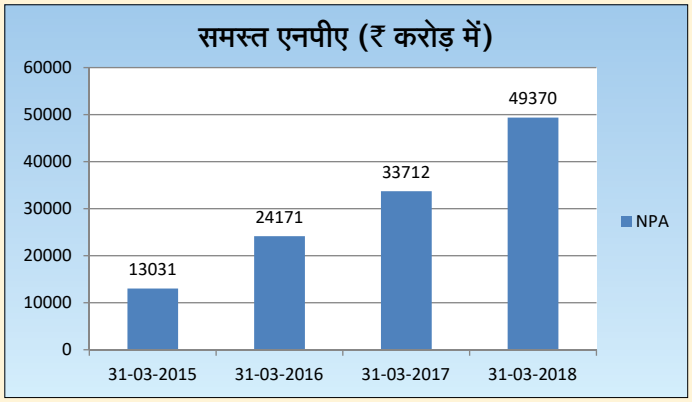


*Figure 1:* ***यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एनपीए का बढ़ता ग्राफ***

***पुष्कर कुमार सिन्हा***
*स्टा. प्र. के., भुवनेश्वर*

# शिखर की ओर

## उच्च कार्यपालक वेतनमान VII में पदोन्नति पर हार्दिक बधाई !!

**श्री पी. एस. राजन**
महाप्रबंधक

**श्री एच.सी. मित्तल**
महाप्रबंधक

## उच्च कार्यपालक वेतनमान VI में पदोन्नति पर हार्दिक बधाई !!

**श्री अशोक कुमार दाश**
उप महाप्रबंधक

**श्री राजेश कुमार**
उप महाप्रबंधक

**श्री आलोक कुमार**
उप महाप्रबंधक

**श्री रूप लाल मीणा**
उप महाप्रबंधक

*हम आपके नेतृत्व में बैंक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं.*

---

# हमें गर्व हैं

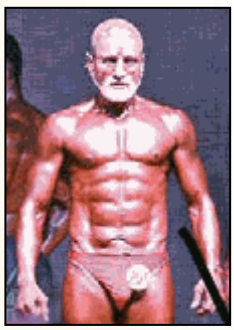

हमारी राजौरी गार्डन शाखा, दिल्ली के प्रबंधक **श्री अशोक सिद्धू** ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में "मिस्टर दिल्ली 2018" का खिताब जीता है. गौरतलब है कि जिस उम्र में लोग रिटायर होते हैं, उस उम्र में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में कदम रखते हुए उन्होंने यह खिताब हासिल किया है. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वे अब मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया और मिस्टर वर्ल्ड खिताब हासिल करने हेतु प्रयासरत हैं.

हमारी सदर बाज़ार शाखा, दिल्ली की स्टाफ श्रीमती इन्द्रा ने ग्राहक द्वारा भूलवश अधिक जमा की हुई कुल ₹ 50,000/– की राशि ग्राहक को लौटा दी.

नेशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, इंडिया द्वारा वर्ष 2017 हेतु सबसे अच्छे विकलांग कर्मचारी (कम दृष्टि) के लिए दिया जानेवाला 'द ट्वेन्टीफ़र्स्ट मिसेस पीलू दोराब खंबाटा मेमोरियल अवार्ड' हमारे डी.आई.टी., मुंबई

के प्रबन्धक **श्री प्रशांत नाईक** को दिया गया. दिनांक 14.03.2018 को आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के करकमलों से यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया.

हमारी कुर्डूवाड़ी शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्हापुर के शाखा प्रबन्धक **श्री बलीराम इबितबार** को दिनांक 02.05.2018 को महाराष्ट्र दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष, श्री हनुमंत पाटोले जी के करकमलों से 'कार्यक्षम अधिकारी – 2018' पुरस्कार प्रदान किया गया.

हमारी जगतपुरा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के दफ्तरी **श्री दिलीप कुमार खटनानी** ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए शाखा परिसर में ग्राहक द्वारा भूलवश छूटी हुई कुल ₹ 50,000/– की राशि ग्राहक को लौटा दी.

# बधाई

**श्री ऋषभ,** सुपुत्र श्री विमलेश जैन, उप महाप्रबंधक, ग्रामीण एवं कृषि कारोबार विभाग, कें.का., मुंबई ने आई.आई.एम., नागपुर के वर्ष 2017–18 के एम.बी.ए. प्रोग्राम में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया. आई.आई.एम., नागपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह में यह गोल्ड मेडल श्री सुभाष चन्द्रा, सांसद, राज्य सभा एवं चेयरमैन, ऐसल एवं जी ग्रुप द्वारा उन्हें प्रदान किया गया. उल्लेखनीय है कि श्री ऋषभ जैन ने सी.ए. की परीक्षा भी प्रथम बार में उत्तीर्ण कर सी.पी.टी. में भी ऑल इंडिया पांचवी रैंक हासिल की थी.

**कुमार धीरज,** सुपुत्र श्री के. रामलिंगेश्वर राव, शाखा प्रबन्धक, गवर्नरपेट शाखा, विजयवाड़ा, (केन्द्रीय विद्यालय की सातवीं कक्षा का विद्यार्थी), को भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए विज्ञान प्रोजेक्ट तथा ज़िला शिक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित ज़िला स्तरीय प्रदर्शनी में उनकी सहभागिता के लिए नकद पुरस्कार राशि ₹ 10,000/– के "इंस्पायर अवार्ड" हेतु चयन किया गया है.

**कुमारी ए. एल. भवानी,** सुपुत्री श्री ए.आर. प्रसाद, वरिष्ठ प्रबन्धक, नोडल क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एज्यूकेशन, आंध्र प्रदेश की जूनियर इंटरमीडिएट परीक्षा 10 सीजीपीए अंकों के साथ उत्तीर्ण की.

**कुमारी एम. साई शरण्या,** सुपुत्री श्री मारें रवि, मुख्य प्रबन्धक, नोक्षेका, विजयवाड़ा ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एज्युकेशन, आंध्र प्रदेश के जूनियर इंटरमीडिएट परीक्षा 9.8 सीजीपीए अंकों के साथ उत्तीर्ण की.

**कुमारी सी. अनूषा,** सुपुत्री श्री सी. चिट्टि बाबू, शाखा प्रबन्धक, उप्पलपाडु शाखा ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एज्युकेशन, आंध्र प्रदेश के सीनियर इंटरमीडिएट परीक्षा में 1000 में से 948 अंक प्राप्त किये.

**कुमारी एन.बी.एस. गीतिका,** सुपुत्री श्रीमती एन.वी.एन.आर. अन्नपूर्णा, नोडल क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एज्यूकेशन, आंध्र प्रदेश की सीनियर इंटरमिडिएट परीक्षा में 984 अंक प्राप्त किये. साथ ही तेलुगू नववर्ष 'उगादी' के अवसर पर आंध्र सोशल एण्ड कल्चरल असोसिएशन, चेन्नै द्वारा चेन्नै में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री सलूरी वासू राव के करकमलों से अस्का एक्सेलेंस अवार्ड (ASCA Excellence Award)प्राप्त करती हुयी सुश्री गीतिका.

**कुमारी शफ़ीन,** सुपुत्री सुश्री शमा सलीम शिकलगर, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), केंद्रीय कार्यालय, मुंबई ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में 94.6% अंक अर्जित किए.

**कुमारी पल्लवी,** सुपुत्री श्री सुनील कुमार लोहिया, मुख्य प्रबन्धक, वारछारोड शाखा, सूरत ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा 94.40% अंकों के साथ उत्तीर्ण की.

**कुमार शांतनु,** सुपुत्र सुश्री माधवी साल्वी, एसडब्ल्यूओ–ए, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई (पश्चिम) ने मुंबई बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में 94.60% अंक अर्जित किए.

**कुमारी शर्वरी,** सुपुत्री श्री संतोष शिर्के, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई (पश्चिम) ने मुंबई बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में 92.60% अंक अर्जित किए.

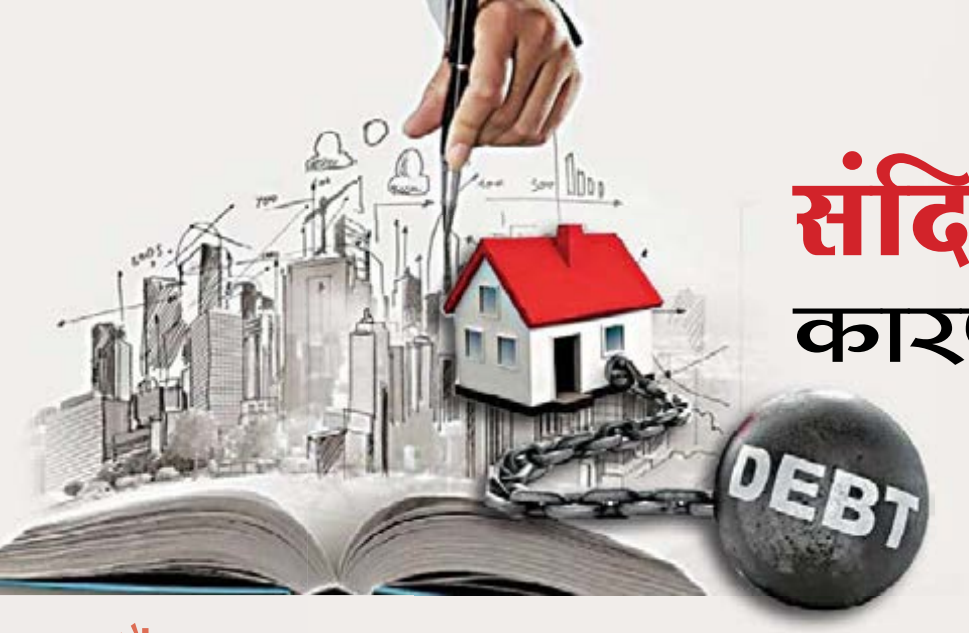


# संदिग्ध बैंक – कारण और उपाय

बैंक – अर्थव्यवस्था का वो अंग है जिसके बिना हम अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते. किसी भी देश की जनता सबसे ज्यादा विश्वास जिस संस्था पर करती है वह है बैंक. इसी कारण जनता अपने मेहनत से कमाई पूँजी को बैंक में जमा करती है और बैंक इस पूँजी का इस्तेमाल ऋण देने में करता है. इस ऋण से होने वाली ब्याज की आय से जमा किये धन पर बैंक ब्याज देता है और उसके उपरांत अपने परिचालन व्यय और टैक्स इत्यादि को निकालने के बाद शुद्ध लाभ कमाता है.

अब सोचिये कि बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण के बड़े भाग को लोग समय पर नहीं चुकायेंगे तो वह अनर्जक अस्तियों में परिवर्तित हो जाएगा और बैंक की आय कम होगी जिसके उपरांत जमाकर्ताओं को ब्याज देने और फंसे कर्ज पर प्रावधान करने के बाद बैंक घाटे में चला जाएगा. जब यह स्थिति आती है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? अगर अनर्जक आस्तियां बढती हैं तो संदिग्ध बैंक की क्या भूमिका है? अपने अनर्जक आस्तियों को संदिग्ध बैंक में हस्तांतरित करना क्यों महत्वपूर्ण है?

दरअसल, जब बैंक की अनर्जक आस्तियां बढ़ती हैं तो इससे होने वाला नुकसान सीधा–सीधा बैंक की तुलन पत्र में प्रदर्शित होता है और निवेशक तुलन पत्र के विभिन्न मापदंडों को देखकर ही बैंक में अपना निवेश करते हैं, अगर बैंकों में निवेश नहीं होगा तो पूँजी जुटाना मुश्किल होगा और बैंक बासेल तीन के मापदंडों को पूरा नहीं कर पायेगा. दूसरा, जब बैंक के पास पूँजी कम होगी तो वह नए ऋण भी प्रदान नहीं कर पायेगा क्योंकि हर प्रकार के ऋण के विरुद्ध बैंक को एक निश्चित मात्रा में पूँजी रखनी होती है. यहीं पर भूमिका आती है संदिग्ध बैंक की. बैंक अपने अनर्जक आस्तियों को संदिग्ध बैंक में हस्तांतरित करके अपनी तुलन पत्र को साफ़ करते हैं, जिससे निवेशकों को एक सकारात्मक और पारदर्शी स्थिति का पता चलता है और वे बैंकों में निवेश करने पर विश्वास करते हैं. इससे बैंकों को पूँजी जुटाने में आसानी होती है. दूसरा, जब अनर्जक आस्तियां संदिग्ध बैंक में हस्तांतरित हो जाती हैं तो बैंकों के कर्मचारियों का जो समय अनर्जक आस्तियों के रख रखाव या उसको वसूलने में जाता है वही समय उपयोगी कार्यों में लगेगा और बैंक मुनाफे की ओर अग्रसर होगा.

## संदिग्ध बैंक के प्रकार :

1. **तुलन पत्र पर गारंटी (On Balance Sheet Guarantee):** इसमें बैंक अपने जोखिम प्रदत्त आस्तियों के कुछ भाग को सरकार की गारंटी द्वारा सुरक्षित करते हैं. यह मॉडल लागू करने में आसान है परन्तु निवेशकों के लिए इसे समझना जटिल है.

2. **आंतरिक पुनर्गठन (Internal Restructuring):** इस मॉडल में बैंक अपनी ही आंतरिक इकाई का गठन करता है जिसमें विशेष रुप से अनर्जक आस्तियों को हस्तांतरित किया जाता है. इस मॉडल में निवेशकों को ज्यादा पारदर्शिता नजर आती है परन्तु जोखिम बैंक के पास बना रहता है.

3. **विशेष प्रायोजित संस्था (Special Purpose Entity):** इस मॉडल में सरकार की भूमिका अहम रहती है, एक ऐसी संस्था बनायी जाती है जिसकी पूरी या ज्यादातर हिस्सेदारी सरकार की होती है. इसमें सभी बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों को इस विशेष संस्था में हस्तांतरित कर देते हैं.

4. **संदिग्ध बैंक उपोत्पाद (Bad Bank-Spin-off) :** इस मॉडल में बैंक अपना ही एक स्वतंत्र बैंक बनाता है, जिसमें अनर्जक आस्तियों को हस्तांतरित किया जाता है. यह पूरी तरह से जोखिम आस्तियों को प्राथमिक बैंक से अलग करता है.

## संदिग्ध बैंक के कुछ उदाहरण :

इस तरह का पहला कदम 1988 में अमेरिका के मेलन बैंक द्वारा उठाया गया और मेलन बैंक ने अपना एक अलग संदिग्ध बैंक बनाया जिसका नाम था ग्रांट स्ट्रीट नेशनल बैंक. ग्रांट स्ट्रीट नेशनल बैंक ने करीब एक अरब डॉलर के अनर्जक आस्तियों की खरीद को वित्त पोषित करने के लिए उन्हें अंकित मूल्य के 57 प्रतिशत मूल्य पर प्रिफर्ड शेयर के रुप में जारी किया और फिर धीरे–धीरे व्यक्तिगत ऋण की तरह वसूल किया. ग्रांट स्ट्रीट नेशनल बैंक के निवेशकों ने अच्छा मुनाफा कमाया और इसका उद्देश्य पूरा होने के बाद 1995 में इसे विघटित कर दिया गया.

वर्ष 1992 में स्वीडन के बैंकिग संकट के समय दो संदिग्ध बैंकों को स्थापित किया गया जिनका नाम था रेत्रिवा और सेकुरम. इन दोनों ही बैंकों ने सकारात्मक परिणाम दिए और संदिग्ध बैंक की धारणा को बल प्रदान किया.

वर्ष 2008 का सब प्राइम संकट जिसने अमेरिका सहित पूरे विश्व पर अपना असर दिखाया और कई बैंक इसमें पूरी तरह बर्बाद हो गये, इस वक्त भी संदिग्ध बैंकों ने अपनी भूमिका निभाई. सिटी ग्रुप और बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने–अपने संदिग्ध बैंक बनाये और अपने उच्च जोखिम वाले अनर्जक आस्तियों को हस्तांतरित किया.

इसी तरह समय–समय पर अन्य देशों जैसे कि फ्रांस, फिनलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, बाल्टिक, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल आदि ने संदिग्ध बैंकों की स्थापना करके अपने देश के बैंकों को संकट की स्थिति से उबरने में मदद की.

उपरोक्त कुछ उदाहरण यह साबित करते हैं कि संदिग्ध बैंक बैंकिंग संकट के समय अपनी भूमिका निभाते हैं. अपनी उच्च जोखिम आस्तियों को संदिग्ध बैंकों को हस्तांतरित कर मूल बैंक अपने जोखिम को अलग करते हैं और व्यापार बढ़ाने की तरफ ध्यान लगाते हैं तथा संदिग्ध बैंक उच्च जोखिम आस्तियों का प्रबंधन करने में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं.

संदिग्ध बैंक ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कि कोई जेल/सुधार गृह करती है, हम लोग समाज में रहते हैं और इस समाज में ही, कुछ लोग गलत दिशा में चले जाते हैं और असामायिक कार्य करने लगते हैं, इनको सुधारने के लिए ही जेल या सुधार गृह की आवश्यकता पड़ती है जहाँ इन्हें अलग तरीके के व्यवहार द्वारा ठीक किया जाता है. बैंकों में भी हर प्रकार के ऋण होते हैं और जब इनमें से कुछ खराब हो जाएँ तो संदिग्ध बैंक इन अनर्जक आस्तियों को एक अलग व्यवहार से ठीक करने की कोशिश करता है. भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में इस समय सकल एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है और मार्च 2018 के परिणाम जारी होने के बाद सभी बैंकों का एनपीए नौ लाख करोड़ के पार जाने की संभावना हैं, ऐसे में संदिग्ध बैंक की मांग भारत में जोर पकड़ रही है. वर्ष 2017 में सरकार संदिग्ध बैंक स्थापित करने का विचार कर रही थी परंतु फिलहाल इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है. सरकार को चाहिए कि संदिग्ध बैंक की स्थापना करे और एनपीए के बढ़ते संकट से उबरने में बैंकों की सहायता करे.

*शैलेन्द्र डबराल*
*खोपोली शाखा*

# The Process and Challenges of IBC 2016 – A Cursory Glance

Insolvency implies the inability of a person or a body corporate to pay their debts or dues when it becomes payable. Bankruptcy means when a person is declared incapable of paying the dues when remains payable. The problem in Indian economy is in the area of corporate and individual insolvency. When insolvency covers all types of debts problem, bankruptcy is related to individual - be in a business or otherwise but he is declared to be bankrupt. Bankruptcy is a state of affairs of an individual declared by a court of competent jurisdiction because he is insolvent. In other words, insolvency is a situation of an entity of not having enough cash to meet its obligation or to pay it's debts becoming due for payment. In case of bankruptcy, a person declares himself as an insolvent and approaches the court to be declared as bankrupt – the Court, thereby, liquidates the personal assets of the insolvent and distributes among his creditors.

The basic legal hurdle in our country was not having a compiled and complete Law of Insolvency and Bankruptcy - thus Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 came as a greater economic reform agenda to expedite insolvency proceedings. It's an innovation in Insolvency Laws to address honest failures, provides freedom to exit and contributes to overall economic growth – hence a great game changer.

As regards IBC laws, primarily we find terminology like bankruptcy/insolvency/liquidation and dissolution. Dissolution and liquidation are much closed to incorporated entity.

The test of insolvency is an asset test because a person or entity remains unable to meet his/its liability from the realization of his/its entire assets i.e. the assets are not sufficient to discharge the liability. The bankruptcy is a cash test i.e. the liquidity position is not sufficient to meet the demand of a creditor. Under IBC 2016, the insolvency is used for corporate and bankruptcy is used for individual and partnership firm.

The IBC is a major transformation because it's a shifting of emphasis from Debtors in possession to Creditors in control. It helps an efficient revival mechanism and initiated only when there is a default. The type of default in a Resolution process is initiated by the Financial Creditors, Operational Creditors and Corporate Applicants.

It facilitates a time bound insolvency resolution of a corporate entity or individual. It helps protecting the viable business and aims uplifting the economic resources through a liquidation process to prevent depletion. The creditors do not suffer and the promoters are prevented to siphon away the assets. Besides resolution, the right of the creditors improves the business environment and investors' confidence; an effective credit market and entrepreneurship development that encourages ultimate higher economic growth and development.

The code has an innovation i.e. creation of a new set-up of professionals called Insolvency Professional (IP). The IP conducts the entire regulating process. The establishment of Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) is the regulating body who is having oversight on the IRPs. IBBI contributes towards capacity building of Insolvency Professionals and administers their code of conduct and discipline.

The IBC code facilitates and empowers creditors i.e. a financial creditor or an operational creditor (Non financial firm or an employee, workman...) to initiate a resolution process wherein the management of the firm is shifted from the existing promoter to keep the enterprise going. Such power is vested with the Committee of the Creditors (CoC).

The IBC overall envisages an efficient adjudicating process that reduces the time period of recovery and prevents destruction of value, provides a robust data base through Information Utilities (IUs) for the use of information and operation of resolution professionals.

Above all, IBC brings in a paradigm shift in the law and practices on the part of the business enterprises those who are debtors, the buyers of goods and services including the State, Central, public authority, Creditors and other Lender Banks, FIs and Investors and most prominently the judicial system.

Recently, banks have tasted the success of IBC 2016 through the resolution of M/S Bhushan Steel & Electrosteel Steels Ltd. There is a huge amount of NPAs waiting in the queue for resolution. Though the law provides effective mechanism, it needs a re-inventing of cross border insolvency process. Regulating corporate insolvency and financial distress involving company having assets of creditors in more than one country is still at a distance. Section 234 and 235 of IBC says that the Centre is empowered to enter into agreement with foreign Govt. to enforce the provisions of IBC on defaulters who stay abroad, but such attempt is yet to take place. Needful process or implementation of cross border insolvency in India is yet to have an effective step to meet the recovery proceeding hassle free.

Above all, it's an improvement in the rights of Lenders/Creditors and more specifically unsecured Creditors. As a revolutionary step it will help to improve credit culture of Banks/FIs and reduce cost of credit, increase the health of business enterprises, developing a Corporate Bond Market and enriching investors' confidence…

***P. C. Panigrahi***
*Financial Inclusion Dept. C.O.*

# वित्तीय संकट की शीघ्र पहचान

**वित्तीय संकट से आशय ऐसी अवस्थाओं के उत्पन्न होने से है जिसमें वित्तीय आस्तियाँ अपना मूल्य खो देती हैं. यह एक ऐसी अवस्था है, जब मुद्रा की आपूर्ति उसकी मांग से प्रतिस्थापित कर दी जाती है. इसका आशय है कि उपलब्ध मुद्रा की तरलता बैंकों से लगातार निकासी द्वारा अवशोषित हो जाती है.**

वित्तीय संकट सीधे-सीधे बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावित करता है. यह बहुधा उस अफरा-तफरी या संत्रास से जुड़ा होता है, जिसमें निवेशकर्ता अपने निवेश की और खाताधारक अपने धन की निकासी बैंकों से इस आशंका से करने लगते हैं कि यदि उसे रहने दिया गया तो उनके उन आस्तियों का मूल्य या तो प्राप्त नहीं होगा और यदि हुआ तो अल्प मूल्य पर. इससे बैंकों पर या तो विनिवेशों को बेचने का या फिर खुद के डूब जाने का असामान्य दबाव आ जाता है.

वित्तीय संकट को यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके अवनति पर जाने और आर्थिक मंदी के शुरू होने का खतरा होता है. आर्थिक मंदी सबसे पहले निर्माण क्षेत्र पर असर डालती है. इसके बाद उत्पादन क्षेत्र पर असर पड़ने से नौकरियों में छंटनी होने से वित्तीय संकट को और बदतर बना देती है. अधिक कंपनियां और लोग बैंक लोन के मामले में डिफॉल्ट करने लगते हैं. इसके बाद बैंक कर्ज देने में आनाकानी करने लगते हैं जिससे उत्पादन और रोजगार पर असर पड़ने लगता है.

पिछली सदी में दुनिया भर के देशों ने कई एक भयावह वित्तीय संकटों को देखा और भोगा है. वर्तमान सदी में 2007 का वित्तीय संकट एक ऐसा ही संकट है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलनिधि की कमी से पैदा हुआ. यह कमी उस दौरान अमेरिका में उफान पर पहुँचने वाले आवास ऋण से संबन्धित अचल सम्पदा के मूल्यों में अचानक गिरावट का कारक बना. इसके फलस्वरूप विश्व स्तर पर कई बड़ी वित्तीय संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ या उनका पतन हुआ और दुनियाभर के शेयर बाजारों में गिरावट आई. कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह 1930 दशक की महामंदी के बाद का सबसे खराब वित्तीय संकट है.

किसी बैंक में वित्तीय जोखिम वह संभावना है, जो किसी प्रत्याशित या अप्रत्याशित घटना के कारण उस बैंक की पूँजी और आमदनी पर प्रत्यक्ष हानि तथा व्यवसाय संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में आती है. स्पष्ट है कि बैंकों में वित्तीय जोखिम की शीघ्र पहचान अत्यंत आवश्यक है, अपरिहार्य है ताकि उन्हें संभावित हानि से बचाया जा सके. पर प्रश्न है कि इसकी पहचान किस प्रकार की जाय?

अमेरिका के 2007 के वित्तीय संकट से सीख लेना आवश्यक है. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल कमेटी (बीसीबीएस) द्वारा जारी सुझाव जारी किये गए. बासेल समिति बैंकिंग नियमों एवं नियंत्रणों से सम्बन्धित सुझाव और अनुशंसा देती है. ये सुझाव बैंकों में अंतर्निहित जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, अनुश्रवण तथा रोकथाम को रेखांकित करते हैं. इनमें सबसे प्रमुख जोखिम अग्रिम से जुड़ी है. अन्य जोखिम परिचालन और बाजार से जुड़ी हुई है.

बासेल III मानकों को 3 दिसंबर, 2010 में जारी किया गया था और यह बासेल समझौते की शृंखला का तीसरा चरण है. बासेल I (1988) और बासेल II (2005) इसके पूर्व संस्करण थे लेकिन कम

कठोर थे. बासेल III सुधार उपायों का एक व्यापक सेट है जिसे बैंकिंग क्षेत्र में विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर तैयार किया गया है. यह वित्तीय एवं आर्थिक तनाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता और जोखिम प्रबंधन में सुधार एवं बैंक की पारदर्शिता को मजबूत बनाना चाहता है. इसमें पूंजी की बेहतर गुणवत्ता और पूंजी संरक्षण बफर पर विशेष बल दिया गया है.

स्वाभाविक रूप से किसी बैंक की माली हालत को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है, उसकी आस्ति गुणवत्ता (एसेट क्वालिटी). यह गुणवत्ता इस बात की व्याख्या करती है कि मोटे तौर पर किसी बैंक के व्यवस्था का प्रदर्शन कैसा है. इसका सीधा सा अर्थ है कि आस्ति गुणवत्ता में आई किसी भी प्रकार की गिरावट से उच्च गैर निष्पादक आस्तियों की मात्रा बढ़ जाती है. यह न केवल वित्तीय संस्था की परिचालन क्षमता को प्रभावित करती है, वरन उसके संसाधनों के रिसाइक्लिंग को बाधित करती है.

अपवादों को छोड़कर, कोई भी ऋण खाता रातों-रात खराब नहीं होता. खराब होने से पहले वह इस संबंध में पर्याप्त संकेत देता है. एक सजग बैंकर इन आरंभिक संकेतों पर ध्यान देकर तथा उनका विश्लेषण कर उनसे संबन्धित खाते को ठीक करने के उपाय समय रहते ढूंढ सकता है. ये संकेत बैंक के भीतर रहकर या फिर बैंक के बाहर जाकर नोटिस किए जा सकते हैं.

उदाहरण के लिए साख स्वीकृति के शर्तों की पूर्ण अनुपालना न करना, ऋण का मार्जिन अंश मिलाने के लिए बिना योजना के उधार लेना, लेटर ऑफ क्रेडिट की समय से सुपुर्दगी न होना, वित्तीय कारणों से चेकों का बिना क्लियरिंग लौटना, स्टॉक स्टेटमेंट/बुकडेट स्टेटमेंट व अन्य आवधिक विवरणियों का देरी से प्रस्तुत करना या प्रस्तुत न करना, ब्याज और किश्त का भुगतान समय से न होना, नकद साख खाते का अपने उच्चतम सीमा में लगातार उपयोग किया जाना, बिल्स खरीद खाते में लंबे समय तक बिलों का पड़े रहना, खाते में अपेक्षित संव्यवहार न होना या फिर स्टॉक स्टेटमेंट में अनपेड स्टॉक न दिखाने जैसे संकेत बैंक के भीतर प्राप्त होते हैं.

जबकि प्रोजेक्ट लागू करने में देरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से मशीनरी न लगाना या अस्तरीय मशीनरी लगाना, प्लांट व मशीनरी में बार-बार होने वाली टूट-फूट, व्यवसाय का बिना प्लानिंग के विस्तार करना, प्रबंधन में हठात या बार-बार किए जाने वाले परिवर्तन, एक या दो-चार क्रेताओं पर निर्भरता, क्षमता से कम उत्पादन, बैंक को सूचित किये बिना प्रोजेक्ट से हटकर बड़े चीजों का उत्पादन/खरीद, बिक्री में लगातार गिरावट, बने/खरीदे माल का बिना बिके पड़ा रहना, कार्यशील पूंजी का उपयोग पूंजीगत व्यय में करना, व्यापार के बहियों का उचित रखरखाव न करना, श्रमिक समस्या और प्रतिष्ठान या उधारकर्ता के बारे में नकारात्मक मार्केट रिपोर्ट मिलना आदि संकेत बैंक से बाहर निकलने पर ही प्राप्त होते हैं.

इनके अलावा तकनीकी कारणों जैसे साख सुविधा का समय से रिव्यू/नवीकरण न करना, 180 दिनों से अधिक पुराने स्टॉक स्टेटमेंट/बुक डेट स्टेटमेंट के पेटे आहरण अनुमत करना आदि के कारण भी आस्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

उक्त के संबंध में यूनियन बैंक द्वारा फील्ड में कार्यरत अपने कर्मियों के लिए विस्तृत तथा सुस्पष्ट दिशा निर्देश मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत जारी किये गये हैं, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है. इतना ही नहीं, इन संकेतों को ध्यान में रखने, समझने व विश्लेषित करने हेतु बैंक द्वारा सीबीएस सिस्टम में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं. बतौर उदाहरण- मानक आस्तियों (स्टैण्डर्ड एसेट) के अनुश्रवण हेतु एसएमए-0, एसएमए-1, एसएमए-2 तथा ईएएस-II (तकनीकी चूक) जैसे फिल्टर लगाए गये हैं और शाखाओं को मासिक आधार पर मॉक रन सूची प्रदान की जा रही है. इन संकेतों पर समय रहते ध्यान देकर आस्तियों को ठीक रखने के उपाय किए जा सकते हैं और बैंकों को वित्तीय संकट से बचाया जा सकता है.

इसी तरह परिचालन में भी सतर्कता और सजगता आवश्यक है. नकदी जमा/निकासी/प्रेषण, चेक संग्रहण/समाशोधन एवं अन्य मामलों में बैंक को होने वाली हानियों के विश्लेषण से यह बात साफ हो जाता है कि अधिकांश मामलों में प्रबंधन द्वारा जारी अनुदेशों व स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन फील्ड स्तर पर उचित रूप से नहीं किया गया.

हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण के साथ अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन के चलते अब देश की बैंकिंग व्यवस्था जोखिम के क्षेत्र में अधिक संवेदनशील हो गई है. इसके मद्देनजर विभिन्न नियामक संस्थाओं यथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीए आदि ने बैंकों में विभिन्न कानूनी प्रावधानों तथा अनुदेशों के कठोर अनुपालन पर बल दिया है. इतना ही नहीं, इनकी गैर अनुपालना से होने वाले किसी भी आर्थिक हानि या अपयश से हुई क्षति के लिए दंडात्मक प्रावधान भी इन नियामक संस्थाओं द्वारा किए गए हैं. हम सभी को याद है कि किस तरह कुछ वर्ष पहले केवाईसी मामले में हुए स्टिंग ऑपरेशन पर रिजर्व बैंक ने सख्त रुख अपनाया था और कुछ एक वित्तीय संस्थाओं को दंडित भी किया था.

एक विवेकशील बैंकर के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम सजग रहें, सतर्क रहें और संस्थागत प्रावधानों तथा अनुदेशों को लेकर अद्यतन करते रहें ताकि बैंकिंग उद्योग को, जो अभी अत्यंत चुनौती भरे समय से गुजर रहा है, किसी प्रकार के वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े.

***प्रतिभू बनर्जी***
*बड़नगर क्लस्टर, क्षे. का., इंदौर*

# Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provision of Advances

## Introduction:

Non Performing Assets (NPA) is a double-edged sword. While on the one hand, it ceases generating income for the Bank, on the other hand it takes away a part of the profit earned by bank through provisioning. It also poses great reputational risk and financial risk for the Bank.

As per the recommendations made by the Committee on the Financial System (Chairman Shri M. Narasimham), the Reserve Bank of India has introduced prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning for the advances portfolio of the banks so as to move towards greater consistency and transparency in the published accounts. These norms were applicable from the financial year 1992-93. According to this norm, interest is not to be debited on the accrual basis but only on the cash basis.

## Definition of NPA:

An asset including a leased asset ceases to generate income is treated as non performing asset (NPA). A Loan or an advance is classified as NPA as under:-

| Nature of Facility | Parameters |
|---|---|
| Term Loan | Interest and/or installment of principal remain overdue beyond 90 days |
| Overdraft/Cash Credit | i) Remains 'out of order' for more than 90 days<br>ii) Where the regular/adhoc credit limits have not been reviewed/renewed within 180 days from the due date of adhoc sanction |
| Bill Purchased/ discounted | Remains overdue beyond 90 days |
| Crop Loans (short duration crops i.e. maturing within one year) | Installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop seasons |
| Crop Loans (Long duration crops i.e. maturing after one year) | Installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season |
| Credit Card | Remains overdue beyond 90 days |
| Securitization transactions | Amount of liquidity facility remains outstanding beyond 90 days |
| Derivative transactions | Overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract which remains unpaid beyond 90 days from specified due date for payment |

| Nature of Facility | Parameters |
|---|---|
| Loan against FD, NSC, KVP, Life insurance policies | Advances against term deposits, NSCs eligible for surrender, IVPs, KVPs and life policies not treated as NPAs provided sufficient margin is available. |
| Loan guaranteed by Government | Loan guaranteed by Central Govt. not treated as NPA for asset classification and provisioning till the Government repudiates its guarantee when invoked. Treated as NPA for income recognition.<br>Advances guaranteed by the State Govt. classified as NPA as in other cases |
| Consortium advances | Based on the record of recovery of the individual member banks. |

## Definition of Out of Order in Cash Credit or Overdraft:

**a) Irregular accounts:** When outstanding balance is more than drawing power or sanctioned limit.

**b) Regular accounts (i.e. balance within limit & drawing power):**

i) There are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period

ii) When the stock statement is delayed for 90 days, the drawing power is to be reduced to nil, rendering the account irregular.

## Income Recognition Policy:

The policy of income recognition is based on the record of recovery. Income from non-performing assets (NPA) is not recognized on accrual basis but is booked as income only when it is actually received from customer. Availability of security or net worth of borrower is immaterial. Therefore, the banks should not charge and take to income account interest on any NPA. This will apply to Government guaranteed accounts also.

**Reversal of income:** If any advance, including bills purchased and discounted, becomes NPA, the entire interest accrued and credited to income account in the past periods, should be reversed if the same is not realized.

## Period of Classification of NPA A/cs:

The loan accounts are classified in 4 categories to assess the general quality of portfolio and for making provision against loan losses.

| Classification | Period |
|---|---|
| Standard – Regular | Any period |
| Standard – Irregular or out of order or overdue (called Special Mention Account – SMA) | 90 days |
| SMA-0 | 01-30 days |
| SMA-1 | 31-60 days |

| Classification | Period |
|---|---|
| SMA-2 | 61-90 days |
| Sub-Standard | 12 months |
| Doubtful – up to one year | 12 months |
| Doubtful – above one year but up to 3 years | 24 months |
| Doubtful – above 3 years | Uncertain |
| Loss | Uncertain |

## SMA classification in Agricultural accounts:

| Interest/Installment | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Crop category | Categorization of advances | | | |
| 1. Short Duration Crops | Grace period for categorizing as NPA after due date | Standard | SMA 1 | SMA 2 |
| A)Under irrigated conditions (more than one crop in a year) | 12 months (two crop seasons) | Default up to 3 months | Default more than 3 months up to 9 months | Default for more than 9 months & up to 12 months |
| B)Under rain fed conditions (Only one crop in a year) | 24 months (two crop seasons) | Default up to 12 months | Default more than 12 months & up to 21 months | Default more than 21 months & up to 24 months |
| 2. Long duration crops | 18 months (one crop season) | Default up to 3 months | Default more than 3 months & up to 15 months | Default more than 15 months & up to 18 months |

## Erosion of security value & Classification:

i) When the realizable value of the security is less than 50% of the value assessed by the bank or accepted by RBI at the time of last inspection, such account to be shifted directly to doubtful category.

ii) If realizable value of security is less than 10% of the outstanding in borrowal accounts assessed by the bank/approved valuer/ RBI, the account to classified as loss asset.

## Provisioning Norms:

Provisioning is made on all types of assets, i.e. Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets.

| Asset Classification | Percentage |
|---|---|
| Standard Assets | |
| Agriculture, MSE | 0.25% |
| Commercial real estate – Residential housing | 0.75% |
| Commercial Real Estate | 1.00% |
| Teaser home loans | 2.00% |
| Other standard loans | 0.40% |
| Sub-standard secured | 15% |
| Sub-standard Unsecured | 25% |
| Sub-standard Unsecured (Infrastructure) | 20% |

| Asset Classification | Percentage |
|---|---|
| Doubtful Assets | |
| Secured | |
| Doubtful up to 1 year (D1) | 25% |
| Doubtful more than 1 year to 3 years (D2) | 40% |
| Doubtful more than 3 years (D3) | 100% |
| Unsecured | 100% |

## Accelerated Provisioning:

Reserve Bank of India has set up the CRILC (Central Repository of Information on Large Credits) to collect, store and disseminate data on all borrowers' credit exposures including Special Mention Accounts (SMA 0, 1 & 2) having aggregate fund-based and non-fund based exposure of Rs.5.00 crore and above. In cases where banks fail to report SMA status of the accounts to CRILC or resort methods with the intent to conceal the actual status of the accounts, banks will be subjected to accelerated provisioning for these accounts and/ or other supervisory actions as deemed appropriated by RBI. The current provisioning in respect of such NPAs are as under:

| Asset Classification | Period as NPA | Revised Accelerated Provisioning |
|---|---|---|
| Sub-standard Secured | Up to 6 months | 15% |
| | 6 months to 1 year | 25% |
| Sub-standard Unsecured | Up to 6 months | 25% |
| | 6 months to 1 year | 40% |
| Doubtful up to 1 year (D1) | 2nd year | 40% (Secured) |
| | | 100% (Unsecured) |
| Doubtful more than 1 year to 3 years (D2) | 3rd and 4th years | 100% (Both secured & unsecured portion) |
| Doubtful more than 3 years (D3) | 5th year onward | 100% (Both secured & unsecured portion) |

## Some facts:

i) Asset classification is borrower-wise and not facility wise.

ii) If the customer has multiple facilities and one account became NPA, then all accounts NPA (Percolated NPA)

iii) In case of fraud A/cs, the account is straight away classified as doubtful or loss category.

iv) In case of threats for recovery due to frauds committed by borrower: 100% of the outstanding amount is to be provided over four quarters.

v) If loan is guaranteed by ECGC or credit guarantee scheme, provision not on guaranteed portion.

vi) NPA affects the profitability, financial risk and reputational risk of the bank as well as affect banks rating.

***Alekh Kumar Sahoo***
*STC, Bhubaneswar*

# Tools and Techniques of Asset Quality Management

## Introduction

The quality of bank's loan portfolio can impact its profitability, capital and liquidity. Assets quality problem are at the root of other financial problems for banks, leading to reduced net interest income and higher provisioning costs. The performance of a bank is inextricably linked with its assets quality. Managing the loan portfolio to minimize bad loan is, therefore, fundamentally important for a financial institution in todays extremely competitive and market driven business environment. In this competitive environment, managing NPA is very vital for banks. Management of NPA begins with the consciousness of a good portfolio, which warrants a better understanding of risks in lending. The management has to decide a strategy keeping in view the regulatory norms, the business environment, its market share, the risk profile, the available resources etc. The strategy should be reflected in management approved policies and procedures to monitor the portfolio. The essential containments of sound NPA management are quick identification of NPAs and maintain it at a bare minimum level to have marginal effect in balance sheets.

## Veracity of present NPA

In financial year 2018, GNPA increased to around ₹10.30 lakh crore or 11.20 percent of advances compared with ₹ 8 lakh crore or 9.50 percent of advances as on March 31, 2017. It is likely to touch 11.50 percent in this fiscal. In FY18, the banking system reported a net loss of ₹ 40000 crore because of the sharp rise in NPA and the resulting increase in loan provisioning costs. About a fifth of the slippages in FY18 were due to withdrawal of various restructuring schemes by RBI after the Insolvency and Bankruptcy code (IBC) process came into force. ₹ 3.30 lakh crore worth of NPA cases referred to NCLT for resolution under IBC.

## Strategies to manage NPA

Two main strategies are

A. Preventive Management
   (i) Preventing slippage of standard assets into NPA category.

B. Curative Management
   (i) Reducing NPAs through cash recovery, up gradation, compromise settlements and other legal measures.

## Preventing management of NPAs

At the pre-disbursement stage, appraisal techniques of bank need to be sharpened. All technical, economic, commercial, organizational and financial aspects of the project need to be assessed realistically. Bankers should satisfy themselves that the project is technically feasible with reference to technical knowhow, scale of production etc.

A major cause for NPA is fixation of unrealistic repayment schedule. Repayment schedule may be fixed taking into account the gestation or moratorium period, harvesting, income generation, surplus available etc. If the repayment schedule is defective both with reference to quantum of installment and period of recovery, assets have a tendency to become NPA.

There should be security (Prime and collateral) consciousness of the loan both by processing and sanctioning officer. Eligible accounts must be covered under CGTMSE and ECGC schemes. Security and guarantee coverage will reduce the amount of provisioning when account turns NPA. The settlement of CGTMSE/ECGC claim and realization of security add to recovery. In case of NPA, no provision required towards guaranteed portion in CGTMSE covered accounts.

At the post–disbursement stage, banks should ensure that the advance does not slip into NPA. So it requires proper follow-up and supervision to ensure both assets creation and assets utilization. There are various tools within the branch by ledger scrutiny and outside the branch by visit and market information. The banker should look for early warning signals and design proper mechanism for rectification by proper involvement with the borrower by investing proper relationship as a business partner from Personal visit and face to face discussion with borrower, the banker may come to know details relating to break down in plant and machinery, labour strike, change in management, death of a key person, reconstitution of the firm etc. All these factors have a bearing on the functioning of the unit and on its financial status.

Early warning signals can be classified into three broad categories viz.

(a) Financial
(b) Management
(c) Banking

Financial related warning signals generally emanate from the borrowers' balance sheet, income expenditure statement, statement of cash flows, statement of receivables etc.

## Common financial warning signals are:

- Persistent irregularity in the account
- Default in repayment obligation
- Devolvement of LC/invocation of guarantees
- Deterioration in liquidity/ working capital position
- Substantial increase in long term debts in relation to equity
- Declining sales etc.

## Common Management related warning signals are:

- Lack of co-operation from key personnel
- Change in management, ownership, or key personnel
- Desire to take undue risks
- Family disputes
- Poor financial controls
- Diversion of funds etc.

## Common Banking related warning signals are :

- Declining bank balances/declining operations in the account
- Opening of account with other bank
- Return of outward bills/dishonored cheques
- Sales transactions not routed through the account
- Frequent requests for excess
- Frequent delays in submitting stock statements, financial data, etc.

## Credit Assessment and Risk Management Mechanism:

Credit assessment and Risk management mechanism are ever lasting solution to the problem of NPAs. Managing credit risk is a much more forward-looking approach and is mainly concerned with managing the quality of credit portfolio before default takes place. The documentation of credit policy and credit audit immediately after the sanction is necessary to upgrade the quality of credit appraisal. In a situation of liquidity overhang, the enthusiasm of the banking system is to increase lending with compromise on asset quality, raising concern about adverse selection and potential danger of addition to the NPAs stock. It is necessary that the banking system is equipped with prudential norms to minimize if not completely avoid the problem of credit risk and develop an effective internal credit risk models for the purpose of credit risk management.

## Organizational restructuring

With regard to internal factors leading to NPAs, the onus of containing the same rest with the bank. This necessitates organizational restructuring, improvement in the managerial efficiency, skill up gradation for proper assessment of credit worthiness and a change in the attitude of the banks towards legal action, which is traditionally viewed as a measure of the last resort.

## Watch-list/Special Mention Category

The grading of the bank's risk assets is an important internal control tool. It serves the need of the Management to identify and monitor potential risks of a loan asset. Most of the banks have a system to put certain borrowable accounts under watch-list or special mention category if performing advances operating under adverse business or economic conditions are exhibiting certain distress signals. These accounts generally exhibit weaknesses which are correctable but warrant banks' closer attention. The categorization of such accounts in watch list or special mention category provides early warning signals enabling Relationship Manager or Credit Officer to anticipate credit deterioration and take necessary preventive steps to avoid their slippage into non performing advances.

## Willful Defaulters

RBI has issued revised guidelines in respect of detection of willful default and diversion and siphoning of funds. As per these guidelines, a willful default occurs when a borrower defaults in meeting its obligations to the lender when it has capacity to honor the obligations or when funds have been utilized for purposes other than those for which finance was granted. The list of willful defaulters is required to be submitted to SEBI and RBI to prevent their access to capital markets. Sharing of information of this nature helps banks in their due diligence exercise and helps in avoiding financing unscrupulous elements. RBI has advised lenders to initiate legal measures including criminal actions, wherever required, and undertake a proactive approach in change in management, where appropriate.

## Curative management of NPAs

## Non legal measures

Banks pursue the defaulting borrowers to repay their overdues by writing letters and sending representatives of the banks to the borrowers for cash recovery and up gradation of assets.

Bank may organize recovery drives, based on overdue and NPA. Officers may short list those accounts, the recovery of which would provide impetus to the system in reducing the pressure on profitability by reducing provisioning burden. This process will directly increase the cash recovery. Once the accounts become NPA, then the bankers should take steps to upgrade the account by recovering the entire overdue and upgrade the account.

## Compromise settlement

Compromise should result in early recovery of dues and also save cost to Bank. OTS is not an administrative decision, but a business decision. Interest of stakeholders should be protected by recovering maximum in minimum possible time. OTS should be done in the interest of bank at large. Borrowers demand should be carefully weighed to ensure no undue advantage is given to them. Staff accountability aspect is to be carefully examined. It must be reported to the competent authority. Committee approach to be preferred for a better judgment.

## Negotiation

The essence of negotiations is that both parties become satisfied and feel that they have won in the bargain. But this is not everybody's cup of tea. It involves maturity, understanding, adjustability and ability to become flexible. It comes out of long business experience, high level of commitment, sincerity and mutual trust.

## Legal Mechanism

In case of legal mechanism, it is observed that all the banks operate this to the maximum extent involving Lok Adalat, Debt Recovery Tribunals (DRT), Securitization Act, and Compromises (OTS), Write off.

## Lok adalat

The Lok Adalat can adjudicate existing suits pending in Courts as well as non-suit filed claims. Loan outstanding upto ₹ 20 lakh can be settled through this process. There is no burden of Court Fee when non-suit filed claims are referred to Lok Adalats. If no settlement is arrived at, the status quo will automatically be restored. The decrees passed by Lok Adalats have legal status and are binding and executable directly in an appropriate Court. The settlement through Lok Adalat is very quick compared to long delays.

## Debt Recovery Tribunal

Established under "The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI)".This is headed by presiding officer. Presiding officer will be an officer qualified to be a District judge. Application for Rs.10 lakh and above can be filed. The aggrieved party can file an application for Review before the DRAT.

**SARFAESIA Act** (The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002)

## Revenue Recovery

In order to expedite recovery through judicial process, several states have passed credit recovery legislation for recovery of banks dues more expeditiously through revenue authorities. Some states have treated bank dues at par with public demand hence expeditious legal remedies are available for recovery.

## Conclusion

The problem of NPAs can be achieved only with proper credit assessment and risk management mechanism. It is necessary that the banking system is to be equipped with prudential norms to minimize if not completely avoid the problem of NPAs. The onus of containing the factors leading to NPAs rests with banks themselves. This will necessitates organizational restructuring, improvement in the managerial efficiency and skill up-gradation for proper assessment of credit worthiness. It is better to avoid NPAs at the nascent stage of credit consideration by putting in place of rigorous and appropriate credit appraisal mechanisms.

***Dibakar Lenka***
*STC, Bhubaneswar*

# Proper and Timely Monitoring & Supervision of NPA

Most of the borrowers who approach PSB for any kind of finance are aware of the fact, or having an impression of it, that PSB lacks tooth for the effective recovery of credit finance by them. Which is true, but this is also true that we do not timely and effectively exercise our rights provided by the law in most of the cases, causing such notion.Spurt in the NPA level of PSBs can be attributed to this, to a certain level.

If we look at the whole cycle of finance which turns bad will look like following figure.

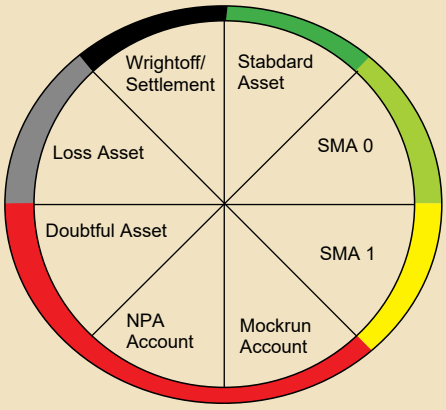


The maximum time and energy is generally applied on mock run part of this cycle, and this part is elongated to such an extent that finally bank ends up with loss in such finances, means account appears in mock-run list regularly for very long time and it is being saved from turning NPA by just recovering critical amount or using other means to save it which is even worse. During this period primary security and book debts are compromised and by the time bank take any action what we left with is empty godowns and absconding borrower.

We need to change our strategy and prospective to deal with such difficult accounts, but there is nothing new which is required, all necessary guidelines are already provided by the bank and we need to honestly start using it and adhere to the circulars.

Obviously selection of borrower and quality of appraisal is first and foremost important part of any credit cycle. In a situation of excess liquidity and the over enthusiasm of the banks to increase lending could lead to poor asset quality, due to adverse selection of borrower and potential danger of addition of the stock of NPA. It is therefore, necessary to enhance our skills as banker and credit appraisal officer, so that we can assess the borrower and its credit worthiness. If I summaries following points can be followed to avoid selection of wrong accounts.

- Do not trust any information provided by the borrower unless it is verified by you and supported by documents, even if he is existing customer and doing banking with us for many years.
- Due diligence shall not be done casually, like visit to borrowers place or casually verifying details of his self employment/employer or quotations provided by him.
- Borrower's background, integrity, whereabouts, economic well being and technical feasibility should be carefully studied
- Borrower's capacity to run things and overcome the challenges of the business should be studied
- We should know the integrity and prowess of third party agencies like, advocate, architect, CA's etc, engaged in a proposal.
- Never over finance or under finance the borrower.
- Finance provided to the customer should be on time, any delay can seriously hamper business capabilities of the borrower and in turn our asset quality.

Despite of an efficient credit appraisal and disbursement, problems can still arise due to various factors which are out of control of borrower as well as bank. But our efficient NPA management system lies in the fact that NPA identification should be quick and their containment at minimum level. Instead of laying our whole hearted energy on mock-run accounts, we should shift our focus on SMA 0 area, and maximum time and energy should be devoted to this particular area.

But this not happening, and most of the branches are busy with mock-run every month, regional offices are also putting their emphasis on mock run only. Every month lists are sent to branches for the accounts appearing in mock-run and CRLD dept is busy with this only till last day of every month. We have changed the habit of customers to deposit only critical amount, because this is what conveyed to customer every month, and he too is a habit of depositing critical amount on last day of the month only. I know few branches that works on SMA 0 and are extremely successful in containing NPAs.

To understand this let us take an example

"M/S XYZ industries is financed by our bank for working capital and term loan, in starting month their were regular transactions in the Cash Credit account and borrower is submitting stock statement reluctantly every month, eventually transactions started to slow down after some time, branch is obtaining stock statement, term loan installment is being deducted from cash credit account. Then borrower approaches for overdraft and after casual inquiry for the purpose it is granted, and this becomes regular feature of the account, over draft is granted and recovered within time or with default of few days. Within few months account started to appear in mock-run and branch starts following the borrower for the same this accounts appears in mock-run for several years, branch resorts to all means to save this account from slippage, when matter runs out of the hand of branch, account turns NPA".

This is not an unusual example, but the story of almost all the accounts turning NPA, technically speaking accounts turns NPA at that very point of time borrower stops earning from his business and this happens relatively very early in business cycle and we can also see the reflection of the same in account.

- When transaction started to slow down branch should have inquired about the same from borrower and verify it from market due diligence, whether a regular business cycle or some other reason is behind of it, so as to take precautionary measures to contain the situation.
- Most of the cases physical verification of stock is not assessed just a stock statement is taken and filed to satisfy the customers, in this case if physical verification is done then branch should have came to know the fact that requisite stock is not maintained, Either low stock and high unrecovered book debt will be there or high unsold more than 90 month old stock will be found, and in both the cases credit exposure is required to be lowered which is never done.
- When borrower seldom approaches for overdraft, thorough enquiry should be done with proper due diligence and should be recorded in file, after getting fully satisfied with justification, only then it should be provided and if demand is justified and regular then borrower should be advised to apply for enhancement else corrective action should be taken to protect the bank's interest.
- Branch should have never waited for account to appear in mock-run list and it should follow from the very first month when party defaulted, it is always better to send advance notice to party for upcoming installment. Branch should use the technology provided by bank and take the list from LAPS of accounts appearing in SMA 0 instead of mock-run list.
- Regional Office CRLD dept. should also focus on SMA 0 and start following the same with branches, obviously when CRLD starts working on SMA 0 this will be additional burden on it but after few months the mock-run list will reduce substantially and burden of CRLD as well. Reason for regular appearance of account in mock-run should be sought from branches and recorded, necessary help should be provided to the branch.
- Most important of all branch should not resort to unethical means to save the account from turning NPA which obviously done under pressure to save self image, instead of promoting the same controlling office and CRLD dept. should restrict the branch from doing the same.
- Any diversion of fund should be checked and not allowed and if happens corrective action should be taken, even if diverted fund is used in some business activity, it is not in the favor of bank, as we have not assessed the operational and other risk involved with that business and our asset could jeopardize.
- Branches should not cross sell our investment products(like insurance and mutual fund etc) forcefully to our borrowers as this will be miss selling, we are selling investment products to a customer who is not having excess funds to invest and unfortunately our own fund will be diverted to the same.
- We should change our approach of considering legal action as last remedy.

We have to accept the facts that, customer will always try to hide the adversity his business is facing, so as to stop the bank from taking any corrective action, but we should always investigate any account which is not as per sanction terms and condition. I will end this article with a real life example where a branch manager saved an account just by being attentive, curious and prudent.

*"A FMCG whole seller was financed by our bank's branch; the good sold by the borrower was seasonal so transaction in the account happens in a particular season only. Account was regular and was not over drawn ever, when in one such season transaction in the account not started in the same amount and number as expected, the branch manager got curious and visited the nearby market where the borrower used to supply. Branch manager stopped by a shop and enquired with shop keeper "where is Mr. ABC now a days, I haven't seen him, is he sending someone else to supply" and in response shopkeeper replied "haven't you heard, Mr. ABC has lost the agreement from the company and the supplies is being provided by Mr. EFG now a days," branch manager asked "when did this happened" shopkeeper; "last month". When branch manager returned to branch he ordered to freeze debit of the account, reported the matter to regional office and called borrower to visit the branch to discuss the matter. When borrower visited the branch, BM further came to know that after losing agreement to sell the goods borrower is using funds in his other business, he wanted the branch to continue his credit limit, but BM do not allow the same and asked the borrower to close the account, and eventually account was closed in next few months, by instantly starting recovery process."*

When things started to turn bad it does not appears that much big a problem and can be contained very easily, but if we let it be, then things will move out of our hands very quickly.

***Rohtash Singh***
*R. O. Dehradun*

## पुरस्कार और सम्मान

केरल राज्य सरकार के 'कुड़ुम्बश्री मिशन' में एन एच जी बैंक लिंकेज (NHG Bank Linkage) के अंतर्गत बेहतर ऋण सहयोग देने हेतु हमारे बैंक को वर्ष 2017–18 के लिए 'श्रेष्ठ बैंक' से सम्मानित किया गया. दिनांक 17 मई, 2018 को कोझीकोड में "कुड़ुम्बश्री" के 20वें वार्षिकोत्सव के दौरान आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में श्री बिजू वासुदेवन, उप महाप्रबंधक व क्षेत्र प्रमुख, कोझीकोड क्षेत्र ने श्री पुरुषन कड़लुंडी, माननीय विधायक, बालुसेरी, केरल के करकमलों से यह पुरस्कार ग्रहण किया. इस अवसर पर केरल राज्य सरकार में स्थानीय प्रशासन मंत्री श्री के टी ज़लील; कृषि मंत्री श्री सुनील कुमार एवं परिवहन मंत्री ए के ससीन्द्रन भी उपस्थित थे.

# IS OTS A MORAL HAZARD

One Time Settlement (OTS) is one of the most Popular and Successful models for Recovery of NPAs. Compromise settlement is an integral part of Indian Banking. All the banks have their own recovery policy which permits negotiated settlement of NPAs. The main objective is to recover the maximum amount within the shortest possible time. It is all the more important in India, looking at our extant system, where delay in enforcing the compliance of contract is fairly common. Being a business organization, it is prudent to go for profit maximization and decisions should be taken to further our business needs.

But there is a general perception that negotiated settlement engenders moral hazard and undermines honest credit culture. Moral Hazard arises when a contract or financial arrangement creates incentives for the parties involved to act against the interest of others. The following questions are generally raised during public discourse:

1. Whether "OTS" encourages people to default in their contractual obligations and seek undue advantage by settling their loans under "OTS" even if they have capacity to repay the full dues.
2. Whether Banks are losing money by not striving to recover the full dues but resort to the so called easier option of "OTS".
3. Whether standard borrowers are treated unfairly and are at a disadvantage.

## Let us examine each case

As stated earlier "OTS" is based on the premise of recovering the maximum amount within the shortest possible time with the co-operation of borrowers. It is pertinent to mention that any business is modeled on the premise of profit maximization. Hence if enforceability of a contract is in question, naturally people will seek discount and may opt for default. But default comes at the expense of reputational risk and it is this disgrace which prohibits people from defaulting especially if it is a going concern or the unit is functioning. Also, whenever there is default, recovery process is initiated and all out efforts are made to recover contractual dues. After the introduction of bankruptcy code there is every chance of the borrower losing control over the unit/ business. Hence, a going concern having assets/ profits will generally not opt to default and risk reputational loss for a little gain.

Coming to the second point, the answer is "yes". Banks are losing money to the tune of total sacrifice as per contractual dues. But the scale tilts in favour of 'OTS' because of the following points:

### A. Time value of money:

One of the main features of OTS is recovery within a short time span. It is common knowledge that money at present has more value than the future. More so, the amount recovered, can be utilized to recycle and generate more profits.

### B. Deterioration of assets:

With passage of time, the assets financed by banks, generally lose their value due to depreciation and general wear & tear. If the units are closed, the value depreciates more rapidly due to non-maintenance. Also the appreciation in value of immovable assets cannot be relied upon in today's economy scenario.

### C. No guarantee of full recovery in the long run:

Last but the most important aspect is the inordinate delay in our system regarding enforcing the contract for recovery of our dues. Even in case of decreed account also, the execution of decree takes much time and rate of success is not so encouraging.

Hence, prudency demands that recovering our dues quickly should be preferred, looking at the net present value, even if there is a sacrifice.

In case of third point, it is pertinent to note that, even in today's scenario more than 4/5th of our assets are in standard category. The facility extended to a standard borrower is not extended to borrower who defaults and repays through "OTS". It is common knowledge that settlement of a loan brings along with it a reputation which can hardly be called "desirable". Moreover settlement of loan should, at the best, should be seen as sharing of losses rather than rewarding a NPA borrower. Hence, it cannot be said that "OTS" is unfair to standard borrowers.

But in any case, the following aspects are/ should always be looked into before entering into a negotiated settlement:

1. OTS should be done to liberate people from their contractual obligation who

are in distress. But people having capacity to pay should be made to pay their contractual dues. In all cases, means of the borrower should be diligently & properly assessed at the time of OTS.

2. It should be ensured that in all NPA accounts, all recovery measures have been initiated and pursued diligently and vigorously to its logical conclusion.
3. It is to be seen that we are not surrendering our advantages by going for negotiated settlement. There should be an honest appraisal of our recovery measures and the amount recovered through settlement should not be less than present value of anticipated recovery through legal measures.
4. Mere offering of a settlement proposal should not be an excuse for cessation of all recovery measures. Time period for payment of settlement amount should be as short as possible and should be strictly adhered to and non-adherence to time schedule of repayment by borrower should trigger immediate re-instatement of all recovery measures.

Entrepreneurial mindset invites risk and so failures are inevitable. It is this mindset that has propelled western economy to such dizzying heights. When we think of any successful person, we can see that the initial failures always shaped their later careers and the experience gained helped them to find success at a later stage. Hence bonafide failures should not be condemned and a second chance should always be extended.

When the intention and execution of OTS is properly synced, OTS is one of the best forms of Recovery. It can be safely concluded that OTS cannot be termed as moral hazard and can be resorted to in the best interest of Bank.

It should always be kept in mind that "Recovery of our dues is not only our legal right but also our moral right".

*J. K. Mishra*
*CRD, CO.*

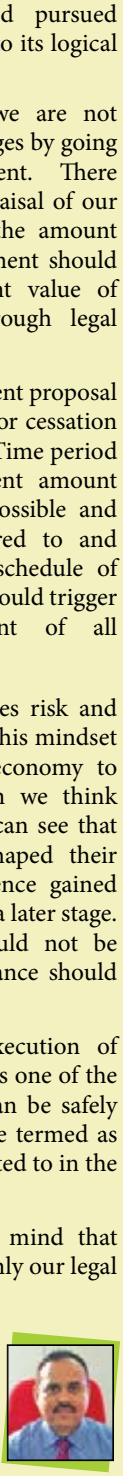

# Sale of Assets to ARCs/NBFCs/BANKs/FIs

**Introduction :**

***Reserve Bank of India (RBI) guidelines issued from time to time to provide for a legal and regulatory framework for sale of non-performing financial assets to ARCs/NBFCs/BANKs/FIs registered with (RBI) under SARFAESIA.***

***In order to effectively implement the strategy and maximize the recovery of non-performing assets, there is a need for a policy which aligns the business imperatives of the Bank with the applicable law, RBI guidelines and lays down clearly the procedure to be followed by Bank for sale of non-performing financial assets to ARCs/NBFCs/BANKs/FIs.***

***Bank has been making efforts to identify and assign eligible NPA accounts to ARCs/NBFCs/BANKs/FIs on a regular basis in its pursuit to bring down NPAs.***

## Financial Assets that can be sold:

a) A Non-Performing Asset (NPA) including a non-performing investments in the books of the Bank;

b) A standard asset where, the asset is under consortium/multiple banking arrangements/ 75% by value of the asset is classified as non-performing asset in the books of other banks/ at least 75% (by value) of the banks/ Financial Institutions who are under consortium/multiple banking arrangements agree to the sale of the asset to ARC/NBFC/BANK/FI.

c) An asset reported as SMA-2 Central Repository for Information on Large Credit (CRILC).

## Rules for sale of Financial Asset to ARC/NBFC/BANK/FI :

a) The sale shall be a true sale and without recourse basis i.e., entire credit risk associated with the financial asset should be transferred to ARC/NBFC/ BANK/FI.

b) There shall not be any known liability devolving on the Bank after sale save and except any contingent liability in the nature of bank guarantee or any counter claim against the Bank.

c) Subsequent to sale Bank should not assume any operational, legal or any other type of risk with respect to the financial asset sold.

d) Assets reported as fraud should not be sold.

**Types of sale: There are two types of sales, which are discussed here under.**

i) **Portfolio sale :** Pool of financial assets comprising NPAs of group accounts, NPA accounts with common security or NPAs of homogenous class such housing loans, vehicle loans, consumer loans as the case may be can be considered for sale to ARC/NBFC/ BANK/FI.

ii) **Single Credit sale :** Sale of one particular NPA account to ARC/ NBFC/BANK/FI leveraging the size of loan and underlying assets to obtain a good price

## Procedure for Selection of Assets to be Sold:

On the basis of norms for selection of assets for sale set out above, at CO level, assets will be identified/selected for sale. In terms of the Bank's Recovery Policy on sale of NPAs to ARCs/NBFCs/BANKs/FIs, NPA accounts are selected for sale on the basis of following parameters:

a) Cash recovery in the near term i.e. 6 months to one year is not foreseen in the account.

b) There are no chances of One Time Settlement in the near term i.e. 6 months to one year.

c) Cost of carry in the books of the Bank can be significantly reduced through the sale.

d) Other Banks either under Consortium/ Multiple Banking sold their financial assets to ARCs or Bank or FIs or NBFCs.

e) Asset Specific bottle necks leading to delay in recovery such as

   i. Large number of lenders and delay in recovery action

   ii. Share of the Bank is miniscule

   iii. Pooled securities and lender interse sharing issues.

f) Value of securities is not significant.

g) There is stalemate in recovery due to stay/stand still from Courts/ Tribunal

h) Any other relevant matter.

## Process for Sale :

In terms of Policy on sale of Financial Assets to Securitization/Reconstruction Companies, after selection of assets for sale, in-principle approval to be obtained from the competent authority for initiating the process of sale. The following steps are required to be followed for sale to ARCs/ NBFCs/BANKs/FIs:

a) Preparation of Preliminary Information Memorandum (PIM) of all the accounts.

b) Ascertaining valuation of financial assets as per the Valuation procedure.

c) Fixation of Reserve Price with the approval of ARC Sale Committee

d) Preparation of Request for Bid (RFB) and obtaining approval from the ARC Sale Committee.

e) Arranging due diligence by the interested bidders.

f) Receipt of bids from the interested bidders.

g) Scrutiny of bids by ARC Sale Committee.

h) Approval of sale by Competent Authority.

## Prudential norms and accounting for the sale & Investment transactions:

a) Sale consideration from ARC will be credited to the account to reduce the NPA. The balance in the account will be written off by reversing the available provision and there after remaining outstanding in the account will be written off absolutely in Bank books to the debit of Income account.

b) Security Receipts (SRs) are controlled as investment at lower of the NBV (net book value) or the face value of SRs and SRs controlled at face value and are subject to mark to market.

c) Bank as an investor in the security receipts, to follow up with the ARC on quarterly basis and ascertain recovery/cash flow in the Trust and the distribution that the Trust is likely to make during the quarter.

d) Bank to obtain reports from ARC with respect to planning for recovery, progress made, NAV of the investments etc. on annual basis.

e) ARCs is entitled to Management fee as per the extant guidelines, which shall be paid out of the recoveries effected by ARCs.

f) Further incentive on net recovery amount will be given to ARCs as per extant guidelines, if recovery is effected within 3 years.

## Revised Guidelines on Sale of Stressed Assets :

a) With effect from 01.04.2017, where the investment by a Bank in SRs backed by stressed assets sold by it, under an asset securitization is more than 50% of SRs backed by its sold assets and issued under that securitization, the provisions held in respect of these SRs will be subject to a floor, this floor shall be progressive provisioning as per extant asset classification and provisioning norms, notionally treating book value of these SRs as the corresponding stressed loans, assuming these had remained, without recovery of principal, on the Banks books.

b) With effect from 01.04.2018, the above threshold of 50% will stand reduced to 10%.

c) **Swiss Auction Method-** is a new process of giving bid/offer that any ARC/NBFC/BANK/FI can submit their offer, which will be made online and a second person can give their counter bids with improved offer and the original bidder will get a chance to improve their offer over counter bidder. In case the original bidder is not able to match the competing counter bid, the asset will be assigned to the counter bidder.

The order of percentage to sell the asset shall be as follows.

i) The ARC/NBFC/BANK/FI, which has already acquired highest significant stake

ii) The original bidder

iii) The highest bidder during the counter bidding process

d) Finally Bank will have the two options either to sell the asset to winning bidder, as determined above or if the Bank decides not to sell the asset to winning bidder, Bank will be required to make immediate provision on the account to the extent of the higher of the discount on the book value quoted by the highest bidder and the provisioning required as per extant asset classification and provisioning norms.

***Sai Manohar Kaki***
*CRD-DART*

# Performance Always Pays Back !!

Under the Reward/Recognition Scheme for reduction of NPAs for FY 2017-18, a grand felicitation function was organised at 'Theme Park Imagica' and 'Hotel Novotel' in Khopoli near Mumbai on 19th and 20th May, 2018. Based on the performance during FY 2017-18 and fulfillment of eligibility criteria of the scheme, the following staff members qualified:

1. FGMs and Recovery In-charge of top 3 Zones.
2. Regional Heads and Recovery In-charge of 8 qualifying Regions
3. Branch Heads and Recovery In-charge of 25 top performing branches under different categories across India.

All the winners with their families attended the function. Our MD & CEO, Shri Rajkiran Rai G. as well as ED, Shri Vinod Kathuria graced the occasion. In a glittering function held at Hotel Novotel on 19th May, 2018, winners were presented with trophies as well as certificates by our MD & CEO as well as ED. On the same day, a gala musical event in the evening was also arranged. A tour of Imagica Theme Park as well as Snow Park was conducted on 20th May 2018. All the winners along with their family members thoroughly enjoyed the function and returned with fond memories of the function with a firm commitment to further better in recovery of NPAs.

*D.K. Gupta*
*CRD, C.O.*

# बासेल मानदंडो की अनुपालना में एनपीए वसूली की भूमिका

रिजर्व बैंक द्वारा नरसिंहम कमेटी की सिफ़ारिश पर आय निर्धारण मापदंड वर्ष 1993 में लागू किया गया. आय निर्धारण व संपत्ति वर्गीकरण मापदंड लागू होने के बाद संपत्ति से आय उपचित आधार से वास्तविक आधार पर होने लगा. इसके साथ ही एनपीए वर्गीकरण का नियम लागू हो गया.

एनपीए का मतलब होता है वैसी संपत्ति, जिससे कोई आय न हो. आय निर्धारण व संपत्ति वर्गीकरण मापदंड के अनुसार सारे संपत्ति को चार भागों में वर्गीकृत कर दिया गया. ये चार हैं मानक परिसंपत्ति, अवमानक परिसंपत्ति, संदिग्ध परिसंपत्ति और नुकसान परिसंपत्ति. आय निर्धारण मापदंड वास्तविक आधार पर वसूली नहीं होने की स्थिति में संपत्ति एनपीए होने लगा. प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए अलग-अलग प्रावधानिकरण लागू किया गया. जैसे

| मानक परिसंपत्ति में | | प्रावधान (%) |
|---|---|---|
| | कृषि व सूक्ष्म, छोटे, माध्यम इकाई के लिए | 0.25% |
| | व्यावसायिक अचल संपत्ति | 1.00% |
| | गृह ऋण(टीजर) | 2.00% |
| | पुनर्गठित ऋण 01.06.2013 के बाद (पहले 2 साल के लिए) | 5.00% |
| | दूसरे अन्य ऋण | 0.40% |
| अवमानक परिसंपत्ति पर | सामान्य प्रावधान कुल बकाया शेष पर | 15% |
| | अतिरिक्त प्रावधान असुरक्षित अवमानक परिसंपत्ति पर | 10% |
| संदिग्ध परिसंपत्ति पर | | |
| | असुरक्षित संदिग्ध परिसंपत्ति पर | 100% |
| सुरक्षित संदिग्ध परिसंपत्ति पर | 1वर्ष तक | 25% |
| | 1वर्ष से 3 वर्ष तक | 40% |
| | 3 वर्ष से अधिक पर | 100% |
| नुकसान परिसंपत्ति की स्थिति में | | 100% |

रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार एनपीए होने के बाद सामान्य प्रोविज़न कवरेज अनुपात 70% होना चाहिए. इसका मतलब यह है कि अगर एक ऋण खाता एनपीए होता है तो :

- बैंक की आय उस खाते से बंद हो जाती है.
- बैंक के उपार्जन क्षमता को प्रभावित करता है जिससे ब्याज दर प्रभावित होती है.
- बैंक की संरक्षित पूंजी से प्रावधान करना पड़ता है जिससे बैंक को दोहरा नुकसान होता है.
- पूंजी की लागत बढ़ जाती है.
- एनपीए पर ज्यादा प्रावधान से पूंजी पर्याप्त निधि पर अनुपात कम हो जाता है.
- एनपीए से बैंक की शेयर मूल्य कम हो जाती है.
- संपत्ति से होने वाली आय को बुरी तरह प्रभावित करता है.
- पूंजी की लागत में बढ़ोतरी होती है.
- परिसंपत्ति व देनदारी बेमेल हो जाता है.
- एनपीए बैंक के जोखिम सहने की क्षमता को प्रभावित करता है.

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल कमिटी बैंक में पूंजी उपायों पर तीन बार सिफारिशें की जो इस प्रकार हैं :

**बासेल-1 :** 1988 (भारत में लागू किया गया 1993)

**बासेल-2 :** 2006 (भारत में लागू किया गया 2008)

**बासेल-3 :** 2010(भारत में लागू किया गया 2013)

दिसम्बर 2010 में बीसीबीएस ने बैंक में अधिक लचीलापन होने के कारण व्यापक नियामक ढांचा जारी किया जो बासेल III के नाम से जाना जाता है. बासेल III भारत में मार्च 2019 से पूर्णत: लागू होनी है. बासेल III के मुख्य उदेश्य निम्नलिखित हैं :

क) बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक व वित्तीय संकट की स्थिति के झटके को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाना.

ख) वास्तविक अर्थव्यवस्था का वित्तीय क्षेत्र से होने वाले नुकसान को कम करना
इसके लिए बैंक को दो स्तर में पूंजी पर्याप्त अनुपात की जरूरत है.

क) समेकित स्तर पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात

ख) स्टैंडअलोन स्तर पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात

**बासेल III ढाँचा के तीन स्तंभ हैं:**

स्तंभ 1. न्यूनतम पूंजी मानक

स्तंभ 2. पर्यवेक्षी समीक्षा और

स्तंभ 3. बाजार अनुशासन

**स्तंभ 1 के अनुसार न्यूनतम पूंजी मानक की जरूरत है, जो इस प्रकार हैं:**

क) टायर 1 पूंजी : टायर 1 पूंजी में शामिल हैं

अ) सामान्य पूंजी टायर 1 (अनवरत पूंजी के आधार पर) और

आ) अतिरिक्त पूंजी टायर 1

ख) टायर 2 पूंजी (अनवरत पूंजी के आधार पर)

इसके अतिरिक्त बैंक को पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की जरूरत है

**सम्पूर्ण पूंजी (जोखिम आधारित पूंजी के % के आधार पर):**

| | | भारत में | बीसीबीएस के अनुसार |
|---|---|---|---|
| 1. | न्यूनतम सामान्य इक्विटी टायर 1 अनुपात (CET1) | 5.5 | 4.5 |
| 2. | अतिरिक्त टायर 1 पूंजी अनुपात | 1.5 | 1.5 |
| 3. | न्यूनतम टायर 1 पूंजी अनुपात (1+2) | 7.0 | 6.0 |
| 4. | टायर 2 पूंजी अनुपात | 2.0 | 2.0 |
| 5. | न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात (3+4) | 9.0 | 8.0 |
| 6. | पूंजी संरक्षण बफर (CCB) | 2.5 | 2.5 |
| 7. | न्यूनतम CET 1 अनुपात + CCB (1+6) | 8.0 | 7.0 |
| 8. | न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात+CCB (5+6) | 11.5 | 10.5 |

बासेल III के अनुसार पूंजी अनुपात की गणना इस प्रकार करनी है :

अ. सामान्य इक्विटी टायर 1 पूंजी अनुपात = सामान्य इक्विटी टायर 1 पूंजी/जोखिम आधारित आस्ति (ऋण जोखिम+बाजार जोखिम+परिचालन जोखिम)

आ. टायर 1 पूंजी अनुपात= टायर 1 पूंजी/ जोखिम आधारित आस्ति(ऋण जोखिम+बाजार जोखिम+परिचालन जोखिम)

इ. कुल पूंजी अनुपात(CRAR)=कुल योग्य पूंजी/ जोखिम आधारित आस्ति(ऋण जोखिम+बाजार जोखिम+परिचालन जोखिम)

इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जोखिम आधारित आस्ति के लिए पूंजी की जरूरत है. अगर पूंजी नहीं रहेगी तो बैंक ऋण नहीं दे सकता है. कोई भी व्यवसाय में व्यापार का निरंतर बढ़ोतरी जरूरी है. खासकर बैंकिंग क्षेत्र में अगर हम व्यवसाय का प्रसार चाहते हैं तो पूंजी की जरूरत होगी. पूंजी में भी टायर 1 पूंजी की ज्यादा जरूरत है. पूंजी के सृजन के साधन सीमित हैं जैसे लाभ उत्पन्न करके शेयर जारी करके या सरकार द्वारा प्रदत्त अगर एक आस्ति अवमानक श्रेणी में जाता है तो बैंक का करीब नौ से दस गुना प्रसार रुक जाता है. जो दिये गए उदाहरण से समझा जा सकता है– जैसे अगर ₹ 100 एनपीए होता है तो इस आस्ति से होने वाली आय करीब ₹ 10 की आय बंद हो जाती है साथ ही साथ जो हमारा आय/पूंजी है उससे उस एनपीए खाता के लिए प्रावधान की जरूरत होती है. बैंक को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 70% सामान्य प्रोविज़न कवरेज अनुपात की जरूरत है. इसका अर्थ यह है कि हमें जो पूंजी अपने व्यापार के विस्तार के लिए लगाना चाहिए वो एनपीए के प्रावधान में चला जाता है. आज बैंकों का एनपीए बढ़ गया है. जिससे बैंकों की पूंजी अवमानक आस्तियों के प्रावधानीकरण में चला गया है. इससे बैंक अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर पा रहा है. स्टाफ का समय भी अनुत्पादक आस्ति के वसूली में चला जाता है जो कि व्यापार विस्तार में लगना चाहिए था. आज बैंक घाटे में है, इसका मुख्य कारण प्रावधान है. इसके विपरीत अगर एनपीए खाते में वसूली करेंगे तो जो प्रावधान एनपीए खाते के लिए किया गया था वह प्रावधान मुक्त हो जाएगा. किसी भी एनपीए खाते में वसूली से बैंकों के कैपिटल में सीधे बढ़ोत्तरी होती है. जैसा कि हम जानते हैं कि बासेल नियम के अनुसार बैंकों को व्यापार विस्तार के लिए पूंजी की जरूरत है. एनपीए वसूली सीधे–सीधे हमारी पूंजी बढ़ाएगी जो बासेल अनुपालन में मदद करेगा. एक अनुमान के अनुसार बैंकों को मार्च 2020 तक करीब अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ पूंजी की जरूरत पड़ेगी. जिसे हम सबको मिलकर निम्न प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे ग्राहक का विश्वास भी बढ़ेगा और बासेल 3 की अनुपालना में भी मदद मिलेगी.

- गुणवत्तायुक्त ऋण प्रदान करना
- शीघ्र एनपीए आस्ति वसूली करना
- ऋण आस्ति को एनपीए में जाने से बचाना
- एनपीए में परिवर्तन के नियम कानून में बदलाव करना
- एमआईएस को सही करना
- एक्सपायर्ड बैंक गारंटी को रिर्वस करना

*प्रभात सिंह सुमन*
*स्टा. प्र. के. भुवनेश्वर*

## शुभमस्तु

हम आपके सुखद एवं सक्रिय सेवानिवृत्त जीवन की कामना करते हैं.

श्रीमती रेखा नायक
महाप्रबंधक

श्री ए. के. दीक्षित
महाप्रबंधक

श्री वी. पी. उशारिया
महाप्रबंधक

श्री आर. रामनाथन
महाप्रबंधक

श्री विमलेश एम. जैन
उप महप्रबंधक

श्री आई. विश्वनाथन
उप महाप्रबंधक

श्री विवेक काथवटे
उप महाप्रबंधक

श्री नरेश कुमार श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक

# Use of Digital Technology in NPA Management

Digital technologies today are disrupting and repositioning the lives of every banker and customer. Today, there are two buzz phrases in banking, difficult to miss — digital disruption and NPAs. The approach is to deal with them separately rather than in a complementing co-operative and mutually simulating way.

Banks have embarked, in ways small and big, on the digitisation bandwagon. However, investments and the learnings have stayed limited to retail space.

Digital platforms and digital interfaces are very prevalent and widespread. Data and analytics are used for greater customer experience, driving revenues, engaging customers, increasing productivity and making on the go offers of new banking products and services. Corporate banking and risk management applications either have got a backseat or were late starters. A victim of late adoption of digital is the NPAs area, the biggest headache afflicting the Indian banking system.

Let us look into the common root causes of the non-performing assets (NPAs) problem. On the borrowing entity side, the problems relate to cash and loan misutilisation, suboptimal project management and oversight, invisible and obscure corporate structures, inter corporate/ intra-group siphoning, excess leverage on the balance sheets and creative accounting practices. At banks, highly divergent loan appraisal standards, absence of common data base, lack of timely intervention on red flags, excessive use of discretion, reliance on business models with suspect assumptions, non-perfection of security interests, non-enforcement of loan covenants and non-notification to statutory authorities are common problems of NPA management.

As these issues are waiting for resolution, probably with significant systemic and social costs, there is a silver lining. Robotic process automation (RPA) and data analytics could be used to improve the deficiencies of the banking sector and control the shenanigans of the borrowers. Established used cases from retail and consumer banking could be utilised without large investments and IT change.

So, how can a bank apply data, analytics and automation to tackle these issues? There could be many solutions. For example, a common big data platform which takes, ingests and processes data relating to a company from various sources, including social media could be the first step. This platform can deploy standard open source and inexpensive analytical tools to create dashboards and distribute insights to prevent borrowers from having the present arbitrage out of distributed, unconnected and diverse databases. Similarly, the deployment of analytics and a layer of artificial intelligence based rule engine could help eliminate or reduce subjectivities in appraisals and human errors in assessments, through validations and logical extrapolations. At the loan management stage, big data and use of block-chain technology can easily enforce credit discipline across banks and reduce deviant behaviour by initiation of non-discretionary first-stage action like statutory notification, reduction in drawing powers, etc.

Many banks today are working on early warning signals (EWS), which are essentially the deployment of big data and analytics technology for getting dashboards on defined issues. However, first level coordination and actioning is largely manual. Use of automation with EWS analytics can improve and fortify quick action on EWS. At the resolution stage, collaboration for security valuation, notification of common resolution and recovery strategy, etc. could be enhanced by using big data points like similar transactions, zone prices, purchase price history, etc. With RPA and block-chain, base lining and registry searches of prices could be highly transparent, data based, reliable and accessible. Suitable algorithms and analytic models shall easily decipher patterns of siphoning of funds from multiple points in the banking and financial system based on unique identifiers, big data, natural language processing and use of inexpensive technologies like geo-tagging and NFC. Cartelisation, often resorted to by borrowers to prevent banks recovering fair value of security, could be thwarted by using analytics. Additionally, due to process enhancement and strong database automation, decision making is expected to be transparent with auditable and well documented transaction trails. These are expected to help reduce the fears of later accountability from the minds of the bankers, a major impediment in rebooting of the system. As observed in the consumer space, the confidence level of successful utilisation of analytic technology is very high in general. Given the general acceptance of data science and RPA at policy making, legislative and the operational levels, the ecosystem is conducive.

One of the biggest impacts of NPAs (Non-performing asset) is the lenders suffering from decreasing profit margins. Plus, the financial strain in the banking sector results in fewer funds being available, to finance

other projects which negatively impact the larger national economy. Moreover, the banks have to maintain higher interest rates in order to maintain their profit margin. They also have to re-direct financial support from the good projects to the bad ones.

In case of public sector banks, deteriorating state of the bank means the shareholders get bad returns, which in turn means that government gets less money as a dividend. Consequently, it may affect easy deployment of funds for infrastructure/ social development leading to social/political costs. NPAs associated cases put added pressure to already pending cases with the judiciary. **Solving the NPA crises – the technology way.**

The RBI itself has made it clear that it wants banks to automate data management and record keeping as much as possible and complete periodic regulatory reporting without intervening manually. Core banking applications can do the above, more so, it can put an end to the manipulations of NPAs- which is a common practice in the manual system. Asides from improving compliance, the application can add value by aggregating data across the company and its touch-points. This will make it easily accessible to the bank as a unified view of each customer.

The NPA Management solution will help assess credit ratings, give early warning signals, classify special mentions accounts and take actions like a follow-up, schedule meetings, file legal cases etc., which will be the first crucial step in ensuring to monitor and manage their existing loan books better. Over time they will also provide valuable inputs to credit policy which would effectively enhance improve asset quality. The NPA solution will help banks to manage the large documentation and compliance part that comes with managing the NPAs.

Technology can bring about a revolutionary shift in NPA management in India. Automated solutions can not only assist in better data analysis but also enable early indicators that will alert before the situation nosedives. Therefore, this will give banks time to take appropriate measures. A new horizon is waiting if we make a paradigm shift for proactive NPA management using the advancement in technology.

***Aayushi Agrawal***
*RO Jaipur*



## The 'TT SUPREMO'

The Table Tennis Star **Gnanasekaran Sathiyan,** son of Smt. Malarkodi Gnanasekaran working in Service Branch, Chennai gave his best at the **Commonwealth Games** held at Gold Coast, Queensland, Australia during 4th to 15th April, 2018 clinching 3 medals - 'Gold' in the Men's Team event; a 'Silver' in the Men's Doubles event partnering with Achanta Sharath Kamal and a 'Bronze' in the Mixed Doubles event partnering with Manika Batra. We all unionites are proud of you dear Sathiyan!!

*One of our Unionites Ms. Gunasekaran, who is working in Service Br. Chennai, her Son Mr.Sathiyan Gunasekaran had won **Gold Medal in Commonwealth Games** at Gold Coast, Australia.*

## Kabaddi.... Kabaddi.....

This season our Kabaddi Team performed excellently winning ***'Shivneri Krida Mandal State Level Kabaddi Tournament'***. They had to finish at the second place (Runners Up) at the 'Prabhadevi State Level Kabaddi Tournament', 'Titwala Ganpati Trust State Level Tournament', 'Kalyan Dombivali Mayor Cup' and 'Ankur Krida Mandal State Level Tournament'.

*Our proud Kabaddi team members with MD & CEO and Executive Directors.*

"BITCOIN is an artificially created currency which can be deciphered by codes. It is so to say another form of internet. The codes are specially created for one single particular individual by a software tool called Meta Mask. In the lingo of cryptography, they are known as the seed phrase. The codes unlock the digital bank account or an online indentity. Obviously one needs to keep the seed phrase secure.

The concept of BITCOIN came up in the year 2008. A mysterious programmer or a group of programmers going by the name Satoshi Nakamoto circulated a paper on a cryptography mailing list. The paper was called "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," and in it, Nakamoto outlined an ingenious system for a digital currency that did not require a centralised trusted authority to verify the transactions.

The Bitcoin has increased in value by nearly 100,000 percent over the past five years, making a fortune for its early investors. It has two key features viz:

1. Bitcoin has offered a kind of proof that it is possible to create a secure database-the block chain-scattered across hundreds or thousands of computers, with no single authority controlling and verifying the authority of the area.

2. Nakamoto designed Bitcoin so that the work of maintaining that distributed ledger was itself rewarded with small, increasingly scarce Bitcoin payments. If one dedicates half of his computer's processing cycles to helping the Bitcoin network get its math right -and thus fend off the hackers and scamster he is entitled to receive a small sliver of the currency. The process has come to be called "mining." This is an incentive for making use of Bitcoin.

One can call Bitcoin as a token currency. Bitcoin is now a nine year old multi billion dollar bug bounty. Seeing the success of Bitcoin other cryptocurrencies like Ethereum have also come up. Ethereum is a system proposed by Vitlik Buterin. The Bitcoin been endorsed by celebrities like D J Khaled, Paris Hilton and Floyd Mayweather and many many are in the line with their pockets full of dollars. It is believed that even our megastar Amitabh Bachan is owning a huge lot of Bitcoins. A few days back one Bitcoin had even reached the value of as high as USD 2000."

*N P S Sohal*
*Rtd. AGM*

The annual meeting of the Union Bank Retirees Welfare Association was held at Mumbai on 10.02.2018. Shri V.H. Kamat and Shri Vivek Mhatre, both Ex-Genaral Managers, were Chief Guests for the meeting. As a special honor and recognition to Super Seniors (members completed 75 years of age), the Association felicitated 34 such members this year by offering them a well designed-name printed memento, Shawl, Bouquet and coconut.

# Shri R·N·Joshi
## The Mystical Artist

Shri Ramesh Joshi, retired Chief Manager (HR), C.O., Mumbai is leading a busy yet satisfied life even after retirement pursuing his 'first love' - painting. Though M.com (M S University), LLB (special), Diploma in Labour Practice and PG in Industrial Relations & Personnel Management adorn his academic career, he could not get a tag of a professional degree in Fine Arts. Dedicating some quality time from his busy professional banker's life over the years, he pursued his passion with great enthusiasm and grit. This self-taught visual artist then completed a professional course of paintings from Mudra School of Fine Arts, Baroda in 2016-17. His creations displayed at the exhibitions, mainly related to life psychology, spirituality and nature drawn on white paper or canvass of varied sizes with eye-catching acrylic and water colours are really a visual treat for the art lovers. His 90+ unique creations are displayed at painting exhibitions held at Air Port Gallery, Baroda; Faculty of Fine Arts, M S University, Baroda; Ravi Shankar Rawal Art Gallery, Ahmedabad; Akriti Art Gallery, Bhilwada, Rajasthan; P N Gadgil Art Gallery, Baroda and Group Show of Astitva, Baroda. Very true to the verse "Retired But Not Tired", he has consolidated his 2nd innings as an established divine artist.

**'Union Dhara' wishes him all the very best in his creative endeavours!**

## कार्टून कोना : एनपीए

*आलोक भार्गव, नई दिल्ली*

# Publication of Photographs of Defaulters in the Press

In the case of M.R. Motor Company Vs. Federal Bank [MANU/TN/3734/2016], the Division Bench of Madras High Court had approved the views expressed in the above case. In the case of D.J.Exim (India) Pvt.Ltd. Vs. State Bank of India [(2015)1CompLJ138(Bom), the Bombay High Court permitted publishing of photographs of Defaulters holding that there was no legal bar which expressly prohibits a bank from publication of photographs and therefore the action of the bank in publishing the photographs cannot be held to be ultra-vires the Constitution of India. Chhattisgarh, Delhi and Gujarat High Courts had also upheld publishing photographs of the Defaulters.

We come across in the Press that some of the Banks publish the photographs of the defaulters. (Default means non-payment of a loan availed by a borrower). The issue of publication of photographs was subject matter of challenge as to its legality and constitutionality before various High Courts.

In the case of Ku.Archana Chauhan Vs. State Bank of India [AIR 2007 MP 45], the Madhya Pradesh High Court upheld the action of the Bank to publish photographs of the defaulters.

Similarly, in the case of K.J. Doraisamy Vs. State Bank of India [(2007)136Comp Cas568(Mad)], Madras High Court permitted publishing photographs of the defaulters observing "If borrowers could find newer and newer methods to avoid repayment of the loans, the Banks are also entitled to invent novel methods to recover their dues".

In the case of M.R.Motor Company Vs. Federal Bank [MANU/TN/3734/2016], the Division Bench of Madras High Court had approved the views expressed in the above case.

Whereas, Calcutta High Court restrained the Bank from publishing the photographs of the defaulters in the case of Ujjal Kumar Vs. State Bank of India (IV(2013 ) BC 200CAL) and held the same was impermissible under the law. However, in the intra-court appeal filed by the Bank, the Division Bench of Calcutta High Court allowed publication of Photographs if the same is done in accordance with the guidelines issued by the RBI and held as under:

"From the above discussion and information, it is very clear so far as the Act and the rules, there is neither positive direction nor negative indication so far as publication of photographs. Definitely Rule 8 is intended to alert the public that the property is encumbered and one should know such encumbrance if anyone intends to deal with such property. Correspondence between the Indian Bank Association to RBI and RBI to the Chairman, State Bank of India in 2007 and the guidelines issued by RBI as updated on 01.7.2015 clearly indicate how and under what circumstances a borrower could be categorized as a willful defaulter and how the information has to be disseminated to the credit information companies. This clarifies the position that as a matter of routine procedure, one should not resort to publication of photographs of defaulters unless and until there are special circumstances where the borrower with malafide intention is committing any of the acts envisaged in the guidelines of RBI which would categorize him as a willful defaulter. In those circumstances the authority can act for public good/public interest for good reasons by publication of photographs, names and addresses of defaulting borrower(s)/guarantor(s). If publication of

photographs is otherwise implemented as a routine, there is bound to be serious impact on economy because if a genuine borrower becomes defaulter for various reasons other than the reasons to treat him as **"willful defaulter"** in terms of guidelines of RBI, such genuine defaulter would face a situation where no one would come forward to assist him to come out of the financial crisis. There should not be publication of photograph before proceeding with further course of action under SARFAESI Act only with a view to pressurize the defaulter/guarantor to repay the loan. In other words it would amount to undue influence or pressure coming in the way of rights of the borrower attracting Article 21A of the Constitution of the India **i.e. Right to live with dignity."**

## So, let us understand who is a "Willful Defaulter" :

A scheme was framed by RBI with effect from 1st April, 1999 under which the banks were required to submit to RBI the details of the willful defaulters of ₹ 25 lakhs and above. As per the consolidated Master Circular no. DBR.No.CID.BC.22/20.16.003/2015-16 dated July 1, 2015, issued by RBI, a "Willful Default" deemed to have occurred if any of the following events are noted :

a. The unit has defaulted in meeting its payment / repayment obligations to the lender even when it has the capacity to honour the said obligations.

b. The unit has defaulted in meeting its payment / repayment obligations to the lender and has not utilised the finance from the lender for the specific purposes for which finance was availed of but has diverted the funds for other purposes.

c. The unit has defaulted in meeting its payment / repayment obligations to the lender and has siphoned off the funds so that the funds have not been utilised for the specific purpose for which finance was availed of, nor are the funds available with the unit in the form of other assets.

d. The unit has defaulted in meeting its payment / repayment obligations to the lender and has also disposed off or removed the movable fixed assets or immovable property given for the purpose of securing a term loan without the knowledge of the bank / lender.

**(The term 'unit' includes individuals, juristic persons and all other forms of business enterprises, whether incorporated or not)**

RBI provided the mechanism to identify Willful Defaulters and also prescribed, inter alia, the following penal measures to be initiated by the Banks against such Willful Defaulters :

a. No additional facilities should be granted by any bank to the listed willful defaulters. In addition, such companies (including their entrepreneurs / promoters) where banks have identified siphoning / diversion of funds, misrepresentation, falsification of accounts and fraudulent transactions should be debarred from institutional finance from the scheduled commercial banks, Financial Institutions, NBFCs, for floating new ventures for a period of 5 years from the date of removal of their name from the list of willful defaulters as published/disseminated by RBI/CICs.

A covenant in the loan agreements should be incorporated by the banks to the effect that the borrowing company should not induct on its board a person whose name appears in the list of Willful Defaulters and that in case, such a person is found to be on its board, it would take expeditious and effective steps for removal of the person from its board.

Banks have also been mandated to submit the list of suit-filed accounts and non suit filed accounts of Willful defaulters of ₹25 lakh and above on a monthly or more frequent basis to all the Credit Information Companies like CIBIL. These measures are not strictly recovery measures but deterrent against default and to choke flow of finance to the willful Defaulters which may compel them to pay up their dues to the Banks. Further, various provisions of Companies Act and SEBI regulations also bar the Companies which have defaulted in repayment of loans to the Banks from accessing the Capital Market.

Thereafter, in the case of Metsil Exports Private Ltd. and Ors.Vs. Punjab National Bank, the Bank had published Demand Notice under Section 13(2) to the Company and its 3 Directors and also published photographs of the said three directors. The Company had challenged the action of the Bank. The Calcutta High Court held that the Bank was not entitled to publish photographs of the borrowers and directed the Bank to publish an apology in the same newspapers (Ananda Bazar Patrika and The Times of India) in which the photographs of the borrowers were published expressing regret for having published the photograph of the second petitioner, within 30 days from date.

In the case of State Bank of India Vs.Lalsangbera [AIR 2015Gau67], the Guwahati High Court held that a Bank cannot publish the photograph of the defaulters as being violation of the loan agreement entered into by the borrower with the Bank.

Similarly, the Kerala High Court, in the case of Venu, P.R. Vs. State Bank of India [MANU/KE/0123/2013], had also restrained the Bank from publishing the photographs of the defaulters by observing as under :

"The practice of exhibiting a photograph of a person and shaming him in public for the sin of being in an impecunious condition cannot be encouraged in a civilized society like ours".

It is noted by the Madras High Court, in the case of M.R.Motors (cited supra), that the Supreme Court did not entertain the Special Leave Petition filed against Bombay High Court Judgment which indicated that a Bank may publish photographs of the "Willful Defaulters" in the press and/or on the websites of the Banks.

To sum up, there is no legal bar to publish the photographs of "Willful Defaulters". But, the law on the issue of publication of Photographs of Defaulters, who are not declared as "Wilful Defaulters" is yet to be settled as there is divergence of views of High Courts.

***Hareesh Kumar***
*RO, Kolkata*

# 'दार्जिलिंग'

## पहाड़ों की रानी

कुदरत के कई करिश्मों में से एक दार्जिलिंग – 'पहाड़ों की रानी' जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है. दिलकश नज़ारे, हसीन वादियां, शरीर को छूती मद–मस्त ठंडी हवाएँ, ऊंचे–ऊंचे खूबसूरत वृक्ष, मन को अपने बस में करने वाली फूलों की खुशबू, बर्फीली पहाड़ियां, मुझे कभी उन लम्हों को भूलने नहीं देंगी जो मैंने दार्जिलिंग में बिताएँ हैं. सफ़ेद बर्फ से ढकी यहाँ की पहाड़ियाँ ऐसी दिखती हैं मानों चाँदी की चादर ओढ़े हुए हैं और सुबह के सूर्य की वो लालिमा उन पर्वतों पर पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है कि मानो स्वर्ग में आ गए हों और इससे अधिक खूबसूरत दिलकश नज़ारा कुछ हो ही नहीं सकता. इन खूबसूरत दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है कि बस इन्हें अपनी आँखों में कैद कर लें. दार्जीलिंग चाय के बागानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है. यकीनन पहाड़ों की चोटी पर विराजमान दार्जिलिंग की वो सुखद अनुभूति एवं प्रकृति के इतने करीब बिताए वे लम्हें जीवन भर मुझे याद रहेंगे. यहां के इस मन–मुग्ध वातावरण को देख मुझे श्री शिशिर मधुकर की एक कविता याद आ गई –

**''हमें तो जब भी कोई फूल नज़र आया है,**
**उसके रूप की कशिश ने हमें लुभाया है,**
**जो तारीफ़ न करें कुदरती करिश्मों की,**
**क्यों हमने फिर मानव का जन्म पाया है.''**

***प्रीती साव***
*कें.का., मुंबई*

UniOne Diary

# Mother EARTH

## Visit to 'Apna Ghar'







## Visit to 'Shraddhanand Mahilashram'

Donated ₹ 75,000/- to 'Hindu Women's Welfare Society'



Imagine you live in a house since your birth. It is a good, old house passed down to you by your ancestors and as natural progression takes place, this house is centuries old and falling apart. Now what will you do? Rebuild, Abandon or Repair? Rebuilding is not possible as it is very expensive and abandoning is difficult, as its having high sentimental value. The next most practical solution would be to repair your current house and make sure it stays like that for future generations.

What exactly are we doing with our Mother Earth? Without caring for the consequences of our actions we are living on this Earth. We are still using fossil fuels to run our cars, factories and businesses, we are using oceans and rivers as dumping grounds and trash cans, fresh water is embraced with chemicals from factories which is causing irreversible health issues. Over fertilization of farms is giving rise to soil pollution. Trees and forest cover is reducing to give way to new cities and towns. Industrialization and urbanization have intensified environmental health risks and pollution. Though our Holy River Ganga is having emotional and religious value in our life, we polluted our own Ganga with chemicals, dead bodies, washing and cleaning our dirt in it that Government has to start a project to clean this river.

Why are we waiting for governments to make rules for us so that we act accordingly? Let each one of us become aware and consciously avoid polluting the rivers, oceans, fresh water, atmosphere, etc. We owe the preservation of Mother Earth to the future generations as we have only one Earth. We should start it ourselves and pledge to be the first one to start it.

*B. Sathyavathi Rai*
*Chair Person,*
*UniOne Foundation*

## Umbrella Distribution

## Visit to MBA Foundation

₹ 75000 donated by UniOne Foundation

## UniOne Foundation Day Celebrations

# Decoding The Code

The Insolvency and Bankruptcy Code 2016 ("the Code") was passed by the parliament in the month of May 2016, later on notified on November 01, 2016. The Code aims to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnerships firms and individuals in a time bound manner for maximization of the value of the assets of such persons, to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interest of all stake holders including alteration in the order of priority of payment of Government dues and to establish an Insolvency and Bankruptcy Code of India and for matter connected therewith or incidental thereto. It also amends the laws relating to insolvency resolution of companies and limited liability entities, partnerships and individuals which are at present contained in various enactments. The main focus on a resolution in a time bound manner for maximization of value of assets. The code lays down framework for resolution through either revival or winding up business. The code is also aimed to establish a process on the principal that insolvency resolution must be commercially and professionally driven with minimal intervention of courts. The code repeals the Presidency Town Insolvency Act 1909 and Provincial Insolvency Act 1920 as well as amends 11 legislations including Indian Partnership Act, 1932, the Companies Act 2013, Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, Limited Liability Partnership Act 2008, Sick Industrial Companies (Special Provisions) Repeal Act 2003.

Traditionally, banks have preferred to restructure the debt of stressed borrowers through the CDR, SDR, 5:25, S4A or JLF mechanisms. While the CDR mechanism was used extensively, the objective seems to have been to provide temporary relief to the borrower rather than make active efforts to revive businesses. CDRs have met with limited success in reviving stressed assets due to poor evaluation of business viability and the lack of effective monitoring.

Until the Insolvency and Bankruptcy Code, there was no single legislation that governed corporate insolvency and bankruptcy proceedings in India. Lenders had limited muscle when faced with default and promoters stayed in control. Only one element of a bankruptcy framework has been put into place to a limited extent.

The Code makes a clear distinction between insolvency and bankruptcy — the former is a short-term inability to meet liabilities during the normal course of business, while the latter is a longer term view on the business. As all businesses cannot succeed, it is perfectly normal for some businesses to fail, making it important to emphasize on corrective action.

The Code ensures certainty in the process, including what constitutes insolvency, the processes to be followed to resolve the insolvency, and the process to resolve bankruptcy once it has been determined. Such a framework can incentivize all stakeholders to behave rationally in negotiations toward the determination of viability, or in bankruptcy resolution. In turn, this will result in shorter recovery timeframes and better recovery and greater certainty on lenders' rights, leading to the development of a robust.

### What does the Code Intend to Change?

- Create a single insolvency and bankruptcy framework. Set up a clear and unambiguous process to be followed by all stake holders in a time bound manner.
- Provide a commercial solution to a commercial issue.
- Allow genuine business failures a second chance.
- Clear and unambiguous process to be followed by all stakeholders in a time-bound manner

### What does it change for the Lenders?

- Right to control the borrower upon default and maximize recovery.
- Option to initiate the process even if the default is in respect of the debt of another lender.
- Need for more robust monitoring systems to enable judicious exercise of power.
- Lack of lender consensus on resolution plan can push the borrower into liquidation.

### What does it change for the Borrowers?

- Any creditor can file an insolvency petition on a default of INR 1 lac or above.
- Insolvency Professional to take over the management and operation of the borrower during the Corporate Insolvency and Resolution Process (CIRP).
- Borrowers to stay on liquidity – ensure tight cash flow forecasting and monitoring to stay current on payment.
- Need to be proactive in identifying issues, communicating with lenders and developing/implementing turn-around plan.
- In case of fraudulent diversion of assets, personal contribution can be sought; imprisonment possible.

## Objective of the Code

The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 has been formed with the following objectives:

- To promote entrepreneurship.
- To make credit available.
- To balance the interest of all stakeholders by consolidating and amending the existing laws relating to insolvency and bankruptcy.
- To reduce the time of resolution for maximizing the value of assets.

The key theme of the Code is to consolidate all laws relating to insolvency of companies, Limited Liability Partnership (LLP), Partnership firms and individuals, presently governed by multiple laws, into a single legislation. The SICA Repeal Act came into force in December 2016, resulting abolishment of BIFR and AAIFR. Several provisions of the Code have been amended during last few months to streamline its operations effectively.

### Legal Structure

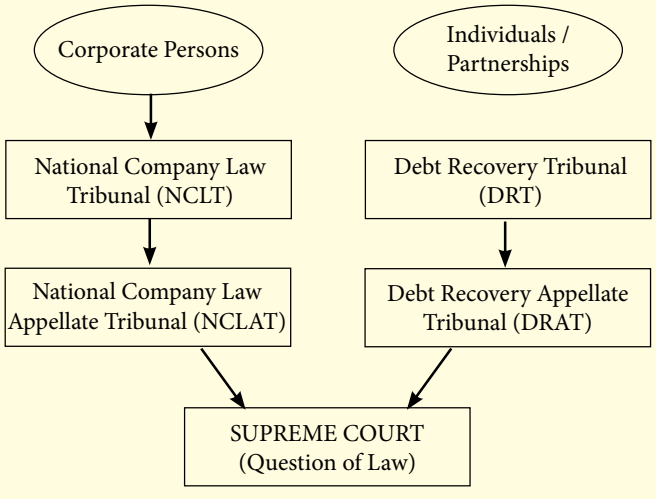


### Key Authorities / Intermediaries

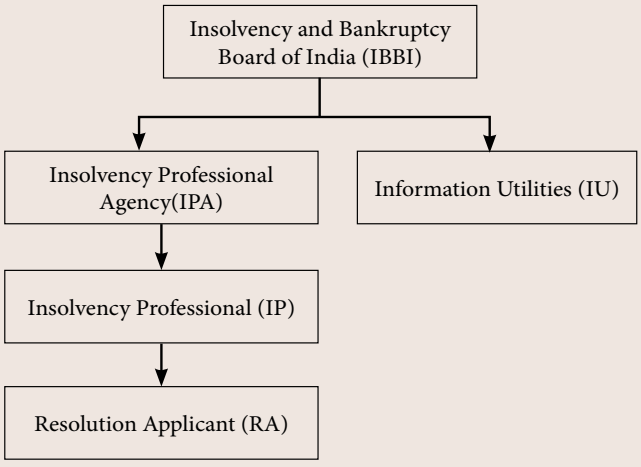


## Bankruptcy for Individuals and Partnership Firms

There are two distinct resolution processes namely the Fresh Start and Insolvency Resolution for individual and partnership firms.

**Fresh Start:**

The Code allows individual debtors, who are unable to pay the debt, to start afresh. As per section 80 of the Code, a debtor, who is unable to pay his debt and fulfils the following conditions, shall be eligible to make application for a fresh start for discharge of his qualifying debt.

- Gross annual income – not more than ₹ 60,000/- ;
- The aggregate value of the asset – not more than ₹ 20,000/- ;
- The aggregate value of the qualifying debt – not more than ₹ 35,000/- ;
- He is not an un-discharged bankrupt and does not own a dwelling unit.

**Insolvency Resolution:**

- Insolvency resolution process shall be initiated either by the debtor or creditor. In the process, both parties shall negotiate and shall arrive at a repayment plan under the supervision of a resolution professional. If the resolution plan fails or cannot be implemented, the bankruptcy of an individual shall be initiated.

## Institutional Infrastructure

**The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 has introduced the following entities for successful implementation and smooth function.**

| Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | Adjudicating Authority (AA) | Insolvency Professional Agencies (IPA) | Insolvency Professionals (IP) | Information Utilities (UI) |
|---|---|---|---|---|
| -Regulatory authority of IPA, IP and IU<br>-Empowered to make regulations in respect of all the process, appointments, procedures, investigation, monitoring, etc. | -The AA will exercise jurisdiction during the Insolvency and liquidation process.<br>-For corporate, LLPs – NCLT is AA<br>-For individuals and partnerships – DRT is AA | -IPA are those specialised bodies/ agencies that will be entrusted with the as of registration and governance of IPs. | -IPs are appointed by IPA, who would take on the roles of Resolution Professional/ Liquidator/Bankruptcy Trustee in the process of different entities. | -An IU is an agency that is in charge of collecting, collating and disseminating financial information. |

## Liquidation and Winding up (Distribution of Asseets)

**Liquidation of Corporate Debtor**

- Order of liquidation:
- Resolution plan is not received by AA submitted within the prescribed timeline
- Rejection of resolution plan by AA
- Upon decision by CoC to liquidate
- Contravention of approved resolution plan – on application by person whose interests are prejudicially affected.
- Liquidation process to be completed within two years unless extended by NCLT
- No suit or other legal proceeding by or against the corporate debtor, except suit or legal proceedings by liquidator with the prior approval of the NCLT.
- Order of Liquidation – Notice of Discharge to the officers, employees and workmen of the Corporate Debtor (Not applicable if liquidator continues the business of the corporate debtor during the liquidation process)

## What IBC Offers to Lenders?

- Creditors in control as almost entire decision making with the lenders
- Time bound and quick solution for stressed and NPA accounts
- Change of management possible
- Brings financial lenders to a platform – enabling quick decision making and arriving at consensus quickly
- Prepare and examine resolution plan by professionals appointed by creditors ensuring fearless decision making
- Final approval by NCLT (a legal entity) – so less stress/fear of accountability/vigilance
- Fair chance to viable and sustainable units for time bound revival
- In case of unviable accounts, faster, transparent and smooth liquidation process
- Legal sanctity of NCLT and hence legal protection
- Clear and fair distribution of funds. Government dues to get last priority
- Protection of assets of secured borrowers with maximisation of realisation
- Supervision and control post sanction of plan

**10 Major Changes in IBC (Amendment) Ordinance Effective from 06.06.2018**

1. Home buyers are treated as financial creditors.
2. MSME with a special dispensation – one major benefit it does not disqualify the promoters to bid for his enterprise under CIRP, if not wilful defaulter.
3. Withdrawal of CIRP permissible only with the approval of the CoC with 90% of the voting share.
4. Furthermore, such withdrawal will only be permissible before publication of notice of EOI.
5. The voting threshold has been brought down to 66% from 75% for all major decisions.
6. Further, in order to facilitate the corporate debtor to continue as a going concern during the CIRP, the voting threshold for routine decisions has been reduced to 51%.
7. The Resolution Applicant shall submit an affidavit certifying its eligibility to bid. This places the primary onus on the resolution applicant to certify its eligibility.
8. Minimum one year grace period for the successful resolution applicant to fulfil various statutory obligations.
9. Non applicability of moratorium period to enforcement of guarantee of the Corporate Debtor.
10. Special resolution for corporate debtors to themselves trigger insolvency.

**Liquidation and distribution of recovery proceeds**

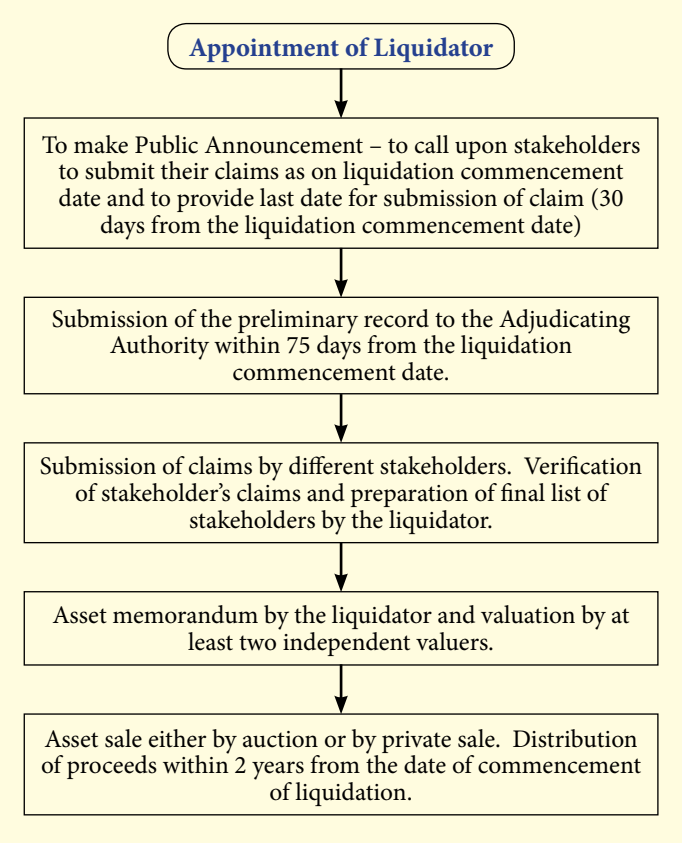


## Liquidation and Distribution of Assets

**Section 53 of the Code deals with distribution of assets from the liquidation estate in the manner of following waterfall mechanism.**

PROCEEDURE AND VARIOUS ACTIVITIES OF CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS AND LIQUIDATION PROCESS.

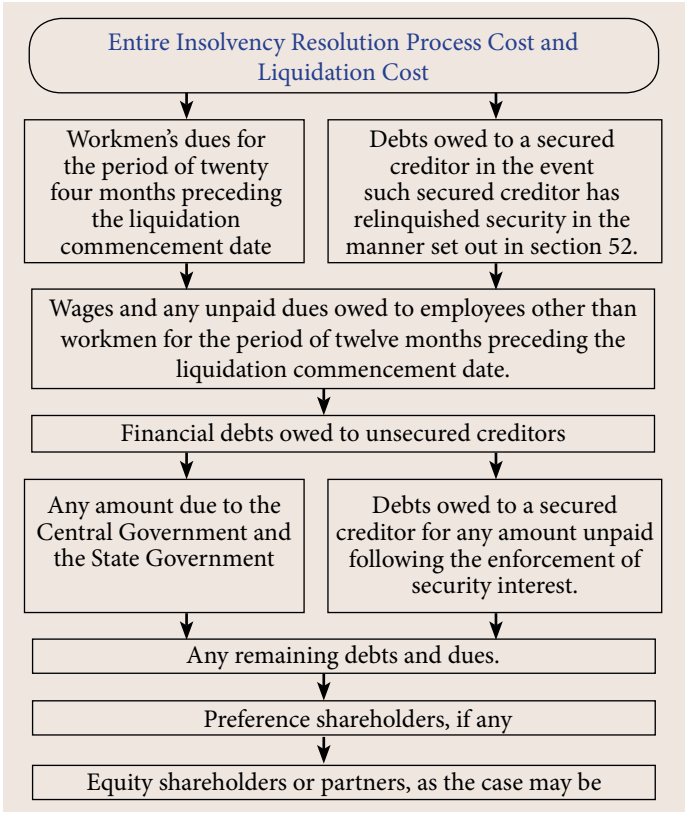


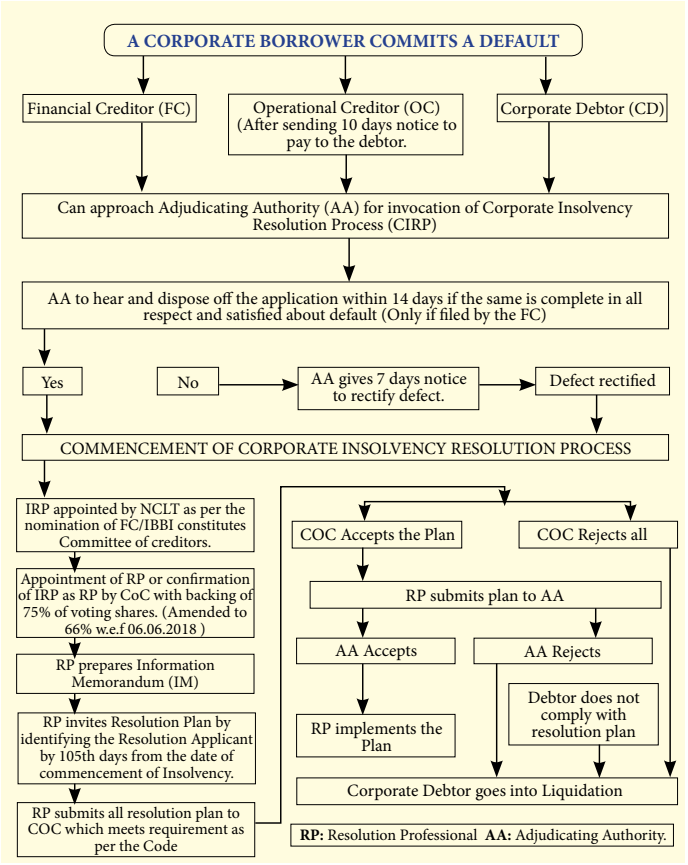

*S.K. Patnaik*
*CRD, CO.*

# डिमांड ड्राफ्ट के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाना

डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के कारण उत्पन्न होने वाली चिंताओं और धनशोधन हेतु इसके संभावित दुरुपयोग को दूर करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर जारी मास्टर निर्देश की धारा 66 को संशोधित किया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र क्र. डीबीआर.एएमएल. बीसी.सं.210/14.01.001/2018–19 दिनांक 12 जुलाई 2018 के द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया है कि डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि के मुख्यपृष्ठ पर क्रेता/ग्राहक का नाम अनिवार्य रूप से लिखा जाए. ये अनुदेश 15 सितंबर 2018 को या उसके बाद जारी लिखतों के लिए प्रभावी होंगे.

**(संदर्भ :– सूचना परिपत्र क्र.4381–2018 दिनांक 17.07.2018)**

*सुधीर प्रसाद*
*कें.का., मुम्बई*

# SARFAESI ACT

## (THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002)

*"An act to regulate securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest and to provide for a central database or security interests created on property rights, and for matters connected therewith or incidental thereto."*

### 1. GENESIS

1.1. Importance of financial sector in achieving overall progress of the country cannot be denied. Financial sector has been the key driver in the success of economy. With the introduction of prudential norms and accounting practices, it was felt that the banking industry in India does not have a level playing field when it comes to realization of its assets, mainly about taking possession of the securities and selling it. Immovable properties as securities are governed by Transfer of Property Act, under which, Banks are required to obtain a decree through Court and bring the mortgaged securities to sale. This resulted in slow pace of recovery and increasing trend in NPAs which was harmful to the health of the banking system.

1.2. Though there already existed Debt Recovery Tribunals (DRTs) established under the Recovery of Debts [and Bankruptcy] Act, 1993 to take care of bank's debts (above Rs. 10 lacs), the need was felt to have one more legislation to strengthen the banks. Narasimhan Committee I & II and Andhyarujjana Committee also suggested enactment of a new legislation for securitization and empowering Banks and Financial Institutions to take possession of the securities and to sell them without intervention of Court. Accordingly SARFAESIA Act was passed by Parliament and received assent of the President on 17th December, 2002. Subsequently the said Act has undergone two major amendments viz Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Act, 2004 (Act 30 of 2004), Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Act, 2012 (Act 1 of 2013) and The Enforcement of Security interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act,2016 (44 of 2016 ).

### 2. OBJECTIVE

2.1 The Act provides the legal framework for securitization activities in India.

2.2 It gives the procedures for the transfer of NPAs to asset reconstruction companies for the reconstruction the assets.

2.3 The Act enforces the security interest without court's intervention.

2.4 The Act gives powers to banks and financial instruction, debenture trustee or Asset Reconstruction Company to take over immoveable property that is hypothecated or charged to enforce the recovery of debt.

### 3. APPLICABITLY OF SARFAESI ACT

- This act is applicable to whole of India including the state of J&K
- To all banking companies which include SBI, its subsidiaries, all Private and Public Sector Banks, Foreign Banks and CO-Operative Banks NOW ALSO TO MULTI-STATE CO-OP Banks (SARFAESI Amendment 2012).

Note: As per the Decision of the Supreme Court in Transcore V/s Union of India, bank can initiate SARFAESIA and DRT Action simultaneously.

### 4. CHAPTER–III ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST (SECTION 13-19)

Section 13 to 19 Deal with provisions relating to enforcement of security interest and power of lender to enforce security interest.

#### CIRCUMSTANCES/CONDITIONS WHEN SEC.13 CAN BE INVOKED

- The account should be a secured debt
- The account should be classified as NPA account.
- Borrower should have committed default in payment of the secured debt or installment thereof.
- Bank issued a notice in writing to the borrower calling upon him to discharge all his liabilities to the Bank and borrower failed to discharge the dues within a period of sixty days from the date of notice and the latter has failed to pay the same.
- The Bank's claim against the borrower shall be within the limitation period as on the date of issuance of the notice.
- The documents creating the security shall be valid and enforceable under law.
- The security intended to be acquired is free from any litigation and should be easily marketable.

#### THE PROVISION OF THIS ACT SHALL NOT APPLY TO THE FOLLOWING

- Lien on good, money or security by way of pledge of movables.

- Aircraft
- Shipping vessel
- Conditional sale or hire purchase or lease
- Rights of unpaid seller
- Goods/properties exempted under Sec. 60 of Civil Procedure Code such as wearing apparels, vessels, tools of artisan, books of a/c, part of salary, etc.
- Agriculture Land.
- The amount due is less than 20% of the principal amount and interest there on.
- Outstanding in the account should be more than ₹ 1 Lac.

## 5. PROCEDURE- HOW ACTION UNDER SARFAESI ACT IS INITIATED?

To issue demand notice under Sec-13(2) of the Act to borrower and guarantor duly signed by Authorized Officer. The notice shall give details of the amount payable by the borrower and the secured assets intended to be enforced by the secured creditor in the event of non-payment of secured debts by the borrower.

### MODE OF SERVICE OF NOTICE

1. Personal delivery with acknowledgement.
2. Registered post or speed post or courier services or fax or E-mail service.
3. When more than one borrower the notice should be served on each of them.
4. Hand delivery under the acknowledgement.
5. If borrower avoids to receive notices, it can be served by:

- affixing a copy of the notice on outer door of the house (Endorsement to such effect witnessed by 2 independent witnesses).
- By publishing in two daily news papers (one in local language).

*If the borrower or guarantor raises any objection or makes representation after receipt of the notice, the secured creditor must reply the same within 15 days from the receipt of such objection or representation failing which the entire SARFAESIA action shall stand abetted. Hence it should be ensured that reply to the representation of borrower/guarantor should be given within the stipulated period.*

If the borrower fails to pay the dues within 60 days from the receipt of notice, the Bank may take recourse to one or more of the following measures:

- Take possession of the security.
- Sale or lease or assign the right over the security.
- Manage the same or appoint any person to manage the same.

**PROCEDURE FOR TAKING POSSESSION:**

### MOVEABLE ASSETS

Normally the movable assets are stocks in trade, work in progress, raw material, finished goods, semi finished goods, parts, tools, stores, movable machinery, book debts, receivables, etc. or as may be hypothecated to the bank. Before we proceed to take possession of the movable assets, the following matters require careful consideration:

1. Notice to take possession of secured assets should be issued to all borrower(s) and guarantor(s) fixing the date and time of taking possession.
2. A Panchanama has to be drawn at the time of taking possession of the assets and the same should be signed by the authorized officer and by two independent witnesses.
3. Detailed Inventory of all the moveable assets should be drawn and copy of the seized secured assets shall be delivered to the borrower or his authorized representative.
4. Secured assets shall be kept in the custody of authorized officer or in the custody of any other person authorized by him or any Manager appointed by him in this behalf. The seized assets shall be given care and custody in the same manner as the owner of such assets will give.
5. If the seized assets are subject to speedy or natural decay or the expenses of keeping such assets in custody is likely to exceed its value, the authorized officer may direct sale of such goods immediately so as to prevent loss due to decay after giving notice.

### IMMOVEABLE ASSETS

Bank might have taken any one or more immovable properties as security which could be residential flats, houses, open plots, factory land & buildings [commercial or factory], industrial galas, warehouses, plant & machinery permanently embedded to earth, etc. This has to be carefully evaluated before taking possession. The following aspects require to be looked into for taking possession of mortgaged immovable assets.

1. Notice to take possession of secured assets should be issued to the owner of the property i.e. borrower/guarantor fixing the date and time of taking possession.
2. A Panchanama and inventory of moveables, if any has to be drawn at the time of taking possession of the assets and the same should be signed by the Authorized Officer and by two independent witnesses. The copy of the same to be served to the borrower/guarantor.
3. After taking the physical possession of the property/ies, possession notice to be published in two leading newspapers within 7 days.

## 6. AMENDMENT TO SUB-SECTION 8 OF SECTION 13 w.e.f 1.9.2016

Where the amount of dues of the secured creditor together with all costs, charges and expenses incurred by him is tendered to the secured creditor **at any time before the date of publication of notice for public auction or inviting quotations or tender from public or private treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured assets —**

(i) the secured assets shall not be transferred by way of lease assignment or sale by the secured creditor; and

(ii) In case, any step has been taken by the secured creditor for transfer by way of lease or assignment or sale of the assets before tendering of such amount under this sub-section, no further step shall be taken by such secured creditor for transfer by way of lease or assignment or sale of such secured assets.

- **SALE OF MOVEABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES (RULES 8 AND 9)**

  The Authorized officer may sell the secured assets taken possession, in one or more lots by adopting any of the following methods to secure maximum sale price for the assets, to be so sold-

a) Obtaining quotations from parties dealing in the secured assets or otherwise interested in buying such assets; or

b) Inviting tenders from the public; or

c) Holding public auction including through e-auction mode; or

d) By private treaty

### PROCEDURE

1. Obtain valuation of the properties and fixe reserve price.
2. The Authorised officer shall serve to the borrower/guarantor a notice of thirty days for sale of the assets.
3. PROVIDED that if the sale of such secured assets is being effected by either inviting tenders from the public or by holding public auction, the secured

creditor shall cause a public notice in two leading newspapers, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality by setting out the terms of sale, which may include-

(a) details about the borrower and the secured creditor;

(b) description of secured assets to be sold with identification marks or numbers, if any, on them;

(c) reserve price, if any, and the time and manner of payment;

(d) time and place of public auction or the time after which sale by any other mode shall be completed;

(e) depositing earnest money as may be stipulated by the secured creditor;

(f) any other thing which the Authorised Officer considers it material for a purchaser to know in order to judge the nature and value of secured assets.

4. Provided further that if sale of property by any one of the methods specified in para no. 3, fails and the sale is required to be conducted again, the Authorised officer shall serve, affix and publish notice of sale of not less than fifteen days to the borrower for any subsequent sale[ Inserted by GSR.1046(E) dated 3.11.2016 w.e.f 4.11.2016].

5. Sale by any methods other than public auction or public tender, shall be on such terms as may be settled **between the secured creditors and the proposed purchaser.**

- **CONFIRMATION OF SALE AND DELIVERY OF POSSESSION OF THE PROPERTEIES:**

### MOVEABLE ASSETS

1. On receipt of the entire sale consideration amount from the Auction purchaser. Sale Certificate is issued.

### IMMOVEABLE ASSETS

1. On every sale of immovable property, the purchaser shall immediately, **i.e. on the same day or not later than next** working day, as the case may be, pay a deposit of twenty five per cent of the amount of the sale price, which is inclusive of earnest money deposited, if any, to the Authorised Officer conducting the sale and in default of such deposit, the property shall be sold again";

2. The Balance amount of purchase shall be payable on or before the fifteenth day of confirmation of sale of the immovable property or such extended period, **as may be agreed upon in writing between the purchaser and the secured creditor, in any case not exceeding three months shall be substituted.**

3. On receipt of the entire sale amount, sale certificate will be issued in favour of auction purchaser and sale deed will be executed.

4. In default of payment within the period mentioned in sub-rule(4), the deposit shall be forfeited **to the secured creditor** and the property shall be resold and the defaulting purchaser shall forfeit all claim to the property or any part of the sum for which it may be subsequently sold.

## 7. SECTION 14-POWER OF CMM/DM TO ASSIST SECURED CREDITOR IN TAKING POSSESSION

The essence and meaning of Section-14 of the Act is that a secured creditor may seek help and assistance of the CMM or the DM for the purpose of taking over of the possession of the secured asset or property, in case the mortgagor (borrower/guarantor) fails to handover peaceful possession of the secured assets.

- The CMM or DM may grant **assistance** to the secured creditor in taking possession of the secured asset **if a request in writing is made** to the CMM or DM within whose jurisdiction the secured asset is situated.
- The written request shall be accompanied by an affidavit duly affirmed by the Authorised Officer of the secured creditor affirming that the provisions of the SARFAESI Act and Rules have been complied with by the secured creditor.
- On being satisfied about the contents of the affidavit the CMM or DM shall pass necessary orders for the purpose of taking possession of secured assets.
- The CMM/DM may delegate the powers to a subordinate officer.
- CMM/DM may authorize the use of force for due compliance with the Act and Rules as necessary in the opinion of such CMM/DM.
- The order of the CMM/DM cannot be questioned in any Court of law or authority. However, the writ jurisdiction under S. 226 and 227 is not barred.
- Second proviso to S. 14(1) – The CMM/DM after being satisfied with the contents of the Affidavit shall pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured asset within a period of **thirty days** from the date of application.
- The insertion of a proviso after the second proviso- In circumstances beyond the control of the CMM/DM, the time period of thirty days may be extended to sixty days after recording of the reasons. No further extension beyond sixty days, in aggregate, is permissible.
- The aforesaid insertions have been made after taking into account the delayed disposal of the cases by the CMMs/DMs.
- The said insertions also take into account the ratio decidendi of the landmark judgement of the Supreme Court in *Harshad Govardhan Sondagar v International Assets Reconstruction Co. Ltd. & Ors7and Vishal N. Kalsaria v Bank of India & Ors.*
- *Section 17 – Any person (including borrower) aggrieved by any of the measures taken by secured creditor of authorised officer under Chapter 3, can file application alongwith such fee as may be prescribed to the Debt Recovery Tribunal having jurisdiction in the matter within 45 days from the date on which such measures had been taken.*

### Main features of the amendment to the SARFAESIA Act in 2016:-

Central Government has amended the SARFAESI Act in August 2016 to empower the Asset Reconstruction Companies to rejuvenate Debt Recovery Tribunals (DRTs) and to enhance the effectiveness of asset reconstruction under the new bankruptcy law. The amendment has given more regulatory powers to the RBI on the working of ARCs. It was also aimed to empower asset reconstruction and the functioning of DRTs in the context of the newly enacted bankruptcy law. As per the amendment the scope of the registry that contains the central database of all loans against properties given by all the lenders has been widened to include more information. DRTs will be the backbone of the bankruptcy code and deal with all insolvency proceedings involving individuals. The defaulter has to deposit 50% of the debt due before filing an appeal at a DRT. With the above amendments to SARFAESI Act and RDDBFI Act and with the assistance of Insolvency and Bankruptcy Code 2016, the banks are now in warpath to recover their dues to reduce the non-performing assets to a large extent. This will infuse the much needed funds to the banking system to boost the economy of the country.

***K. C. Chaudhary***
*Law Dept. CO.*

# RAKSHITH

## The 'Percussion' Wizard

KR RAKSHITH SHARMA receiving All India Radio NATIONAL AWARD at Thiruvanantapuram Palace from Dr. Omanakutty flanked by AIR Station Director.

KR RAKSHITH SHARMA with parents and sister Madhavi Sharma who is an upcoming Bharatanatyam Artist at Tirupati before NAADA NEERAJANAM CONCERT

K R RAKSHITH SHARMA in a performance

The Carnatic Music is considered as one of the oldest systems of music in the world. It has a very complex system that requires much thought, both artistically and technically. It is often said that the basic skill plus the hard work put in and a must regular practice grooms a person into a perfect artiste. The musical musings of **Master K.R. Rakshith Sharma** has proven this fact very true. This mrudangam & western drumming enthusiast son of Shri K.V.Ravi Shankar Sharma, SWO 'A', Vijaynagar Branch, Bangalore is a rare child artist to have blessed with a great degree of talent with a capacity to play more than ten percussion (rhythm) instruments like mrudangam, western classical drums, thavil, khanjeera, ghatam, konnakol, chande, dikki tarang, morsing,dol, etc. Stepping into the footsteps of his role model, Guru and father Shri K.V.Ravi Shankar Sharma, he was trained under Vidwan Kalaimamani Guruvayur Sri Dorai (world renowned veteran mrudangam maestro); Shri H.S. Sudhindra, Ganakala Shree Vidwan, Bangalore. He also leant western classical acoustic drums under Shri Sukumaran Babu.

This first year student of B.E. (Mechanical Engineering), had performed all over India with the prestigious Tal Vadya (percussion ensemble) Troupes in the recent past, namely 'Mookambika Talavadya' & 'Shruti Sindhura Academy of Music®' and had also performed for the prestigious series like 'Kalavantha', 'Ananya', 'Gayana Samaja', 'R K Srikanthan Memorial', etc. He had a rare honor of performing on mrudangam along with living legend of mrudangam Padmabhushan Sri Umayalapuram K. Sivaraman sir for a fund raising ticketed show. He is the youngest boy who has shown the extra-ordinary skill of being adept in both western classical Acoustic drumming with 8th Grade qualification - the highest level in India (at the age of 13) from Trinity College of Music, London, (UK) with Distinction & 'B' gradation in Indian - Carnatic Classical Music Percussion Mrudangam playing from All India Radio/ Doordarshan, Government of India. At the tender age of 8 years, he was invited by Remo® International (an American Western Percussion Instrument Manufacturing Company) for a practical demonstration of their instruments. This recorded visit is uploaded by the company on their official website & also in their You Tube Portal.

He had performed non-stop for 10 hours marathon Veena Concert with Veena Kesari Vidwan Prashanth Iyengar at Bangalore. He had played 'Chande', a Kerala Percussion instrument, for an overseas project by internationally renowned music artist and music director Mr. Amit Heri. He had played 'khanjeera', single handed drum, for a 'Gana Sudha' Sabha Concert at Hubli. He had performed thrice- for 'Pallavotsava' at Melkote on mrudangam and Thavil (Dolu) in 2010,2011 & 2012. He had performed for a concert organized by Department of Archeology at Sri Rangapatnam with Vidwan Prashanth Iyengar. He had been featured in 'Arunodaya Children's Music and Dance Festival' since 2006. He has accompanied many upcoming artists in live concerts on Thavil. He had participated in the reality show 'Bala Gandharva' and reached the finals in 2008 and also in reality show 'India Has Got Talent, Edition-IV, Mumbai' of the 'Colors TV Channel.

This apart, Rakshit has been a regular and prolific performer at many prestigious sabhas and stages. He has been appreciated by the eminent personalities in the field of World Percussion Kalaimamani Guruvayur Sri Dorai, Sangeetha Kalacharaya Neela Ramgopal, legendary Guru Karaikkudi Mani, Kalaimanani Sri Neyveli Santhanagopalan, Ganakalabhushana Tas Mani, Layakala & Ganakalabhushana veteran A.V. Anand and many other eminent personalities in the field of Indian Music.

Though Rakshith believes that winning prizes in competitions is not an end in itself, he had refrained from competing in local events from the age of 15 years. But prior to this, he had a long list of the prizes won viz. First prize at Junior level, Bangalore Gayana Samaja-2009-annual competitions; Second prize at the 50th National level Mrudangam competitions held at Hyderabad (he won in the age group of 18-25 years while he was just 12 years); won 'the Bala Pratibhe Award' conducted by Department of Kannada and Culture, Government of Karnataka for second place in 2011-12; First prize: Junior level - Percussive Arts Centre-2012; Second prize: Sub Junior level- Percussive Arts Centre-2008; Third prize: Junior level- Percussive Arts Centre-2009; First prize: Sub Junior level - Malleswaram Sangeetha Sabha-2008; Pratibhakankshi Award from Sri Rama Seva Mandali, Fort, Bangalore and many many more.

This young 'musical' soul aspires to excel at the global level and to spread the value of Indian Culture through music all over the world.

**'Union Dhara' wishes him all the Best in his future musical endeavors!! More power to his percussion skills!!!**

*Supriya Nadkarni*
*Union Dhara, C.O.*

# CREDIT APPRAISAL AND NPA MANAGEMENT

Credit appraisal means an assessment done by bank /financial institution prior to providing any funding / loan / project finance, in which it checks the economic, financial and technical viability of the proposed project. The assessment of various risks that can impact of repayment of loan or credit worthiness is termed credit appraisal. In other words it is the assessment whether the loan will be repaid or not.

Depending upon the purpose and quantum of loan, the appraisal process may be simple or elaborate. e.g. for personal loans, credit scoring based on income, existing liabilities and other parameters may suffice but in case of project finance, the process comprises of technical, marketing, financial, managerial appraisal.

Credit appraisal is a knack of adapting certain precautions at the time of new sanction or renewal or enhancement of an existing limit. Credit appraisal revolves around the credit investigation to determine the economic and business environment in which prospective borrower is placed.

The banks over the years have developed a scientific credit appraisal methodology which is being constantly revised in the light of different factors.

The process involves assessment of honesty and integrity of the borrower, standing of the borrower, business capacity and experience in their line of business, managerial competence and financial resources in relation to size of the project.

Now let us look into 5 simple steps of credit appraisal :

1. As a first step of appraisal, the work place of prospective borrower to be inspected by the manager. Manager should visit the factory or business place and residence of the borrower.
2. In addition to the unit inspection, bank manager needs to conduct credit investigation of the prospective borrower. Credit investigation means ascertaining the business reputation and credit worthiness of the borrower as well as the guarantor.
3. Information from external sources like meetings with the borrower, present and past employees of the borrower.
4. Analysis of financial statements for identifying the financial strength and weakness of a business establishment. It shows how the capital is contributed, how much of investment is identified with various accounts.
5. Along with appraisal of financial papers, the credit officer of the bank needs to examine the non-financial papers.

Credit appraisal plays a vital role for asset management of a bank. Proper credit appraisal is an opportunity to increase not only the volume of business but to optimize return of asset also, whereas due to poor credit appraisal bank gives credit to those who are not able to repay it back. To minimize the risk of default, there is a growing need for banks to strengthen their internal credit appraisal system that is credit assessment and risk management mechanism. At the same time, the bank should consider using external credit appraisals in consideration with their own assessment.

More than fifty per cent of infrastructure projects are stuck at various stages of implementations due to regulatory hurdles and sector specific bottlenecks leading to significant time and cost overrun.

There has been no dearth of policy pronouncements and re-engineering and process aimed at improving the investment climate for infrastructure projects.

**The five important variables or parameters of credit appraisals are:**

- Character
- Capital
- Capacity
- Conditions
- Collateral

**A comprehensive credit appraisal techniques involves following steps :**

- Customer identification
- Understanding the business of the borrower.
- Understanding the credit requirements.
- Selecting appropriate schemes / credit facility.
- Loan application.
- KYC.
- Generation of CIBIL of borrowers as well as guarantor.
- Check RBI defaulter list, MCA search.
- Visit the security as well as unit.
- Documents and information to be obtained from borrower.
- Obtaining due diligence report of the borrower.
- Obtaining due diligence report of the security.
- Credit risk rating –internal (and external if applicable).
- Confidential credit report from existing banks (if exists).
- Assessment of quantum (with repayment in case of TL).
- Appraisal note.
- Terms and conditions.
- Disbursement.

Defination of NPA – An asset, including leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. AN asset is termed as non performing when interest or instalment or both are overdue for more than 90 days in case of term loan and the account remains out of order for cash credit or overdraft accounts.

The origin of rising NPA in banking industry lies in the quality of managing credit risk by the banks.

### Reasons for an asset becoming NPA

An asset becomes non-performing due to:

(a) Inability of the borrower to repay.

(b) Unwillingness of the borrower to repay.

(c) Other cases (like loss due to natural calamity, death etc.)

### Types of NPA

Banks require to classifies their NPA into the following three categories based on the period for which specific asset has remained non performing as well as the reliability of the dues – Sub Standard Asset, Doubtful Asset and Loss Assets.

### Factors leading to Non-performing Assets

The origin of the problem of rising NPA lies in the quality of managing credit risk by the banks. The banking sector has been facing several problems of rising NPA.

### External factors

The major external factors which lead to increase in NPAs are namely ineffective statutory recovery procedure, wilful defaulters, natural calamities, industrial sickness, lack of demand, statutory obligations, change in Govt. policies, etc.

### Internal Factors

The major internal factors which lead to increase in NPAs are defective lending process or poor lending decision, improper SWOT analysis, poor credit approval system, absence of regular industrial visit, ineffective review process, etc.

The credit appraisal standards are the key to a healthy credit portfolio and consequent prevention of NPA. In the past, reckless lending by banks without appropriate credit appraisal of the project and its financial need has been one of the significant reasons for present NPAs. The viability assessment parameters need to be strengthened and independent techno-economic viability study of the project before bank proceeds to carry out lending. The bank needs to come out of the thought of 'one size fits all' and according to the project realistic repayment schedule to be stipulated. In many cases it has been observed that due to delay in completion and commencement of the projects, the repayment commences even before the facility has actually commenced commercial production which itself marks the beginning of stress in the account right from inception. Another important measure is to strengthen the monitoring of the credit extended by the banks which may include meaningful site inspections, timely audits, in depth analysis of financials, audit of receivables, etc. which may help the lender in detecting warning signals at an early stage.

Other important factors that lead to NPAs are loans sanctioned without proper due diligence and understanding the business of the customer and due to lack of knowledge or ignorance.

Therefore, it may be concluded that better credit appraisal, lesser the probability of default of the borrower and consequently non performing asset of the bank. As credit appraisal is the balanced combination of many steps/ procedures (like due diligence, proper assessment of requirement of the borrower, analysis of audited financials as well as future cash flow etc.), each steps/ procedure should be taken care of for prevention of fresh slippage of standard assets to non performing assets.

***Jhilmil Sen***
*R.O., Howrah*

## चरक का कोना

# गुणकारी कटेरी
## (कंटकारी)

कटेरी (कंटकारी) एक जंगली, कांटेदार पौधा होता है जो झाड़ी के रूप में जमीन पर चारों ओर फैला होता है. कटेरी चमकीले हरे रंग की होती हैं और इस पर पीले रंग के डेढ़ इंच लम्बे या इसमें कुछ छोटे कांटे होते हैं. इसके पत्ते 4 से 6 इंच लम्बे, कटे–फटे एवं किनारे सफेद धारीदार होते हैं जिसके नीचे कांटे होते हैं. पत्ते के बीच का शिरा सफेद रंग का होती है. इसके फूल नीले या बैंगनी रंग के, पुंकेसर पीले रंग के तथा फल गोल और हरे रंग के सफेद धारीदार होते हैं. पकने पर फल पीले रंग के हो जाते हैं. इसकी दो जातियां होती हैं – छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी. बसन्त के मौसम में कटेरी में फूल आते हैं और बरसात के मौसम में इसमें गोल–गोल फल लगते हैं. सर्दी के मौसम में ये फल पक जाते हैं. कटेरी के पौधे दिसम्बर–जनवरी में सूख जाते हैं. कांटे से भरे होने की वजह से इन्हें कोई जल्दी नहीं छूता.

### आईए, देखते हैं इसके अन्य प्रभावी गुण!

- कटेरी के फूलों के चूर्ण को (1/2 ग्राम से 1 ग्राम) शहद के साथ चटाने से बालकों की खांसी दूर होती है.
- जब छाती में कफ भरा हुआ हो, तब इसके 50–60 ग्राम काढ़े में 2 ग्राम भुनी हुई हींग और उतना ही सैंधा नमक मिलाकर पीने से दमे की बीमारी भी ठीक हो जाती है.
- गले की सूजन में इसके फलों का रस 10–20 मिलीलीटर की मात्रा में प्रयोग करने से गले की सूजन दूर होती है.
- नागरमोथा, पिप्पली, मुनक्का और बड़ी कटेरी के सूखे फल को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और यह 5 से 10 ग्राम की मात्रा में 1 चम्मच घी व 2 चम्मच शहद के साथ सुबह–शाम सेवन करने से टी.बी. की खांसी खत्म होती है.
- कटेरी की जड़ का 10 से 20 मिलीलीटर रस, 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर देने से वमन (उल्टी) बंद होता है.
- कटेरी और गिलोय बराबर मात्रा में लें और इसके डेढ़ किलो रस में एक किलो घी डालकर पकाएं. जब यह पकते–पकते केवल घी बच जाए, तब इसे उतार कर छान लें. इस घी को 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से मंदाग्नि और वात की खांसी मिटती है.
- कटेरी की जड़ को नींबू के रस में घिसकर आंखों में काजल की तरह लगाएं. इसे प्रतिदिन आंखों में लगाने से धुंध और जाला मिटता है.
- जबड़े में तेज दर्द पर कटेरी के बीजों को जलाकर उसका धुआं लें.

***अनीता भोबे***
*यूनियन धारा, कें.का.*

# बैंक की लाभप्रदता में वसूली की भूमिका

*विकास कार्य में धन मूल साधन है. उसे उपलब्ध करवाने में संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. बैंक नई विकासात्मक भूमिका निभाने के संदर्भ में मुख्य एजेंसियों में सबसे अधिक सक्रिय और महत्वपूर्ण हैं. आज बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य विकासात्मक एजेंसियों और संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करके देश का समग्र विकास सुनिश्चित करें.*

आपसी सहयोगी और मितव्ययिता की भावना से सहकारी ऋण समितियों का गठन किया जाना बीसवीं शताब्दी से ही प्रारंभ हुआ जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत रूप से कमजोर और पिछड़े लोगों के लिए संस्थागत वित्त पद्धति की शुरुआत हुई. अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस शताब्दी के मध्य में सहकारी ऋण पद्धति का पुनर्गठन किया गया. उसके बाद भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों ने सहकारिता आंदोलन की प्रगति में और अधिक सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास किए. फिर भी देश के सभी भागों में सहकारी ऋण की वृद्धि समान रूप से नहीं हुई. किसानों, पिछड़े वर्ग और ग्रामीण और अर्द्ध शहरी लोगों में ऋण की आवश्यकताएँ बढ़ी. अतः सन 1967 में वाणिज्य बैंकों पर भी सामाजिक नियंत्रण नीति लागू कर दी गयी और उन्हें कृषि ऋण नीति में सहभागी होने के लिए प्रेरित किया गया. सरकार बैंकों की ऋण नीति को नया आयाम देना चाहती थी. सरकार यह चाहती थी कि बैंकों का लाभ देश के कृषि व उससे सहबद्ध कार्यकलापों/उद्योगों, लघु, छोटे-छोटे कारोबार करने वालों को भी मिलता रहे. अतः सरकार ने अपने समाजीकरण की नीति के अंतर्गत 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया. 1969 के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उनके परिणामों से प्रभावित होकर सरकार ने 1980 में पुनः छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया. अब सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 हो गई जिनमें भारतीय स्टेट बैंक और उनके सहयोगी भी शामिल हैं. राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंक रूपी गंगा का रुख गावों व छोटे लोगों की ओर हो गया. बैंकों को ग्रामीण और गरीब वर्ग के लोगों को ऋण देने वाले अतिरिक्त परंतु सशक्त साधन के रूप में देखा जाने लगा और उसे बहु एजेंसी दृष्टिकोण का नाम दिया गया. उसमें सहकारी और बैंकिंग क्षेत्र,वित्तीय और गैर वित्तीय प्रकार की सहायता केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास निगम आदि से वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्राप्त होती है.

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का दृष्टिकोण बदला और ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाएँ खोली जाने लगी. सन 1969 में कुल 21940 बैंक शाखाएँ थी जिनमें 22.2% शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में थी.

शाखा विस्तार और विकास कार्यक्रमों में वृद्धि के साथ-साथ ऋण देने के कार्यक्रमों में भी वृद्धि होना स्वाभाविक था. जब बैंकों का कार्यक्षेत्र बढ़ा, व्यापारी वर्ग और शहरी लोगों के अतिरिक्त हितकारी भी जब बैंकों के पास आने लगे तो कुछ समस्याएँ भी स्वाभाविक रूप से आने लगीं. उनमें सबसे प्रमुख समस्या है संस्थागत ऋणों की चुकौती में चूक. संस्थागत ऋणों में बैंकों के ऋणों की मात्रा अधिक रही है जो सीधे हितकारियों को दिये गए हैं. अतः ऋणों की वसूली में बैंकों को ही विशेष भूमिका निभानी होगी जिसके लिए बैंकों के विकास के लिए बैंकों को प्रमुख भूमिका निभानी होगी अतः बैंकों की विकासात्मक भूमिका का मूल्यांकन आवश्यक हो गया है.

**विकास की अवधारणा:** विकास वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों और लाभान्वित हों. देश की विकास प्रक्रिया में बैंकों का योगदान बढ़ा है और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का विकास बैंकों के सहयोग के बिना संभव ही नहीं है इसलिए नगरोन्मुख बैंकों की विकास धारा को गावों की तरफ मोड़ा गया. गावों और उपेक्षित क्षेत्रों के विकास की ज़िम्मेदारी बैंकों को दी गई.

**ऋण प्रबंध:** ऋण के माध्यम से विकास की जो परिकल्पना की गई थी उसका उचित प्रबंध नहीं हो पाया. ऋण की सफलता के जो सामान्य सिद्धान्त थे उनका अनुसरण किए बिना ही बैंक ऋण देते रहे. अतः बैंक निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रख कर ऋण प्रदान करने के कार्य में गुणात्मक सुधार ला सकते हैं जिससे वसूली भी अच्छी होगी और साथ ही विकास की गति में भी सुधार आएगा.

**ऋण के उद्धेश्य :**

- हिताधिकारी के आर्थिक स्तर में सुधार.
- बैंक द्वारा दिये गए ऋण की समयानुसार चुकौती और
- भावी विकास की संभावना हेतु बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना.

**कोई ऋण किन-किन कारणों से अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल सकता है :-**

1. ऐसी परिसंपत्ति जिस पर व्याज 3 महीने या उससे अधिक समय से कालातीत (overdue) हो.
2. अदत्त – ब्याज सहित ऐसा मियादी ऋण जिसकी किस्त 3 या उससे अधिक माह से बकाया हो या जिस पर ब्याज की राशि 3 माह या उससे अधिक समय तक कालातीत हो.
3. ऐसा बिल जो 3 माह या उससे अधिक समय से कालातीत हो.
4. अल्पावधि ऋण/अग्रिम के रूप में अन्य चालू परिसंपत्तियों शीर्ष के अंतर्गत कर्ज से संबन्धित ब्याज या प्राप्त राशि से होने वाली आय की सुविधा 3 माह या उससे अधिक समय से कालातीत हो.
5. परिसंपत्तियों की बिक्री या दी गयी सेवाओं के लिए या किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति से संबन्धित कोई बकाया राशि जो 3 माह या उससे अधिक समय से कालातीत हो.
6. पट्टा किराया और किराया खरीद की किस्त जो निर्धारित माह या उससे अधिक समय से कालातीत हो गयी हो.

7. ऋणों, अग्रिमों, और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में (खरीदे और भुनाये गए बिलों सहित) एक ही ऋणकर्ता /लाभार्थी को उपलब्ध कराई गयी ऋण सुविधाओं के अंतर्गत शेष बकाया राशि जो उक्त ऋण सुविधाओं में से कोई एक अनर्जक परिसंपत्ति हो जाएं, बशर्ते कि पट्टा और किराया खरीद लेन देन के मामले में ऐसे प्रत्येक खातों को उसकी वसूली स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करे.
8. ऐसी मांग या सूचना ऋण जो मांग या सूचना की तारीख से 3 माह या उससे अधिक समय से कालातीत हो.

**किसी भी आस्ति के अनर्जक परिसंपत्ति में बदलने के उपरोक्त के अलावा भी निम्न कारण हो सकते हैं –**

1. **बाह्य कारण:**– किसी भी आस्ति के अनर्जक परिसंपत्ति में बदलने का मुख्य कारण होता है सर्वाधिक कमजोर प्रक्रियाएँ. इसके अलावा जो दूसरे महत्वपूर्ण घटक होते हैं, उनमें प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप, बाढ़ आदि, मांग की कमी, सरकारी नीतियों में बदलाव और इरादतन चूक प्रमुख हैं.
2. **आंतरिक कारण:**– दोषपूर्ण निवेश प्रक्रिया, उचित टेक्नॉलाजी का अभाव, कमजोर ऋण मूल्यांकन पद्धति अनर्जक परिसंपत्तियों के बढ़ने का प्रमुख आंतरिक कारण है.

**अनर्जक परिसंपत्तियों को घटाने के लिए किये जा सकने वाले उपाय/ योजनाएँ:–**

बैंक की जो आस्तियां अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में आ जाती हैं तो यह बैंक के आय को रोकने के साथ ही इसके साख पर भी प्रभाव डालती हैं. अनर्जक परिसंपत्ति दो–धारी तलवार की तरह है जो बैंक के लाभ को तो प्रभावित करती ही है, बैंक की रेटिंग को भी कम करती है और बैंक के पूंजीगत ढांचे को कमजोर करता है.

ऋण जितना अधिक समय तक बैंक के बहियों में रहेगा, उसके अनर्जक परिसंपत्तियों में बदलने की ज्यादा संभावनाएं हैं. यद्यपि अनर्जक परिसंपत्ति बनने से पूरी तरह रोका नहीं जा सकता किन्तु खातों में लगातार अनुश्रवण करके, और नए ऋण स्वीकृत करते समय, वार्षिक पुनरक्षित/नवीकरण, ऋण सीमा में वृद्धि के समय आवश्यक सावधानियाँ बरतें तो एनपीए को उसके न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है. यदि आवश्यक हो तो ऋण की किश्तों का पुनःनिर्धारण सीजीटीएमएसई को समझौता दावा के लिए आवेदन करके, ओटीएस समझौते द्वारा कोर्ट के बाहर समझौता द्वारा एनपीए को कम किया जा सकता है.

ऋण के अनुमोदन के पूर्व और पश्चात उचित अनुश्रवण द्वारा भी एनपीए को कम किया जा सकता है. किसी कंपनी के खाते में नकारात्मकता को देखने के लिए वित्तीय विवरण का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन किया जाए. साथ ही किसी भी कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करते समय उसके प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता की जांच करके भी एनपीए को कम किया जा सकता है. शुरुआती लक्षणों की पहचान करना, खाते के विवरणों की समीक्षा करना, ऋणी से बातचीत करना और ऋणी के सभी बैंक खातों का अवलोकन करना तथा अन्य बैंकों से भी खाते के संबंध में बात करके, कमजोर यूनिट का पता लगाकर खाते को एनपीए होने से बचाया जा सकता है.

**इसके अलावा अन्य उपयोगी साधनों का प्रयोग भी एनपीए कम करने में मदद करता है :–**

1. लोक अदालत, डीआरटी, सरफेसिया की प्रक्रिया भी वसूली में मददगार साबित होते हैं, सिविल दावे भी एनपीए कम करने में मददगार होते हैं.
2. आईबीसी कोड के अस्तित्व में आने के बाद एनसीएलटी (NCLT) के माध्यम से भी दावों का निपटान किया जा रहा है और एनपीए को कम किए जाने में मददगार है. 1 लाख से अधिक के दावों के लिए बैंक एनसीएलटी में आवेदन किया जा सकता है जहां 6 महीने के अंदर नतीजा घोषित किया जाता है. अतः बड़े कॉर्पोरेट ऋणों का निपटान जल्दी और उचित तरीके से किया जा सकेगा.

**समझौता निपटान के लाभ:–**

1. पूंजी की पुनरावृत्ति
2. समय / विधिक कार्यवाही में होने वाले खर्च में बचत
3. बकायों में वसूली न होने योग्य भाग को बट्टा खाते में डालने से कर में प्राप्त छूट

**एनपीए वसूली के लाभ :**

एनपीए वसूली बैंक के लाभ को कई तरफ से बढ़ाता है. वसूल की गयी पूंजी की पुनरावृत्ति कर निवेश की जा सकती है. जो बैंक की आय को बढ़ायेगा. जिससे बैंक का शुद्ध लाभ बढ़ेगा. बैंक का पूंजीगत ढ़ांचा मजबूत होगा और बैंक की रेटिंग में वृद्धि करेगा.

वसूली की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है वसूली किश्तों का निर्धारण. यह अपेक्षा की गई है कि भुगतान क्षमता के अनुरूप ही वसूली किश्तों को निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि इस वर्ग के लोगों को निवेश के जरिये अर्जित आय में से अधिकतम 50 प्रतिशत से ज्यादा की राशि किश्त के रूप में जमा न करनी पड़े. वास्तविक कठिनाइयों के गुण दोषों के आधार पर वसूली किश्तों का निर्धारण भी वसूली वातावरण को अच्छा बनाने में सहायक सिद्ध होता है.

1. ऋण वांछित सुविधाओं के पूर्ण पैकेज का साथ दिया जाय.
2. ऋण के उपयोग का अनुप्रवर्तन हो, समस्याओं के निराकरण के विचार से सहयोगी दृष्टिकोण अपनाया जाय.
3. सामाजिक दायित्व जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, इत्यादि में सहायता/ सहयोग प्रदान किया जाय.

यदि उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन ऋण वितरण में किया जाए तो न केवल ऋण की उत्पादकता में सुधार होगा बल्कि ऋण चुकौती अवधि में भी सुधार होगा और भावी विकास के लिए बचत को भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा. इन उपायों को लागू करने से ऋण की उत्पादकता में वृद्धि और हितकारियों से संबंध भी सुदृढ़ होंगे जिससे बैंक की वसूली की मात्रा में भी वृद्धि होगी.

**ऋण के उपरांत अनुप्रवर्तन:** सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी अभिनिर्धारण कर देने से और उसी के आधार पर ऋण का वितरण कर देने से ही ऋण की सफलता की गारंटी नही होगी और यह भ्रामक भी सिद्ध हो सकता है.

**अनुप्रवर्तन का दायित्व :** ऋण के अनुप्रवर्तन का दायित्व केवल शाखा प्रबंधक और क्षेत्रीय अधिकारियों का नहीं होना चाहिए. उच्च नियंत्रक कार्यालयों को भी इसका दायित्व उठाना चाहिए. इससे आदर्श ऋण संस्कृति के विकास के साथ–साथ शाखा में कार्यरत अधिकारियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. अनुप्रवर्तन का तात्पर्य मात्र ऋण को उपलब्ध करवा देना अथवा उसका सत्यापन ही नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि शाखा वांछित पैकेज के साथ ऋण का वितरण करें. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऋणी को उस निवेश से क्या लाभ अर्जित होगा. यदि उससे लाभ अर्जित नहीं हो रहा है तो क्यों? उन कारणों, समस्याओं का अध्ययन किया जाये. इस बात का पता लगाया जाय कि उन समस्याओं के निराकरण के लिए बैंक ने क्या कदम उठाए.

उक्त उपायों को अपनाकर बैंक के एनपीए को बहुत कम किया जा सकता है कार्य कठिन है, राह दुष्कर, किन्तु यदि निष्ठापूर्ण शुरुआत की जाए तो सफलता निश्चित है.


***कुन्दन भगत***
*क्षे.का., मुंबई (उ.)*

***हेमंत भाटिया***
*क्षे.का., मुंबई (उ.)*

# A Precedent Success

Nowadays due to huge slippages and poor asset quality it has become increasing pertinent to focus on recovery as a key area in today's banking scenario.

Recovery of NPA has become the most critical and difficult task for bankers today. Success in recovery is totally unpredictable, despite best efforts put in. However, if dedicated efforts coupled with persistent follow ups is done then recovery is not an uphill task.

Commonly, recovery officers are found saying that Government guaranteed accounts or consortium advances are difficult to recover under the present available mechanism without affecting the business relationship with the borrowers. However, the following success story proves that there are exceptions to the above notion, if rigorous and continuous follow up is made.

The following is a recent success story in NPA Recovery, which happened in ARB Kolkata.

The borrower, West Bengal Essential Commodities and Supply Corporation Ltd, (WBECS Ltd, A Government of West Bengal Enterprise) has been banking with us since 2003. The credit limits last availed by the corporation were Rs 212.00 crores (last renewed in the year 2004). This was sanctioned under multiple banking arrangements with 8 other banks. Our Bank's share was 25.22% of the total exposure. Due to problems in debtor's realization, the liquidity of the corporation suffered badly and a restructuring was accorded in the year 2007 for Rs. 234.00 crores. As per restructuring terms, Government of West Bengal offered its guarantee to the loan. Even after the restructuring, the performance of the account was not satisfactory. Once again, proposal for second restructuring was put forward by the corporation which was not favored by the lenders. Subsequently, the account turned NPA and remained as NPA since 2008.

Banks started follow up for the dues, but the account remained chronic since 2008. As the financial position of the corporation did not recuperate, recovery was not forthcoming.

## Recovery Mantra

Difficulty faced by Banks in initiating recovery action:-

- Dealing with a Government corporation, it was difficult to initiate harsh measures immediately, unlike in the case of loans against individuals.
- The officials of the corporation did not respond properly to Bankers' calls, and were recalcitrant. The officials were not even willing to meet the bank officials.
- Any disrupting of relationship with the corporation means disruption of relations with the State Government. Banks needed to be very selective in their words/actions and correspondence.
- The overall relationship value of the state Government with our Bank itself amounts to Rs. 2000 crores approximately, for our Bank alone.
- As part of recovery action, though the guarantee against the Government was invoked, the Government did not honor its commitment.
- The matter was referred to DRT. Sale of prime security available did not materialize due to many constraints.
- The financial condition of the corporation was in very poor state. At this stage, the recovery seemed impossible even though it is a Government guaranteed account. DRT proceedings also were not very successful.

## In the above circumstances, what action has triggered the recovery?

On introduction of IBC 2016, Bank of Maharashtra one of the Tenders, suggested action under NCLT and our Bank immediately supported the same and filed a case in NCLT Kolkata. It was accepted and order was passed by NCLT on 29.5.2017. The corporation moved NCLAT but of no avail. NCLAT suggested settlement of dispute with the creditors.

On this move, the corporation, looking at the possible outcome of the actions under NCLT (liquidation), had no option except to come for the negotiating table for a resolution plan. Accordingly, the corporation proposed an OTS in the meeting of Committee of Creditors. Due to concerted efforts of the lead bank (i.e. the timely approval of the OTS proposal by our Corporate office in a record time) which was followed by member banks, it resulted in a recovery of (our share) ₹ 42.956 crores.

## Learning points

1. Bank has handled the recovery without affecting the Relationship with the State Government which may affect our Business Relation also.
2. Taken advantage of the IBC 2016 to resolve old and chronic NPA accounts and be the pioneer to come out with insolvency Resolution Plan under aegis of New Insolvency and Bankruptcy Law.
3. Taken the bold decision of moving NCLT against a Government owned corporation
4. Due to the time lines under the IBC, the Borrower was compelled to take an immediate decision to settle the dues with the Bank.
5. If the IBC timelines expire and had the liquidation been ordered against the corporation or even the state government, it would not have fetched any better timely option for the Bank. Hence, Bank has handled the situation by keeping in regular touch with the corporation officials and convincing them for payment of dues and start new relationship with banks (Like opening of salary accounts USSA, retail scheme for employees etc.)
6. Ultimately, it was decided to settle and Government of West Bengal allocated funds for repayment of dues to the Bank.
7. A chronic accounts under A3 category with 100 provisions was amicably settled and banks got the fund within the timeline of resolution.
8. The proposal was closed without any "Write off" for the Bank and provision held has been released.

Hence we can say that recovery is best done with a practical and sharp approach and continuous focus, perseverance and alertness are the keys to speedy recovery.

***Baijnath Singh***
*R. O., Siligudi*

# जे.एच.वी. शुगर लिमिटेड
## ऋण खाते में
# एनपीए वसूली

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका के साथ कार्यरत हमारे बैंक का वाराणसी अंचल, यहां के 25 जिलों में अपनी 592 शाखाओं के सघन नेटवर्क के साथ आम जनता की सेवा में निरंतर लगा है. लघु एवं मध्यम आकार के कृषि एवं एमएसएमई ऋण खातों से समृद्ध इस अंचल में बड़े औद्योगिक ऋणों की संख्या नगण्य ही है. ऐसे में बड़े एवं मध्यम आकार के ऋणों की महत्ता बढ़ जाती है. ये ऋण खाते यदि बेहतर ढंग से संचालित होते रहें, तो बैंक के लिए भी ये आन, बान व शान के प्रतीक बन जाते हैं; लेकिन यदि किसी कारण से ऐसे बड़े खाते एनपीए हो जाते हैं; तो बैंक के लिए परेशानी का सबब भी बनते हैं. हमारे अंचल में इसी तरह का एक ऋण खाता जे.एच.वी. शुगर लिमिटेड का है, जो हमारी वाराणसी मुख्य शाखा में है तथा इसकी यूनिट महाराजगंज जिले में स्थित है.

जे.एच.वी. शुगर लिमिटेड वर्ष 2001 से हमारी वाराणसी मुख्य शाखा से ऋण सुविधा का लाभ उठा रही थी, जिसके तहत यूनिट को कैश क्रेडिट व सावधि ऋण के रूप में ₹ 66 करोड़ की ऋण सीमा प्रदान की गई थी. प्रारम्भ में इस यूनिट की स्थिति काफी अच्छी थी तथा लाभ भी कमा रही थी; लेकिन कालांतर में फैक्ट्री हानि की स्थिति में आ गई. दुखद पहलू यह रहा कि इसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया तथा मासिक किश्तों की समय से अदायगी न होने के कारण 30 सितम्बर, 2016 को यह खाता एनपीए हो गया. उस समय एनपीए राशि ₹ 61.22 करोड़ थी.

उल्लेखनीय है कि उक्त फैक्ट्री के मालिक वाराणसी के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो पूर्व सांसद भी हैं. अत: इनकी बंधक सम्पत्ति से ऋण की वसूली करना काफी कठिन कार्य हो गया था. ऋण वसूली हेतु बैंक द्वारा किये गये प्रयास विफल हो जाते थे. अत: विवश होकर तत्कालीन अंचल प्रमुख श्री एस. एन. कौशिक के मार्गदर्शन व क्षेत्र प्रमुख श्री राजीव मिश्र के नेतृत्व में सरफेसिया के तहत बंधक सम्पत्ति की नीलामी की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन ऋणी के प्रभाव एवं सामाजिक स्थिति के कारण बंधक सम्पत्ति को खरीदने के लिए कोई खरीददार नहीं मिल रहा था. बैंक की इस सरफेसिया कार्रवाई के विरूद्ध ऋणी ने डीआरटी, इलाहाबाद में अपील कर दी, लेकिन सार्थक प्रयासों से माननीय डीआरटी द्वारा ऋणी की अपील को खारिज कर दिया गया. तब ऋणी ने बैंक के विरूद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की. बैंक के विधि अधिकारी श्री जे.बी. सिंह ने बैंक एडवोकेट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बैंक के पक्ष को काफी मजबूती से रखा. बैंक के तर्क से सहमत होते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने ऋणी की इस अपील को भी खारिज कर दिया.

इस दौरान अंचल प्रमुख श्री कौशिक के मार्गदर्शन तथा क्षेत्र प्रमुख श्री राजीव मिश्र के नेतृत्व में बैंक की वसूली टीम, बंधक सम्पत्ति की ई–नीलामी में लगी रही तथा खरीददार मिलते ही बंधक सम्पत्ति में से तीन प्रमुख प्लांटों की बिक्री कर ₹ 11.75 करोड़ की वसूली कर ली. साथ ही ऋणी की अन्य बंधक परिसम्पत्तियों पर बैंक का भौतिक कब्जा पाने हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी के यहां अपील की गई.

जिलाधिकारी महोदय से अनुमति मिलते ही बैंक की ओर से ई–नीलामी कार्रवाई पुन: शुरू की गई. ऋणी ने बैंक की इस कार्रवाई के विरूद्ध पुन: डीआरटी, इलाहाबाद में अपील की, लेकिन सम्भवत: अपने विरूद्ध निर्णय का आभास करते हुए ऋणी ने अपने प्रभाव के बल पर अपील को डीआरटी इलाहाबाद से पटना में स्थानांतरित करा लिया. माननीय डीआरटी पटना के समक्ष भी बैंक ने पक्ष को उसी मजबूती के साथ व तर्कपूर्ण ढंग से रखा गया तथा डीआरटी पटना द्वारा भी ऋणी की अपील खारिज कर दी गई.

अपील खारिज होने तथा ई–नीलामी की तिथि नजदीक आते देख ऋणी ने बैंक के समक्ष समर्पण करते हुए ₹ 45 करोड़ भुगतान करने का एकमुश्त समझौता प्रस्ताव (ओटीएस) दिया. अंचल प्रमुख तथा क्षेत्र प्रमुख द्वारा यह समझौता प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया गया तथा केन्द्रीय प्रबंधन की मौखिक सहमति से न्यूनतम रनिंग लेजर की शेष राशि, जो ₹ 51.28 करोड़ थी, ऋणी को जमा कराने हेतु प्रस्ताव दिया गया. इसमें से ₹ 10 करोड़ अग्रिम राशि के रूप में जमा करने को कहा गया. अंतत: ऋणी ने इस ओटीएस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ₹ 10 करोड़ तुरंत जमा किये. उसके बाद से अब तक उक्त खाते में ₹ 8.90 करोड़ और जमा किये गये हैं. इस प्रकार खाता एनपीए होने की तिथि से अब तक कुल ₹ 30.65 करोड़ जमा हो गये हैं तथा शेष बकाया राशि 30 जून, 2018 तक जमा होने की सम्भावना है.

उल्लेखनीय है कि जे.एच.वी शुगर लिमिटेड के मामले में बैंक को मिली सफलता ने बैंक के वसूली प्रयासों को नई ऊर्जा व दिशा प्रदान की है. ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के विरूद्ध वसूली की सफल कार्रवाई से एनपीए ऋणियों द्वारा बैंक का ऋण अदा न करने के दुस्साहस को झटका लगा है और अन्य एनपीए ऋणी भी ऋण जमा करने हेतु सार्थक पहल कर रहे हैं. इसी दिशा में एक सार्थक पहल की गई है मे. मानव ब्रेवरीज की बंधक सम्पत्तियों का बाजार मूल्य अधिक है. अत: इसके मालिक ने 30 जून, 2018 तक अपने एनपीए खाते को पूर्णत: समायोजित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें ₹ 2.10 करोड़ जमा भी कर दिये है.

हमारे तत्कालीन अंचल प्रमुख श्री एस. एन. कौशिक, तत्कालीन क्षेत्र प्रमुख श्री राजीव मिश्र एवं टीम वाराणसी द्वारा किये गये अथक प्रयासों के फलस्वरूप वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान वाराणसी अंचल वसूली में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम रहा, जिसमें हमारे बैंक के उच्च प्रबंधन का प्रेरणादायी मार्गदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

*संजीव कुमार*
*क्षे.म.प्र.का., वाराणसी*

# ऋण वसूली

ज़िंदगी को सफल ढंग से जीने के लिए या वसूली का कार्य सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए हमें आशावादी होने के साथ व्यावहारिक, यथार्थवादी के साथ व्यवहार कुशल होना आवश्यक है. हमें यह अच्छी तरह जानना होगा कि इस दुनिया में दुख, कठिनाई, अवसाद आदि हमारे जीवन के प्रमुख अंग हैं. यहां कभी खुशी है, कभी गम है, अर्थात हमें जब एक तरीका असफल होता दिखे तो हमें तुरंत दूसरा रास्ता खोजकर कार्य को अंजाम देना चाहिए.

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार की नीतियों में निरंतर परिवर्तन के कारण आज-कल बैंक का एनपीए निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसमें ऋण माफी का भी योगदान है. जो लोग बैंक का पैसा चुकता नहीं करते हैं उनको माफी दी जाती हैं और जो लोग समय से पैसा जमा करते हैं उन्हें ऋण माफी का लाभ नहीं दिया जाता है. इन सभी नीतियों के कारण बैंकिंग क्षेत्र बढ़ते एनपीए को लेकर बहुत चिंतित है. इसलिए आज बैंक की प्राथमिकता में ऋण वसूली एवं एनपीए प्रबंधन बैंक की पहली प्राथमिकता है क्योंकि एनपीए बढ़ने से सीधे बैंक के लाभांश से प्रोविजिनिंग करनी पड़ती है और आगे चल कर बैंक के तुलन पत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है और फंडिंग बंद हो जाती है और अंततः बैंक की आमदनी का जरिया भी धीमा हो जाता है.

जब मैं आगरा क्षेत्र की एक शाखा में शाखा प्रबन्धक था तो वहाँ कुछ खाते एन पी ए हो गए थे. उसके बाद हमने उन खातों की सूची बनाकर हम उन खाता धारकों से मिले जो उनमें से कुछ मजबूर थे, कुछ मगरूर थे, अर्थात वह बैंक का पैसा चुकाने में सक्षम थे लेकिन पैसा जान-बूझ कर नहीं चुकाना चाहते थे. उस समय मुझे एक कहानी याद आई कि 3 डाकू और 40 मुसाफिर अर्थात 40 लोग सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे और उन्हें रास्ते में तीन डाकुओं का दल मिला और उन चालीस लोगों को लूट लिया क्योंकि वे संगठित नहीं थे लेकिन तीन डाकू एक दल के रूप में संगठित थे. इस घटना से प्रेरित होकर मैंने पूरे ताने बाने के साथ ट्रांस-जेंडर (किन्नरों) से बात की और उनको गाड़ी में ले कर ₹ 15.00 लाख के बकायेदार के घर पहुंचा.

सबसे पहले हमने उनको अपना परिचय दिया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सैयां शाखा से आये हैं, आपका बैंक पर ₹ 15.00 लाख का बकाया है और आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है, आप हमारे पैसे दीजिये. उसके बाद पार्टी ने धमकी भरे स्वर में कहा कि हमने पहले ही आपको घर पर आने के लिए मना किया था, आप हमारे घर कैसे आये? हमने कहा 'हमारे बैंक में जो ग्राहकों का पैसा है, उसी से हमारा बैंक चलता है और आप जैसे लोग लोन लेकर उसका भुगतान नहीं करेंगे तो बैंक कैसे चलेगा?' फिर उन्होंने धमकी भरे स्वर में कहा कि हम आपको अभी देखते हैं! उसके बाद हमारी किन्नरों की टीम गाड़ी से उतरी और चारों तरफ से उस घर को घेर लिया और उसके बाद उन्होंने बकायेदार को कहा कि बैंक से पैसा लेकर जमा नहीं करते हो और कहते हो घर पर क्यों आए हो? उसके बाद बकायेदार ने इस स्थिति को टालने के लिए कहा कि 15 दिन के बाद हम आपके पैसे को जमा कर देंगे. फिर उसके बाद किन्नरों की टीम ने कहा कि हमें अभी तुरंत पैसा चाहिए, जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे. उसके बाद कुछ महिलाओं ने धमकी देने की कोशिश की तब उन्होंने अर्थात किन्नरों ने महिलाओं को बंद कर पुलिस को सूचित किया कि 'हम बैंक का लोन वसूलने आए हैं और ये हमसे झगड़ा एवं मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए इनकी तुरंत प्राथिमिकी रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर इन्हें जेल में बंद किया जाए.' इस घटना को देखते हुए बकायेदार को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी और उसने कहा, "15 मिनट का समय दीजिए हम आपको अभी पैसे देते हैं,' उसके बाद हमने बकायेदार को वहीं बैठाये रखा तथा दूसरे व्यक्ति को पैसा लेकर आने को कहा. वह व्यक्ति 15 मिनट में कहीं से पैसा लेकर आ गया और हमने एनपीए खाते को बंद कर दिया. इसके बाद मुझे यह आभास हुआ कि सही समय पर सही निर्णय या कड़े फैसले लेने से वसूली में अच्छे परिणाम आ सकते हैं और इसी योजना के तहत मैंने एक महीने में अपनी शाखा के एनपीए स्तर को बहुत कम कर दिया और यह तरीका मैंने सभी विलफुल डिफ़ाल्टर पर अपनाया.

*डॉ. श्याम बाबू सागर*
*क्षे. का. आगरा*

# Wheels of

Opened 47 years ago (in 1971), our Uppalapadu branch is one of the oldest branches under NRO, Vijayawada. Being a rural branch, most of its business is agro-based, the major segments being crop loans and MSME loans. The branch has adopted 12 villages.

After going into the charge of Mr.Ch. Chitti Babu, Branch Manager, the branch has really registered an astounding performance in NPA recovery. Its NPA level of ₹ 8.25 crore when he took charge in May 2017 was drastically reduced by 50 percent, i.e. to ₹ 4.50 crore as on date, i.e. within a span of 12 months.

Mr. Chitti Babu started his career in Karur Vysya Bank as a Scale-I Officer, continued in Andhra Bank and IDBI before joining our Bank in 2009 as a direct-recruit Scale-II officer. He is an energetic go-getter with an instinctive passion for recovery of bad debts, forever after the defaulters with his unique strategies. Strengthened by the exposure and experience from his previous assignments, he applies his unique PCA formula (positive contact through action), draws up a monthly action-plan involving a monthly target of ₹ 50-60 lakh of NPA recoveries, and, with his unique way of functioning, is successful in recovering not less than ₹ 30 lakh every month. Apart from the most welcome results in the form of phenomenal recoveries, the branch has also garnered a good number of loan proposals under the SSS scheme.

He starts his recovery hunt every morning on a bicycle – yes, a bicycle. He takes out his bicycle at 05.30 a.m. with a handy list on his person of the NPA borrowers of a particular village, and covers a distance of nearly 5 km in search of the defaulters. Leaving nothing to chance and leaving no stone unturned, he moves about in the selected villages until 08.30 a.m., busy with his interaction with the borrowers. It

# Recovery

is the early bird that catches the worm. If he moves out early, he is sure to get into touch with the borrowers before they leave home. If, at times, he happens to be too late for that, he would extend his pursuit out into the paddy fields or whatever, and achieves his contact. He has been regularly visiting NPA borrowers right from taking charge of the branch, which calls for consistent efforts and great perseverance. His vigour and vibrancy in follow-up have been bearing fruit in substantial recoveries even from the chronic, hard-core defaulters, and in ensuring the health of the loan-assets in general.

His philosophy, commitment and methodology combine to form an eternal source of motivation for the other members of his team, right down to the subordinate level. They move about along with him in contacting the defaulters and sticky customers and taking steps to ensure compliance with the lending system of the bank. In this campaign, his team takes a tour of the concerned villages wearing special white attire with placards reading "NPA is terrible, please get rid of it", " Farmer's welfare is our Bank's motto", "Pay old loans and take new loans with lower rate of interest", "Don't be rigid in paying dues, pay your debts promptly". The campaign brings about certain awareness among the illiterate customers and wilful defaulters alike, of their essential responsibility in the financial assistance provided by the bank. Mr. Chitti Babu says, "this type of early morning campaigns will spread positive messages throughout the villages, and the farmers will come to know how dreadful and dangerous the NPAs are to the organisation and the borrowers alike."

Thus, thanks to the team work and positive attitude of the staff members under the dynamic leadership of Mr. Chitti Babu, the branch registered NPA recoveries to the tune of ₹ 4.50 crore just in one year. After his reporting, branch deposits increased to the tune of ₹ 100 lakh, advances increased to the tune of ₹ 573 lakh and CASA improved by ₹ 198 lakh as of 31.03.2018. Also, due to effective and meticulous planning strategies applied, the branch profit almost doubled from ₹ 49 crore to ₹ 117 crore.

While taking charge, Mr. Chitti Babu noticed the dilapidation of the branch premises and the instant need for renovation. His attention to this aspect resulted in the inauguration of the renovated premises on 12.03.2018 by Sri K.P.Acharya, F.G.M., Bangalore, during his visit to N.R.O., Vijayawada and this is the first time in the history of the branch that an executive in the rank of Field General Manager visited the branch.

With a screen saver "NPA IS BAD" on all the computer screens of the branch, Mr.Chadalavada Chitti Babu says that with the able guidance, support and encouragement from the Regional Head Dr.K.Ravindranath, the team is confident of bringing more such laurels and sustaining low NPA levels in the days ahead.

TEAM UPPALAPADU deserves a special mention and applause in NPA recovery.

***NVNR Annapurna***
*N.R.O., Vijaywada*

# एनपीए रिकवरी

बैंकिंग सेक्टर के चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक एनपीए रिकवरी है, एक तरफ आर्थिक विकास की दर को तेज करने के लिए उन्हें ज्यादा कर्ज़ देने को प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बढ़ते एनपीए की वजह से कर्ज़ के साथ जुड़े जोखिम को लेकर भी सावधानी बरतनी है. जानबूझकर कर्ज़ नहीं लौटाने वाले ग्राहकों से एनपीए वसूली सबसे मुश्किल होती है. अधिकांश मामलों में 12% से 15% एनपीए की वसूली ही संभव हो पाती है.

एनपीए वसूली में आने वाली सबसे बड़ी कठिनाई भाषा की समस्या है. आदिवासी इलाकों से वसूली करना बहुत ही कठिन कार्य है, जहाँ आवागमन की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है. वसूली करने वाले अधिकारियों पर जानमाल का खतरा भी बना रहता है.

क्षेत्रीय कार्यालय, महेसाणा की रिकवरी टीम अत्यधिक उत्साहपूर्वक कार्य करती है जिसका परिणाम समय-समय पर प्रदर्शित होता रहता है. वित्तीय वर्ष 2016-2017 में एनपीए वसूली ₹ 5 करोड़ 40 लाख थी. वित्तीय वर्ष 2017-2018 का शानदार प्रदर्शन रहा. वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 18 करोड़ 93 लाख हो गयी जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले ₹ 13 करोड़ 53 लाख ज्यादा हैं।

*क्षेत्रीय कार्यालय महेसाणा के सबसे बड़े एनपीए खाते मरियाना फूड प्रा. लि. के एनपीए होने के पश्चात SARFAESIA Act के तहत 13/4 में कब्जा लेते हुए क्षेत्रीय कार्यालय महेसाणा की रिकवरी टीम.*

महेसाणा क्षेत्र में एनपीए वसूली में तेज़ी से वृद्धि का श्रेय क्षेत्र के मजबूत प्रबंधन एवं समस्त महेसाणा टीम को जाता है. क्षेत्रीय कार्यालय महेसाणा के कुशल प्रबंधन द्वारा एवं अधीनस्थ शाखाओं के सामंजस्य से यह कार्य सफल हो पाया एवं क्षेत्रीय कार्यालय महेसाणा ने अपने 11/11 पैरामीटर के लक्ष्यों को प्राप्त किया. अहमदाबाद अंचलीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रीय कार्यालय महेसाणा, छोटा कार्यालय होते हुए भी समस्त भारत में अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है. प्रत्येक प्रातः कॉर्पोरेट प्रार्थना के बाद एक प्रेरणादायक प्रसंग के साथ एक परिपत्र पर चर्चा की जाती है तथा प्रत्येक शाखा के शाखा प्रमुख अपनी शाखाओं से दैनिक आधार पर अनुश्रवण करते हैं एवं उन्हें प्रोत्साहित करते हैं.

***डॉ. मनीषा सिंह***
*क्षे.का., महेसाणा*

# PWO में वसूली

*हमारी शाखा, नायगांव क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक के अंतर्गत आती है. हमारे यहाँ 'जय मल्हार लिफ्ट इरिगेशन' नाम से हमारे बैंक द्वारा सन 1987 में 1,36,00,000/–(एक करोड़ छत्तीस लाख रुपए) का ऋण लिफ्ट सिंचाई के लिए दिया गया था. इस योजना के अंतर्गत पिंपल गाँव निपानी एवं तलवाड़े तालुका, निफाड़ जिला नासिक इन्हीं दोनों गांवों के 500 किसानों को फायदा पहुंचाया गया है. यह योजना 10 साल तक अच्छी तरह से चली. अंततः योजना 1999 में बंद हो गई और हमारा खाता एनपीए में चला गया. हमारे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा कई बार दोनों शाखाओं के समक्ष समझौता प्रस्ताव रखा गया पर गाँव के किसानों में आपसी समझ एवं सहमति न होने के कारण हर बार हमारा प्रस्ताव पास नहीं हुआ. अंत में हमारा यह खाता ₹ 79,54,342/– से पीडबल्यूओ (prudential write off) किया गया.*

हम कानूनी तौर पर हर साल कमजोर होते जा रहे थे. एक साथ सभी किसानों पर सूट फाइल करना कठिन काम था. जबकि हमारी शाखा के पास केवल संस्था के साथ 'डीड ऑफ असाइनमेंट' था. संस्था की सबमर्सिबल मोटर सील करके रखी गई थी एवं उसका वैल्यूएशन भी कम था. इसी दौरान जून–2017 में मैंने नायगांव शाखा का प्रभार शाखा प्रबन्धक के रूप में ले लिया. मेरे मन में पहले दो महीनों तक इसी जय मल्हार लिफ्ट इरिगेशन की पहेली सुलझाने की इच्छा थी और मुझे विश्वास था कि मैं और मेरे सहयोगी जरूर इसका निपटान कर लेंगे. अतः हमने शुरुआती महीनों में हमारा सबसे पुराना माध्यम पोस्ट कार्ड, किसानों को भेजना शुरू किया.

शुरुआत में लोगों को हैरानी हुई कि आज इस 'वॉट्स एप' के दौर में भी बैंक पोस्ट कार्ड भेज रहा है. कुछ लोगों को लगा कि बैंक के पास कम पैसे होंगे इसलिए उन्होंने यह पोस्ट कार्ड भेजा होगा. इन पत्रों के माध्यम से लोगों को एहसास हो गया था कि हमारे ऊपर आज भी कर्ज बाकी है. दूसरे उपाय के रूप में हमने तुरंत गांव में मीटिंग बुलानी शुरू की. लोगों से कर्ज अदायगी करने की अपील की. कुछ लोगों ने हमें यह कहा कि आप कुछ छूट दोगे तो हम पैसे भरेंगे. मेरी समझ में आ गया कि लोगों की पैसा वापस करने की ईच्छा है लेकिन कोई भी इस संवेदनशील विषय में हाथ लगाना नहीं चाहता. इसलिए मैंने संस्था के चेयरमैन एवं सचिव, दोनों गांवों के बीसी की मीटिंग बुलाई और दि. 09.12.2017 को होनेवाली लोक अदालत में सभी कर्जदारों को भेजने के लिए कहा. हमारी मीटिंग 30.11.2017 को सम्पन्न हुई.

दूसरे दिन नजदीकी कोर्ट में जाकर 231 लोगों को नोटिस भेजी गई. हमारे पास 6 दिनों में 231 लोगों को नोटिस पहुँचाने का लक्ष्य था. उसमें भी कई सारी दिक्कतें थी, जैसे कर्जदार का मृत पाया जाना, कर्जदार का 20 साल पहले गाँव छोड़कर जाना आदि. हमारे द्वारा भेजे गए 231 में से सिर्फ 70 लोगों को नोटिस मिली और अन्य नोटिस हमें उपरोक्त कारणों की वजह से हमारी शाखा में वापस आ गए. फिर हमने दि. 08.12.2017 को दोनों गांवों की अंतिम मीटिंग अलग–अलग की. हमने अपील की कि जिन लोगों को एनओसी चाहिए वह लोग कल कोर्ट में आकर अपना प्रस्ताव रखें, उन्हें भारी छूट दी जाएगी.

इसी साल हमारे बैंक द्वारा एनएसएसडीएल–2017 योजना लाई गई और इस तरह 45% पीडबल्यूओ के तहत हम ले सकते थे. दि. 09.12.2017 को चेयरमैन एवं सचिव लोक अदालत पहुंचे. दोपहर के बारह बज चुके थे पर कोई भी कर्जदार नहीं आया था. अचानक एक 40 लोगों का ग्रुप आया और हमारे साथ चर्चा का प्रस्ताव रखा कि इसी समय 2006 का जो बकाया था, उस पर हमें 50% छूट अगर संस्था और बैंक देती है तो अगले 16.12.2017 तक रुपए जमा करेंगे और हमें तुरंत एनओसी चाहिए. यह मेरे लिए बड़ा ही पेचीदा मामला था क्योंकि उन्हें निर्णय तुरंत चाहिए था. उसी समय मैंने हमारे क्षेत्र प्रमुख, श्री विनायक टेंभूर्णे, श्री वी एस मूर्ति और हमारी सीआरएलडी टीम के श्री अमित छोड़ंगे एवं श्री राजा इनके साथ चर्चा की.

उस चर्चा के उपरांत हमने किसानों की शर्त मान ली क्योंकि हमारा काम 45% के हिसाब से हो रहा था. मगर हमने भी यह शर्त रखी कि यहाँ मौजूद सभी किसानों को लोक अदालत में अवार्ड कराना होगा और संस्था का आरओसी तब हटेगा जब बैंक की रकम वसूली जाएगी. यह शर्त किसानों ने मानी और हर अवार्ड के साथ मिनिमम एक हजार रिकवरी रखी. उसी दिन हमें ₹ 3,50,000/– नकद वसूली प्राप्त हुई. यह बात हमने फैला दी कि बैंक 50% माफ कर रहा है, ऐसे में बचे हुए लोगों के लगातार 4 दिन कोर्ट में अवार्ड पास किए गए. हमारे 225 अवार्ड पास हुए. इस तरह पैसे भरने के लिए सचिव, गाँव के प्रतिष्ठित नागरिक और बीसी से मैंने दबाव बनाना शुरू किया. वातावरण पॉज़िटिव रहा और आज दि. 30.12.2017 को क्षेत्रीय कार्यालय ने ₹ 3,57,90,000/– ओटीएस एप्रूव किया और दि. 11.12.2017 से 30.12.2017 तक सभी किसानों से हमने 35,79,000/– रु. 'राइट ऑफ' अकाउंट में ले लिए. हम इसके लिए हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. मेरा मानना है कि हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य होता है. जहां आप अपना दिल लगा दो, वहाँ परिणाम मिलते ही हैं. उसके लिए आपको अपने मन में विश्वास और काम के प्रति श्रद्धा रखनी होती है.

***योगेश पाटील***
*नायगांव शाखा, नासिक*

# IMPACT OF NPA ON INDIAN ECONOMY

Loans classified as Non-Performing assets of the banks is a very critical issue.

The RBI/the finance ministry should take strict steps to curtail the Non Performing Assets of the Bank. The mounting non performing assets of the PSU banks is a threat to the economy of the nation and should be dealt with a firm hand by the finance ministry and the Reserve Bank of India.

Some of the effects of growing NPAs on Indian economy are summarised below :-

- India is a developing country and for the development of Indian economy, the various businesses have to grow. Businesses require funds to grow and they depend on Banks for funds. However, if Banks suffer losses, there will be credit squeeze and banks will not be able to lend to businesses which in turn will slow down the economy and hamper growth.
- Unemployment is one of the biggest problems faced by our country. The number of unemployed people in India has always been on a high. It is gathered that there are currently nearly 31 million unemployed Indians looking for jobs. To create jobs for these unemployed people we should lend to businesses, entrepreneurs, infrastructure projects, small and medium enterprises etc. who will generate jobs for the jobless. However if the Banks do not have enough funds to lend to these sectors, they will not be able to create jobs and thus we will not be able to generate jobs for the youth.
- With mounting NPAs, people will slowly stop trusting the banking system which is bad for the economy. This will also have an adverse effect in the global market.
- The banks will not be able to lend to priority sector like agriculture, housing, education which will have an adverse effect on the Indian society.
- When banks are unable to lend due to mounting NPAs, more and more people depend on money lenders/ unorganised sector for their credit needs.This is detrimental to the interests of the people and society in general.
- Most of the time and energy of the bankers is shifted to recovery and thus many other jobs related to banking will be effected.

To recover the dues, Banks use various methods including DRTs, adverse reports in CIBIL reports, SARFAESI etc. The following methods can also be used to recover our dues :-

- Counseling the borrowers will bear fruits if done with tact and diligence. The defaulters may be counseled either by bank staff or by people of repute like retired teachers, motivational speakers, religious gurus etc.
- The defaulters should be convinced/ educated that defaulting dues with the bank will result in their names being reflected in the CIBIL Reports and that they will not get loans in future due to low CIBIL score. They should also be educated that not only they, but even their family members will find it difficult to get loans in future due to their default.
- In case of defaulters working in offices/ employed, the bank staff should visit their offices and try to meet their superiors/employers .This will result in embarrassment for the defaulters and they will try to pay the dues.
- Wherever guarantors are available, the bank staff should put pressure on them and inform them about the overdues and counsel the guarantor to advise/ pressurise the defaulters to pay the dues.
- A copy of the default letter should be sent to the employers of the defaulters in case of defaulters who are working with reputed employers/government organisations.

In the end, I would like to add that preventing slippages is better than recovery. This can be achieved by thorough due diligence of the borrowers, security and other parameters and proper assessment of the repayment capacity of the borrowers.

***Veena Shenoy***
*NRO Bangalore*

## *Face in the Union Bank Crowd*

# Mr. B. B. Roy
# Banking on his 'Numismatic Traits'

**Friends, we all are acustomed to our currency, generally coins since our childhood, thanks to our piggy banks. In day-to-day business, bankers deal in various types of curruencies. But hardly a few have ardent love for these coins who collect them not for hoarding but to extract and enrich their knowledge from these tiny yet precious pieces. For this, they delve deeper and deeper into the chosen subject but still touching the boundary of satisfaction seems to be just missed out. This hunger leads them on the way of becoming exuberant. In this journey, not only the new, shining coins but old, dirty, soiled, dented ones lure them equally. One such fanatic fellow amongst unionites is Shri B.B. Roy, Senior Manager (Law), Regional Office, Vijaywada. Joining our Bank in 1990 as a Law Officer, Shri Roy is the only member in his family having any interst in the rare hobby of Numismatics. Nurturing the hobby on his own, he aspires to develop a mini museum of his own in post retired life. He also desires from the heart to make people aware of the rich history. Because he believes that these coins not only depict India's achievements & contributions to the world but also display world's historic events, economy and philosophy as well. Here, in this candid dialogue with Mrs. Supriya Nadkarni, this ardent coin collector shares the numismatic tales with our readers.**

**Who introduced you to the field of 'Numismatics'? How have you started?**

During my visit to native place, one of my uncles approached me for getting a 'Hanuman paisa' since I was in Bombay (Mumbai) then. Out of curiosity, I purchased a book on Indian Coins & found "Hanuman Coin" which was in circulation in Ratlam State. To my surprise, uncle was not in search of that coin. However, this incident triggered my latent fascination for 'Numismatic' hobby. Then onwards, there was no looking back.

**Please throw some light on numismatics and how popular is it in India.**

Coins are important archaeological objects that can provide valuable information regarding coin minting methodology and provenance as well as politics and economics of the time. 'Numismatics' is the study or collection of currency that includes coins, tokens, paper money and related objects.

It is called the "Hobby of Kings", due to its most esteemed founders. The collection of antiquity started by priests, nobles and rulers long back in history and later the systematic development of the study of coins was pioneered by Joseph Hilarius Eckhle, an Austrian Priest of 18th century who introduced Greek and Roman coinage. Later on, the collection of numismatics was initiated in the universities under the supervision of historians and archaeologists methodically and subsequently general public started having interest in this hobby. The coin age goes back to 600 BC from the Mauryan era. Hence, numismatics is not new in India. Anyone can be a numismatist by collecting coins. The person who is interested in coin collection should know how to figure out whether it is genuine or fake. But a layman cannot identify the genuineness of a coin easily as it requires some expertise. At present, the hobby of coin and currency collection steadily is becoming a good business venture in India and many people have taken to coin collection. I started with buying old coins & currency notes from dealers to build my own collection. Due to my transferable job, I have little opportunity to associate with Numismatic Society. As such, I have no specific field of collection as it is too costly & requires a lot of time to have all items on that particular subject.

**For this, is it obligatory to register with Postal Dept/RBI or any other Institute?**

Being an antique item, it comes under 'Antique & Art Treasure Act, 1972'. The objects, belonging to

the era more than 100 years ago, are to be registered with Archeological Survey of India (ASI), along with photograph. However, Dealers who sell the pieces, are required to register under the said act and not the collectors. Now, the said Act is going to be amended for making smooth movement of such antiquities in the country.

**Which is the oldest note and coin adoring your collection? How had you obtained it?**

I have "Punchmark" Coins which belong to B.C. era. Luckily, I could get it from the Dealer 25 years back. Punch-marked coins are the oldest known numismatics used in ancient India. When the barter system lost credibility in ancient times, a uniform currency system came into being. An authentication mark was stamped on the piece of metal to promise that it had adequate purity and weight. The ruling King of the concerned territory was given power to issue coined money. Punch-marked coins are considered the earliest documented coins in India. These coins were mostly made of silver and bear various symbols, each of which was punched on the coin with a separate 'punch'. The date generally accepted for these coins is the beginning of the 6th century BC. the Indian silver punch-marked coins are unique and different from other contemporary currencies of the world. They reflect the worship of nature, Vedic divinities, Brahmanical and Hindu gods, Yaksha and Yakshi figures, tribal gods, and deities of Buddhism and Jainism.

**How can a person trace the era of a coin?**

If a person having coins knows ancient scripts and meaning of the figures encrypted on them, then the era of the coin can be traced. Actually, coins have been in use since ancient times. Hence, every coin has the name of the ruler or emperor along with the place of the mint encrypted on it.

**What steps do you take to enrich your collection? What are your sources?**

I used to visit e-bay site for updation. But being a costly affair, I have stopped buying now. Further, I have some other obligations which restrict me to pursue my hobby.

**Who organize exhibitions/competitions here?**

Only the Numismatic Societies or Philatelic Societies organize such exhibitions.

However, I have not participated in any such exhibitions so far.

**To have a huge collection is certainly a matter of pride. What are the worst elements that affect paper currency collection? What are your suggestions to preserve the collection of coins & currencies?**

Light, heat and moisture are the worst elements that affect your paper currency collection. They damage the paper itself slowly, causing shredding and eventually pictures fade away completely. Please do not to display your collection in direct sunlight for a prolonged time as it causes fading, yellowing and brittleness. Instead, halogen bulbs can be used for close examination purposes since ultra-violet rays are destructive to paper currency.

**Any special tips for preserving coins?**

Coins can be protected by use of acid free plastic folders, especially of Taiwan, German make or else coins and currencies will be damaged. For avoiding moisture, use of 'Silica Gel' is a must. For Commemorative Coins, they usually come in acrylic packing and are temper proof. Normal issue coins have to be cleaned and polished and then packed in "Coin Holders" and placed in good Albums. Silver Coins need periodical cleaning and care.

**How do you spare your precious time from this responsible job for nurturing your equally precious job?**

Hardly I get time….I utilize Sundays and holidays for the same.

**According to you, who can take up this hobby?**

To have interest in collecting things and preserving them, keeping them neat and clean are the basic requisite of numismatics. Don't collect things with the thought that I will make MONEY out of it. Have knowledge of the subject of collection and theme / story behind it. All Collections are like Babies, it needs extra care, attention and grooming like a Child, Love and Affection is most important for it to grow. Any person who is Loving, Caring, Cheerful, Helpful, with Good Habits and no vises can start this Hobby. A person should have liking for Art, Culture Music, and should be Artistic too.

**How will you guide the budding collectors?**

To initiate, one should go for Indian old coins/currencies, which are available a plenty at a premium rate & hence easily affordable. But while going for rare items (which are also costlier), be cautious as now-a-days the market is full of duplicate coins, currencies & it is very difficult to get genuine items.

***'Union Dhara' wishes him all the Best in his future numismatic endeavours. More variety to his numismatic treasure!!***

*Supriya Nadkarni*
*Union Dhara, C.O.*

प्रतियोगिता क्र. 146

# नयी प्रतियोगिता

## "बारिश" पर कविता लिखें

जून 2018 अंक

हमारी गृहपत्रिका का जून 2018 अंक **'बारिश' पर कविता प्रतियोगिता'** का ऐलान करता है. कुछ लोगों के लिए बारिश खुशी की लहर, आनंद, आमोद–प्रमोद और राहत लेकर आती है. जब कि कुछ लोगों के लिए वह आकस्मिक दुःख लेकर आती है. लेकिन जल जीवन होने की वजह से बारिश के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, यह बात भी उतनी ही सत्य है. हमें विश्वास है कि हमारे साथियों को अपनी यादों में विचरण करने तथा बारिश के अपने अनुभवों को याद करने हेतु यह विषय काफी दिलचस्प लगेगा. आपके कुछ अलग अंदाज को बयां करती हुयी आपकी कविताओं को प्राप्त कर हमें खुशी होगी. कृपया, नोट करें कि आपकी कवितायें 20 पंक्तियों से बड़ी न हों. कृपया इन कविताओं को 'संपादक, यूनियन धारा, 11वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई' को प्रेषित करें या इनकी सॉफ्ट कापी "uniondhara@unionbankofindia.com" पर मेल कर दें. जल्दी करें, **प्रविष्टियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 10 सितंबर, 2018!!**

संपादक

## Compose a poem on "Rain"

June 2018

June 2018 issue of our House Magazine is carrying a ***Poetry Contest on 'Rain'.*** For some, the rain brings in the winds of joy, happiness, revelry and relief, for others it may bring in untold misery. But the fact remains that we cannot do without rain since water is the source of life. We have confidence that our colleagues will find the subject interesting enough for them to delve into memory and recall their experiences with rain. Please note that your poems should not exceed the limit of 20 lines. We shall be happy to receive your poetic masterpieces (a soft copy or a hard print) at 'The Editor, Union Dhara, 11th floor, Central Office, Mumbai' or by e-mailing your entry to "uniondhara@unionbankofindia.com" immediately. Hurry up, the **last date is 10th September, 2018!!**

Editor

# 'यूनियन धारा' प्रतियोगिता के परिणाम

## प्रतियोगिता क्र. 144

### "चित्रों में सामंजस्य स्थापित करते हुए कविता लिखें"

पुरस्कार हिन्दी खण्ड

**प्रथम** **श्री दिलीप डांगी,** क्षे.का., मुंबई (पश्चिम)

**द्वितीय** **श्री आशीष कुमार गुप्ता,** क्षे.का., मुंबई (पश्चिम)

**सुश्री उपासना सिरसैया,** क्षे.का., भोपाल

**तृतीय** **श्री आशीष आर.,** बेहट शाखा

***अंग्रेजी खण्ड*** *– पर्याप्त मात्रा में प्रविष्टियाँ प्राप्त न होने की वजह से प्रतियोगिता निरस्त*

## प्रतियोगिता क्र. 145

### "'माँ' पर कविता लिखें"

पुरस्कार हिन्दी खण्ड

**प्रथम** **श्री सूर्य कुमार दूबे,** अयोध्या शाखा, लखनऊ

**द्वितीय** **श्री आशीष कुमार गुप्ता,** क्षे.का., मुंबई (पश्चिम)

***अंग्रेजी खण्ड*** *– पर्याप्त मात्रा में प्रविष्टियाँ प्राप्त न होने की वजह से प्रतियोगिता निरस्त*

*सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई !!!*

*– संपादक*

Our MD & CEO, Shri Rajkiran Rai G. flanked by our Executive Directors Shri V.K Kathuria, Shri R.K.Verma & Shri A.K.Goel, at the press conference held in Mumbai on the occasion of announcement of Audited Financial Results for the Quarter/ Year ended March 31, 2018.

Our Bank conducted its 16th Annual General Meeting on 27.06.2018 at Mumbai. Seen in the photograph are Shri Kewal Handa, Chairman; Shri Rajkiran Rai G., MD & CEO; Shri Vinod Kathuria, Shri Raj Kamal Verma & Shri Atul Kumar Goel, ED's; Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director; Dr.Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director & Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director at the 16th Annual General Meeting of the Bank held on 27th June, 2018 at Mumbai.

## श्री राज किरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का विदेश दौरा

दि. 29 अप्रैल, 2018 को श्री राज किरण रै जी. द्वारा दुबई की डीआईएफसी शाखा का दौरा किया गया. तब डीआईएफसी शाखा के सीईओ श्री जितेन्दर मनीराम एवं समस्त स्टाफ सदस्यों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया गया. दुबई शाखा के ग्राहकों एवं डीएफएसए के साथियों के साथ मुलाकात एवं विचार विमर्श करते हुए श्री राज किरण रै जी.

दि. 30 अप्रैल 2018 को श्री राज किरण रै जी. के आबुधाबी प्रतिनिधि कार्यालय में आगमन पर आबुधाबी कार्यालय के मुख्य चीफ अधिकारी श्री सुरेश भारती शर्मा द्वारा पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत किया गया. साथ में दुबई शाखा के सीईओ श्री जितेन्दर मनीराम भी उपस्थित थे.

## श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का लखनऊ दौरा

दिनांक 25.03.2018 को लखनऊ अंचल के क्षेत्र प्रमुखों और अंचल की चुनिन्दा शाखा प्रमुखों के बैठक का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ. साथ में, श्री लाल सिंह, क्षेत्र महाप्रबंधक, लखनऊ अंचल और श्री एस.पी. कर, क्षेत्र प्रमुख, लखनऊ क्षेत्र.

दिनांक 26.03.2018 को स्थानीय पर्यटन भवन, लखनऊ में हमारे बैंक द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और हल्के वाणिज्यिक वाहन (यूनियन एलसीवी) के तहत बृहद ऋण शिविर के आयोजन पर महिला हितग्राही को ऋण वितरित करते हुए श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ. साथ में, श्री लाल सिंह, क्षेत्र महाप्रबंधक, लखनऊ और श्री एस.पी. कर, क्षेत्र प्रमुख, लखनऊ. इस अवसर पर लखनऊ के यूनियनाइट्स ने बैंक को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए अपने अथक प्रयासों हेतु सामूहिक हस्ताक्षर कर प्रतिज्ञा ली.

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक क्लब कार्यनिष्पादन सम्मान योजना के तहत दिल्ली (उत्तर) को 'मेट्रो संवर्ग में श्रेष्ठ क्षेत्र' घोषित किया गया. तत्संबंधी पुरस्कार श्री अशोक सिरोही, उप महाप्रबंधक को प्रदान करते हुए श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ. साथ में कार्यपालक निदेशक, श्री राजकमल वर्मा, श्री विनोद कथूरिया एवं श्री अतुल गोयल.

दिनांक 26.03.2018 को लखनऊ मुख्य शाखा के बृहद और सुविधायुक्त नवीन अत्याधुनिक परिसर एवं ई लॉबी, यूनियन 24 x 7 कंफर्ट का उद्घाटन करते हुए श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ. साथ में, श्री लाल सिंह, क्षेत्र महाप्रबंधक, लखनऊ अंचल और श्री एस.पी. कर, क्षेत्र प्रमुख, लखनऊ.

On 23.06.2018, Shri Raj Kiran Rai G., MD & CEO, inaugurating the revamped Mid Corporate Branch under RO Delhi (North) while Shri Sanjay Sharma, FGM, Delhi and Shri Ashok Kumar Sirohi, Regional Head, Delhi (North) look on. Mr. Rai also unveiled revamped SARAL under RO Delhi (North).

दि. 14.04.2018 से 05–05–2018 तक आयोजित "ग्राम स्वराज अभियान" के तहत दिनांक 18.04.2018 को 'स्वच्छ भारत दिवस' के दिन ग्राम हेतिमपुर, जिला गाज़ीपुर में उपस्थितों को संबोधित करते हुए श्री मनोज सिन्हा, रेल राज्य मंत्री.

दिनांक 12.04.2018 को रांची में बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री विनोद कथूरिया के रांची दौरे के अवसर पर उनका झारखंड के पारंपरिक तरीके से स्वागत करते हुए स्थानीय आदिवासी समाज के लोग; साथ में, श्री जी.आर. पाडलकर, क्षेत्र महाप्रबंधक, रांची; श्री अंकेश जैन, क्षेत्र प्रमुख, रांची.

दिनांक 12.04.2018 को क्षे.का., रांची द्वारा आयोजित बृहद् ऋण शिविर के अवसर पर लाभार्थी को गाड़ी की चाबी प्रदान करते हुए श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक; साथ में श्री जी.आर. पाडलकर, क्षेत्र महाप्रबंधक, रांची तथा श्री अंकेश जैन, क्षेत्र प्रमुख, रांची.

दिनांक 23.05.2018 को करनाल क्षेत्र की तीसरी यूनियन कंफ़र्ट लॉबी का शुभारंभ श्री संजय शर्मा, क्षेत्र महाप्रबंधक, दिल्ली ने किया. इस अवसर पर श्री नवनीत कुमार, क्षेत्र प्रमुख, करनाल तथा क्षेत्र के शाखा प्रबन्धक एवं ग्राहक उपस्थित थे.

रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत भोपालपट्टनम शाखा का उद्घाटन भोपालपट्टनम गांव की सरपंच महोदया द्वारा रिबन काट कर किया गया. उद्घाटन के दौरान भोपाल अंचल प्रमुख श्री योगेंद्र सिंह (महाप्रबंधक), श्री एम पी सिंह, क्षेत्र प्रमुख रायपुर एवं शाखा प्रमुख अम्बरीश पंड्या उपस्थित थे.

दिनांक 11.05.2018 को जबलपुर क्षेत्र में आयोजित स्टाफ सम्मेलन में उपस्थितों को संबोधित करते हुए श्री दिवाकर कामथ, उप महाप्रबंधक, बीपीटी, केन्द्रीय कार्यालय; साथ मंचासीन हैं, श्री योगेंद्र सिंह महाप्रबंधक, भोपाल अंचल और श्री अरुण कुमार, क्षेत्र प्रमुख, जबलपुर.

दिनांक 3.3.2018 को ऋषिनगर, उज्जैन शाखा के सौजन्य से, महाकालेश्वर मंदिर की भोजन शाला में एल ई डी. टी वी लगाया गया. श्री देवेंद्र गोस्वामी, शाखा प्रमुख, उज्जैन (मुख्य) शाखा एवं श्री आशीष सोनी, ऋषिनगर शाखा, उज्जैन मंदिर समिति के सहायक प्रशासक श्री गरुड़ जी तथा पुजारी श्री भावेश व्यास को एल ई डी टीवी प्रदान करते हुए.

## अखिल भारतीय वार्षिक राजभाषा समीक्षा एवं आयोजना बैठक 2018

वर्ष 2018–19 के लिए अखिल भारतीय राजभाषा समीक्षा सह आयोजना बैठक का आयोजन स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल में दिनांक 4 से 6 अप्रैल तक किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार श्री बिपिन बिहारी एवं केन्द्रीय कार्यालय मुंबई से महाप्रबंधक (मासंप्र) श्री रवि गुप्ता, महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख श्री योगेंद्र सिंह, क्षेत्र प्रमुख श्री गुरतेज सिंह, सहायक महाप्रबंधक(राजभाषा) श्री राजेश कुमार ने की. कार्यक्रम के प्रथम दिवस में सहायक निदेशक, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से श्री हरीश चौहान ने अपना सत्र लिया. द्वितीय दिवस श्री बिपिन बिहारी जी द्वारा देश भर से आए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ राजभाषा प्रभारियों को संबोधित किया गया. अंतिम दिवस सभी राजभाषा प्रभारियों की कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति पर समीक्षा की गयी एवं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नयी कार्ययोजना पर भी विचार विमर्श किया गया. इस बैठक के दौरान अंचलीय कार्यालय, भोपाल एवं अंचलीय कार्यालय, पुणे की गृह पत्रिकाओं का विमोचन भी किया गया.

## यूनियन धारा संवाददाता सम्मेलन 2018

**श्री विजय तिवारी**
उप संपादक, दैनिक भास्कर (हिंदी)

**श्री एस.आर. सिंह**
मुख्य संपादक, फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी)

प्रतिवर्ष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी केन्द्रीय कार्यालय से प्रकाशित होने वाली द्विभाषिक गृह पत्रिका 'यूनियन धारा' के संवाददाता सम्मेलन आयोजित करता है. इस वर्ष यह सम्मेलन स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र,भोपाल में दिनांक 07.04.2014 को आयोजित किया गया. इस सम्मेलन की अध्यक्षता, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री विनोद कथूरिया द्वारा की गयी. देश भर से आये चुनिन्दा 32 संवाददाताओं को उनके कार्यप्रदर्शन के आधार पर चुना गया था एवं इस बैठक में आमंत्रित किया गया था. यूनियन धारा की संपादक डॉ. सुलभा कोरे, संपादकीय सलाहकार श्री राजेश कुमार, सहायक महाप्रबन्धक (राजभाषा) इस बैठक के आयोजक रहे. विशेष अतिथि तथा व्याख्याता के रूप में दैनिक भास्कर (हिन्दी) से उप संपादक श्री विजय तिवारी एवं फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी) से मुख्य संपादक श्री एस आर सिंह आमंत्रित थे. उन्होंने सभी संवाददाताओं के साथ संवाद स्थापित किया. इस बैठक में इस बार की स्टार संवाददाता सुश्री राधा मिश्र, क्षे.का., बड़ौदा को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया.

दिनांक 25.06.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर की सरल शाखा का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक; श्री एम पी सिंह, क्षेत्र प्रमुख, रायपुर एवं श्री इश्तियाक अर्शद, सहायक महाप्रबन्धक, सरल शाखा, रायपुर.

दिनांक 25.06.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर में श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक तथा श्री एम पी सिंह, क्षेत्र प्रमुख, रायपुर की अध्यक्षता में टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर शहर की शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित थे.

दिनांक 21.05.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर द्वारा बैंक की विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक की उपस्थिति में हितग्राहियों को ऋण वितरित किए गए. इस अवसर पर, रेलीगेयर हेल्थ इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के नेशनल के प्रमुख श्री नौशील शाह द्वारा दुर्घटना मृत्यु दावे स्वरूप, श्री मुकाम सिंह की मृत्यु उपरांत, नामिती उनकी माता श्रीमती राजली को 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी.

दिनांक 05.05.2018 को ब्रिगेडियर आशुतोष सिरौठिया, सेना मेडल, मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा एवं करेंसी चेस्ट शाखा का निरीक्षण किया. इस अवसर पर मुख्य सुरक्षा अधिकारी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करते हुए श्री कपूर सिंह यादव, क्षेत्र प्रमुख, क्षे.का., आगरा.

यूनियन समृद्धि केंद्र, राजातालाब, वाराणसी का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री शिव प्रताप शुक्ल. साथ में, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री विनोद कथूरिया तथा क्षेत्र महाप्रबंधक, वाराणसी श्री जगमोहन सिंह व अन्य स्टाफ.

दिनांक 14.04.2018 को यूनियन बैंक एस सी/एस टी एम्प्लॉईज़ वेल्फेयर एसोसियेशन द्वारा भारतरत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की 127वीं जयंती के अवसर पर श्री राजेश कुमार, क्षेत्र प्रमुख, इंदौर, डॉ. आंबेडकर जी की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करते हुए. इस अवसर पर श्री एल.सी. झारवाल, मुख्य प्रबन्धक; एसोसियेशन के पदाधिकारी सर्वश्री बी.एल. बनसेरिया, हरीशंकर वाशी, सुभाष हार्डिया तथा सुश्री स्नेहा वर्मा, सुश्री रोजलीन उपस्थित थें.

दिनांक 23.06.2018 को रायपुर क्षेत्र के बस्तर जिले के जगदलपुर में आयोजित टाउन हॉल मीटिंग के दौरान मंचासीन हैं श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक. इस अवसर पर कुल 11 शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित थे.

दिनांक 25.06.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के प्रांगण में आयोजित ऋण वितरण शिविर के दौरान एलसीवी ऋणदाता को गाड़ी की प्रतिकात्मक चाबी सौंपते हुए श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक; साथ हैं श्री एम पी सिंह, क्षेत्र प्रमुख, रायपुर; श्री जी के पॉल, सहायक महाप्रबन्धक, रायपुर (मुख्य) शाखा एवं श्री इश्तियाक अर्शद, सहायक महाप्रबन्धक, सरल शाखा, रायपुर.

24 जून, 2018 को इंदौर में आयोजित टाउन हाल मीटिंग का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करते हुए श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.

दिनांक 12.06.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा के अंतर्गत रीवा (मुख्य) शाखा की ई–लॉबी का उद्घाटन करते हुए श्री योगेंद्र सिंह, क्षेत्र महाप्रबंधक, भोपाल एवं श्री महेंद्र श्रीवास्तव, क्षेत्र प्रमुख, रीवा.

दिनांक 06.06.2018 को भोपाल क्षेत्र की सरल लाइट शाखा का फीता काटकर शुभारंभ करते हुए श्री ए.के. सिंह; महाप्रबंधक (बीपीटी) क्षेत्र महाप्रबंधक, भोपाल, श्री योगेंद्र सिंह; क्षेत्र प्रमुख, भोपाल, श्री गुरतेज सिंह एवं सरल लाइट के प्रमुख, मुख्य प्रबन्धक, श्री मनोज जैन.

आजमगढ़ क्षेत्र को वर्ष 2017–18 के दौरान वाराणसी अंचल में वसूली के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया. क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 07.05.2018 को आयोजित कार्यक्रम में श्री आर. के. भगत, मुख्य प्रबंधक, सी.आर.एल.डी., क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ को अंचल प्रमुख श्री जगमोहन सिंह के कर कमलों से पुरस्कृत किया गया. इस अवसर पर आजमगढ़ क्षेत्र के विधि अधिकारी श्री एन. ए. रिजवी भी उपस्थित थे.

On 25.06.2018, Union Samruddhi Kendra at Ujjain was launched by Honourable Lok Sabha Speaker Smt Sumitra Mahajan under the august presence of Shri Raj Kiran Rai G., MD & CEO. On this occasion Smt. Mahajan is seen handing over the cheque to one of the beneficiaries of Pradhanmantri Jeevan Jyoti Beema Yojana while Shri Raj Kiran Rai G., MD & CEO; Shri Yogendra Singh, FGM, Bhopal; Shri A.K. Singh, GM, BPT and Shri Rajesh Kumar, Regional Head, Indore look on.

दिनांक 01.06.2018 को वृहद ऋण शिविर कार्यक्रम में स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वित्त पोषिण करते श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ; श्री अतुल कुमार, अंचल प्रमुख, रांची एवं श्री अंकेश जैन, क्षेत्र प्रमुख, रांची.

दिनांक 04.05.2018 को भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत कोलार रोड शाखा द्वारा शाखा परिसर में नि:शुल्क दन्त परीक्षण कैम्प का आयोजन किया गया. शाखा के स्टाफ सदस्यों के अलावा शाखा में आनेवाले ग्राहकों द्वारा भी इस कैम्प का फायदा उठाया गया.

दिनांक 05.06.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर में शाखा प्रबंधकों हेतु कारोबार आयोजना बैठक 2018–19 का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंचल प्रमुख श्री योगेंद्र सिंह एवं क्षेत्र प्रमुख श्री एम. पी. सिंह ने की.

दिनांक 01.06.2018 को कार्निवल हॉल, रांची में स्टाफ सदस्यों हेतु आयोजित टाउन हॉल मीटिंग के दौरान विजन–2020 योजना की रूप रेखा प्रस्तुत करते हुए श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.

दिनांक 12.04.2018 को रांची अंचल में वृहत ऋण शिविर का आयोजन किया गया. इस अवसर पर लाभार्थियों को ऋण मुहैया कराते श्री विनोद कथूरिया, मुख्य अतिथि एवं कार्यपालक निदेशक; साथ हैं (बाएँ) श्री जी आर पाडलकर, तात्कालीन महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख एवं श्री अंकेश जैन, क्षेत्र प्रमुख, रांची.

अपने रांची दौरे के दौरान दिनांक 01.06.2018 को रांची अंचल स्थित सभी क्षेत्र प्रमुखों की बैठक में उपस्थितों को संबोधित करते हुए श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री राजकिरण रै जी. के कर कमलों से सरल रांची का उद्घाटन किया गया. साथ में श्री अतुल कुमार, अंचल प्रमुख रांची एवं श्री अंकेश जैन, क्षेत्र प्रमुख, रांची.

अपने रांची दौरे के दौरान दिनांक 01.06.2018 को श्री राजकिरण रै जी., प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ ने श्री रघुबर दास, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से मुलाक़ात की. उनके साथ हैं श्री अतुल कुमार, अंचल प्रमुख, रांची एवं श्री अंकेश जैन, क्षेत्र प्रमुख, रांची.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एस सी/ एस टी एम्प्लाईज़ वेल्फेयर एसोसिएशन, दिल्ली द्वारा दिनांक 14.04.2018 को डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर की 127वीं जयंती संसद भवन मार्ग गेट के समक्ष मनाई गई. इस अवसर पर श्री संजय शर्मा, महाप्रबंधक, दिल्ली; श्री सी.बी. झा, उप महाप्रबंधक; श्री ए.के. सिरोही, उप महाप्रबंधक; श्री नवीन जैन, उप महाप्रबंधक के साथ साथ श्री ब्रिजभूषण, महामंत्री, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एस सी/ एस टी एम्प्लाईज़ वेल्फेयर एसोसिएशन, दिल्ली भी उपस्थित थें.

दिनांक 01.06.2018 को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री राजकिरण रै जी. के कर कमलों से नॉर्थ ऑफिस पाड़ा, श्यामली कॉलोनी रांची में 24X7 ई – लॉबी का उद्घाटन किया गया.

On 11th May 2018, Shri Raj Kamal Verma, our ED, inaugurated the revamped SARAL Br., Kolkata. Shri Ishraq Ali Khan, GM & Zonal Head, FGMO, Kolkata & Shri Rajiv Mishra, DGM & Regional Head, Kolkata were also present.

दिनांक 02.06.2018 को कोलकाता क्षेत्र में सीएजी (CAG) का शुभारंभ करते हुए श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ; श्री वी. पी. उशारिया, सीएजी प्रमुख; अंचल प्रमुख श्री इशराक अली खान, महाप्रबंधक, कोलकाता. इस अवसर पर कोलकाता अंचल के अधीन सभी क्षेत्र प्रमुख, क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय के कर्मचारी; एवं सभी शाखा प्रमुख और विपणन अधिकारी उपस्थित थें.

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कोलकाता क्षेत्र में दिनांक 28.05.2018 को आयोजित कारोबार बैठक में कोलकाता के अंचल प्रमुख, श्री इशराक अली खान, महाप्रबन्धक; उप अंचल प्रमुख, श्री गिरीश चन्द्र जोशी, उप महाप्रबन्धक; कोलकाता, क्षेत्र प्रमुख श्री राजीव मिश्रा, उप महाप्रबन्धक; उप क्षेत्र प्रमुख, श्री सिबिल प्रधान, सहायक महाप्रबन्धक; क्षेत्र महाप्रबन्धक कार्यालय, कोलकाता एवं क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के सभी विभागों के विभाग प्रमुख तथा कोलकाता क्षेत्र के सभी शाखा प्रबन्धक सम्मिलित हुए. वित्तीय वर्ष 2017–18 में क्षेत्र के कारोबार में अच्छा प्रदर्शन करने वाली शाखाओं को महाप्रबंधक, कोलकाता के करकमलों से पुरस्कृत किया गया.

On 20th March, 2018 the second E-Lobby of Guwahati Region was inaugurated by Shri Avinash Kumar Singh, FGM, Kolkata and Shri Prakash R. Gupta, Regional Head, Guwahati by lighting the traditional lamp

क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी द्वारा एलसीवी योजना के तहत 51 गाड़ियों हेतु ऋण वितरण किया गया. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में देशबंधु पाड़ा शाखा के ग्राहक को गाड़ी की प्रतिकात्मक चाभी देते हुए श्री इशराक अली खान, महाप्रबंधक एवं श्री बैजनाथ सिंह, क्षेत्र प्रमुख; साथ में हैं श्री बसंत पिंगुआ, शाखा प्रमुख एवं श्री पुरुषोत्तम कुमार, प्रबन्धक, देशबंधु पाड़ा शाखा.

दिनांक 02.06.2018 को कोलकाता क्षेत्र में आयोजित लीडरशिप समिट में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री राजकिरण रै जी.; सीएजी प्रमुख श्री वी. पी. उशारिया, महाप्रबंधक; कोलकाता के अंचल प्रमुख श्री इशराक अली खान, महाप्रबन्धक; उप अंचल प्रमुख श्री गिरीश चन्द्र जोशी, उप महाप्रबन्धक, कोलकाता के साथ क्षेत्र प्रमुख श्री राजीव मिश्रा, उप महाप्रबन्धक; उप क्षेत्र प्रमुख श्री सिबिल प्रधान, सहायक महाप्रबन्धक; श्री कुन्दन लाल, क्षेत्र प्रमुख, हावड़ा; श्री विपण सिंह, क्षेत्र प्रमुख, दुर्गापुर; श्री बी एन सिंह, क्षेत्र प्रमुख सिलीगुड़ी; श्री पी आर गुप्ता, क्षेत्र प्रमुख, गुवाहाटी तथा कोलकाता क्षेत्र के वेतनमान V के शाखा प्रबन्धक भी उपस्थित थें.

Bharat Ratna Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar Jayanti was celebrated at Damodar Hall, Parel, Mumbai on 26th May, 2018. On this occasion Mr. Rajkiran Rai G., MD & CEO addressing the gathering.

क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक की एसएसआई शाखा का नवीनीकरण के उपरांत शुभारंभ दिनांक 07.05.2018 को श्री एच.सी. मित्तल, अंचल प्रमुख के करकमलों से किया गया. इस अवसर पर श्री विनायक टेंभुर्णे, क्षेत्र प्रमुख के साथ श्री मनीष कुमार, शाखा प्रबंधक एवं सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित थें.

दिनांक 14.05.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर में क्षेत्र महाप्रबन्धक श्री एच. सी. मित्तल की अध्यक्षता में कारोबार योजना बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न कारोबारी पैरामीटरों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले शाखा प्रबन्धकों को पुरस्कृत किया गया.

दिनांक 21.06.2018 को 'सरल रोल आउट' कार्यशाला में प्रतिभागियों को सरल लाइट शाखा की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए श्री एस. हेगड़े, सहायक महाप्रबंधक, बीपीटी, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई.

Town Hall Meeting in Mumbai North on 28th June 2018 in the presence of our Hon'ble Shri Kewal Handa, Chairman and Hon'ble Shri Rajkiran Rai G, Managing Director & CEO Sir in Thane. To connect all the staff members with Bank's Vision 2020, we invited one of the Senior Housekeeper, Senior most Award staff & Junior most Officer for lighting of lamp along with diginitaries.

दिनांक 16.05.2018 को श्री एच. सी. मित्तल, क्षेत्र महाप्रबंधक, पुणे के क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्हापुर में आगमन पर आयोजित स्टाफ सदस्यों की बैठक में उपस्थितों को संबोधित करते हुये श्री मित्तल.

दिनांक 14 अप्रैल 2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा डॉ. बी. आर. आंबेडकर की 127 वीं जयंती महोत्सव का आयोजन नागपुर के संविधान चौक के साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय के प्रांगण में किया गया. इस अवसर पर नागपुर के क्षेत्र प्रमुख, श्री पवन कुमार दास (उप महाप्रबंधक); उप क्षेत्र प्रमुख श्री उत्पल कर, सहायक महाप्रबंधक श्री भोलाप्रसाद गुप्ता (सरल), सहायक महाप्रबंधक श्री अरविंद सुसरला (धंतोली शाखा), एससी/एसटी असोसिएशन के प्रमुख श्री वानखेडे, श्री मिलिंद वासनिक, श्री राजेश मेश्राम तथा क्षेत्रीय कार्यालय व शाखाओं के स्टाफ सदस्य उपस्थित थे.

विसनगर तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में श्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को विसनगर के एमएलए, श्री ऋषिकेश पटेल के करकमलों से शील्ड प्रदान की गयी. शील्ड प्राप्त करते हुए श्री अनिल कुमार सिंह चौहान, क्षेत्र प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय, महेसाणा एवं श्री जिनेश पटेल, शाखा प्रमुख, विसनगर शाखा.

दिनांक 17.05.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा द्वारा आमंत्रित शाखाओं की समीक्षा बैठक में उपस्थितों को संबोधित करती हुई श्रीमती मोनिका कालिया, अंचल प्रमुख; साथ में है, श्री राजीव झा, क्षेत्र प्रमुख, बड़ौदा. इस अवसर पर कर्मचारी संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया.

दिनांक 21.06.2018 को 'सरल लाइट, गोवा' का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए श्री एच.सी. मित्तल, क्षेत्र महाप्रबंधक, पुणे तथा श्री पी.सी. राजन, महाप्रबंधक, एमएसएमई, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई.

दिनांक 21.06.2018 को लोनी सहजानपुर ग्राम एवं गुंजला ग्राम में क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक की बीड शाखा द्वारा आयोजित शेतकरी मेले में श्री सचिन माली, सहायक महाप्रबंधक एवं श्री भोला राम सैनी, शाखा प्रबन्धक उपस्थित थें.

दिनांक 18.04.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा में आयोजित शाखा प्रमुखों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री केवल हांडा, बैंक के अध्यक्ष; साथ में हैं श्रीमती मोनिका कालिया, अंचल प्रमुख; श्री राजीव झा, क्षेत्र प्रमुख, बड़ौदा एवं अन्य कार्यपालक तथा शाखा प्रमुख.

दिनांक 26.04.2018 को श्री राजीव कुमार झा, क्षेत्र प्रमुख, बड़ौदा के नेतृत्व में टीम बड़ौदा द्वारा क्यूआर कोड जनरेशन हेतु विशेष अभियान की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत बैंक द्वारा वित्तपोषित एलसीवी हेतु क्यू.आर. कोड इंस्टॉलेशन (भीम ऍप के माध्यम से उधारकर्ताओं के बचत खाते में भुगतान प्राप्त करने हेतु) का प्रारम्भ किया गया.

दिनांक 17.05.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा में बैंक के महत्वपूर्ण ग्राहकों हेतु आयोजित ग्राहक संगोष्ठी में ग्राहकों से वार्तालाप करती हुई श्रीमती मोनिका कालिया, अंचल प्रमुख; साथ में हैं श्री राजीव झा, क्षेत्र प्रमुख, बड़ौदा. इस कार्यक्रम में बड़ौदा क्षेत्र के सभी कर्मचारियों हेतु कर्मचारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था.

क्षे.का., अहमदाबाद में 21 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ सदस्य योगासन करते हुए.

दिनांक 10.05.2018 को जिलाधिकारी कार्यालय, नासिक में आयोजित 'डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर समिति' की बैठक में 'वार्षिक क्रेडिट प्लान' का लोकार्पण किया गया. इस अवसर पर सर्वश्री तांबट, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र; तावरे, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र; राधाकृष्णन, जिलाधिकारी, नासिक; विनायक टेंभुर्णे, उप महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नासिक तथा बर्वे, जिला अग्रणी प्रबन्धक उपस्थित थे.

दिनांक 28.06.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक की नरढ़ाने शाखा द्वारा किसानों के लिए 'सुलभ फसल ऋण मेले' का आयोजन विविध कार्यकारी सोसाइटी, नरढ़ाने में किया गया, जिसमें किसानों को मार्गदर्शन करने हेतु शाखा प्रबन्धक एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित थे.

क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक की दोंडाईचा शाखा द्वारा ग्रामवासियों के लिए दिनांक 21.06.2018 को पाटीलवाड़ी लॉन्स में आयोजित वित्तीय साक्षरता अभियान के अवसर पर श्री विनायक टेंभुर्णे, क्षेत्र प्रमुख, नासिक; श्री पी.सी. पाणिग्रही, महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन विभाग; केंद्रीय कार्यालय; श्री सरकारसाहेब रावल, अध्यक्ष, दादासाहेब रावल उद्योग समूह; श्री नारायण पाटील, सभापति, बाजार समिति; श्री बी.एस. ठाकुर, शाखा प्रबन्धक, दोंडाईचा शाखा एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित थे.

दिनांक 25.06.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक की नायगांव शाखा द्वारा स्वयं सहायता समूह के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय, नायगांव में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर के दौरान स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री योगेश पाटील, शाखा प्रबंधक, नायगांव शाखा.

दिनांक 14.04.2018 को आंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र प्रमुख श्री विनायक टेंभुर्णे तथा उप क्षेत्र प्रमुख श्री पी.वी.जे.एन. मूर्ति द्वारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण किया गया. इस अवसर पर नासिक क्षेत्र की जेल रोड शाखा द्वारा सुबह 9 बजे से रात के 7 बजे तक सार्वजनिक रूप से पानी एवं बिस्कुट भी वितरित किये गये.

दिनांक 23.06.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक की जामखेड़ शाखा एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओबीसी असोसिएशन द्वारा जामखेड़ ग्राम में आयोजित पुस्तक वितरण समारोह में विद्यार्थियों को किताबें भेंट करते हुए श्री अरूप दास, मुख्य प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक एवं श्री धीरजकुमार घुगे, शाखा प्रबन्धक, जामखेड़ शाखा.

दिनांक 25.05.2018 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा मुन्नार शाखा का निरीक्षण किया गया. इस उप समिति के संयोजक माननीय श्री हुकुम नारायण यादव (सांसद), समिति के माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश नारायण यादव (सांसद) एवं डॉ. ए. संपत (सांसद) उपस्थित रहे. समिति सचिवालय के सचिव श्री एस.एस. राणाजी एवं अनुसंधान अधिकारी श्री कमल स्वरूप, श्री मुकेश शर्मा, अनुसंधान सहायक, श्री देवेन्द्र सिंह गोसाई, समिति सहायक एवं श्री जय प्रकाश जांगिड़, रिपोर्टर भी उपस्थित थे. इस अवसर पर हमारे बैंक की ओर से श्री ब्रजेश्वर शर्मा, महाप्रबंधक (मां. सं.), केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई; श्री एस. के. महापात्रा, क्षेत्र महाप्रबंधक, चेन्नै; श्री राजेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक (रा.भा); श्री वी. प्रदीप, क्षेत्रीय प्रमुख, कोट्टयम एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे.

क्षे. का., मदुरै के अंतर्गत आनेवाली तिरुचित्राम्बलम शाखा में एनपीए रिकवरी कैंप में भाग लेते हुए श्री एस.के. मोहपात्रा, अंचल प्रमुख और श्री श्रीनिवास वांग्ला, क्षेत्र प्रमुख, मदुरै.

क्षे. का., मदुरै में दिनांक 25.05.2018 को सुरक्षा अधिकारी द्वारा 'अग्नि सुरक्षा' पर प्रशिक्षण दिया गया. इस अवसर पर अग्नि सुरक्षा की जानकारी देते हुए सुरक्षा अधिकारी श्री एम. प्रवीण कुमार.

नो. क्षे. का., बेंगलुरु द्वारा दिनांक 03.05.2018 को होटल सदर्न स्टार में क्षेत्र के समस्त शाखा प्रबंधकों की उपस्थिति में आयोजित 'शिखर नेतृत्व सम्मेलन 2018' के दौरान उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु कैंटोनमेंट शाखा, बेंगलुरु के शाखा प्रबंधक श्री एच.वी. नारायण, सहायक महाप्रबंधक को प्रशस्ति पत्र व शील्ड प्रदान कर सम्मानित करते हुए श्री एस.एन. कौशिक, क्षेत्र महाप्रबंधक, बेंगलुरु; साथ में हैं (बाएँ से) श्री अजय कुमार, सहायक महाप्रबंधक; श्री संजय कुमार रथ, सहायक महाप्रबंधक, क्षेत्र प्रमुख, बेंगलुरु; श्री आलोक कुमार, उप महाप्रबंधक व श्री बी. सुहास, सहायक महाप्रबंधक.

दिनांक 09 से 11 अप्रैल, 2018 तक स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलुरु में संपन्न सुरक्षा अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करते हुए श्री कल्याण कुमार, प्राचार्य, स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलुरु; साथ में (बाएँ से) अतिथि वक्ता प्रोफेसर वेणुगोपाल अयंगर; कैप्टन एन. गोपालकृष्णन, सहायक महाप्रबंधक व ब्रिगेडियर आशुतोष सिरौठिया (सेना मेडल), बैंक के मुख्य सुरक्षा अधिकारी.

On 14th February, 2018 Union Bank's Social Foundation has donated ₹ 14,03,043/- for purchase of 42 computers and accessories to Bunt's Alias Nadavara Mathr Sangha, Sri Ramakrishna Vidyarthi Bhavana, Mangalore. Mr. Rajkiran Rai G., MD & CEO of Union Bank of India inaugurating Lab consisting of 42 computers.

दिनांक 14 फरवरी, 2018 को यूनियन बैंक सोशल फ़ाउंडेशन द्वारा चेतना स्पेशल स्कूल, (for mentally challenged children) मंगलोर को कक्षाओं के संचालन हेतु 3 कमरे प्रदान किए गए, जिसका उद्घाटन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री राजकिरण रै जी. ने अपने करकमलों से किया और वहाँ के दिव्यांग बच्चों को टिफिन बॉक्स भी प्रदान किए.

During his visit to Ernakulam Region, Shri Vinod Kathuria, ED addressed all the staff members. He also inaugurated the renovated premises of Willingdon Island Branch. On this occasion, the Regional Office has organized a LCV camp in which 51 loans to the tune of ₹ 1.42 crores were sanctioned.

क्षेत्रीय कार्यालय, मैंगलोर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा हमारे देश के संविधान निर्माता व महान विद्वान डॉ. भीमराव अम्बेडकर को उनकी जन्मतिथि 14 अप्रैल 2018 के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन कर उनके अतुलनीय योगदान को याद किया गया.

Inauguration of our RSETI (Rural Self Employment Training Institute) building at Nellad in Ernakulam Region was inaugurated on 05.05.2018 by Prof K.V. Thomas, MP in the presence of Shri Ravi Kumar Gupta, GM, RABD, C.O.; Shri. P.S.Rajan, GM, MSME and Shri A.Krishnaswamy, Regional Head, Ernakulam look on.

Mrs. Rajshri Baglari, DGM, ZAO, Hyderabad addressing concurrent auditors at Hotel Swarna Palace, Vijayawada on 21st June, 2018 while Dr.K.Ravindranath, DGM and Shri G.Jayajeevan, DRH, NRO, Vijayawada look on.

क्षेत्रीय कार्यालय, नेल्लूर के अंतर्गत दिनांक 04.02.2018 को वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन, के जी के कल्याण मंड़पम, नेल्लूर में धूमधाम से सम्पन्न हुआ. कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आनेवाले सभी 06 ज़िला मुख्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया. इस दौरान विजेता टीम के साथ श्री एस. जवाहर, क्षेत्र प्रमुख, नेल्लूर (दाएँ से प्रथम).

दि. 08.04.2018 को पोरंकि शाखा, नोक्षेका, विजयवाड़ा में आयोजित स्वयं सहायता समूह एवं एलसीवी मेले में एसएचजी लाभार्थियों को ₹ 1,25,00,000/– का चेक प्रदान करते हुये प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री राज किरण रै जी. साथ में हैं, श्री के.पी. आचार्य, क्षेत्र महाप्रबन्धक, बेंगलुरू; श्री पी. सुगतन, उप क्षेत्र प्रमुख, विजयवाड़ा एवं श्री डी. रामा राव, शाखा प्रबन्धक, पोरंकि शाखा. इस अवसर पर प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के घरेलू उत्पादों को भी स्वीकार किया गया.

दिनांक 8.4.2018 को पोरंकि शाखा, नोक्षेका, विजयवाड़ा में स्वयं सहायता समूह एवं एलसीवी मेले का आयोजन किया गया. इस अवसर पर एलसीवी ऋण लाभार्थी को चेक एवं गाड़ी की चाबी प्रदान करते हुए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री राज किरण रै जी. साथ में हैं, श्री के.पी. आचार्य, क्षेत्र महाप्रबन्धक, बेंगलुरू; डॉ. के. रवीन्द्रनाथ, उप महाप्रबन्धक, नो. क्षे.का., विजयवाड़ा; श्री डी. रामा राव, शाखा प्रबन्धक, पोरंकि शाखा एवं शाखा के अन्य सदस्य.

दिनांक 8.4.2018 को नोडल क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा के अंतर्गत सरल कार्यालय का शुभारंभ करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री राज किरण रै जी; साथ में है, श्री के पी आचार्य, क्षेत्र महाप्रबन्धक, बेंगलुरू एवं डॉ. के. रवीन्द्रनाथ, उप महाप्रबन्धक, नो.क्षे.का., विजयवाड़ा

दिनांक 12.3.2018 को विजयवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत उप्पलपाडु शाखा के नए परिसर का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए श्री के.पी. आचार्य, क्षेत्र महाप्रबन्धक, बेंगलुरु. साथ में हैं, डॉ. के. रवीन्द्रनाथ, उप महाप्रबन्धक, नो.क्षे.का., विजयवाड़ा एवं श्री सी. चिट्टि बाबू, शाखा प्रबन्धक, उप्पलपाडु शाखा, विजयवाड़ा .

दिनांक 14.4.2018 को डॉ. आंबेडकर जयंती के अवसर पर गरीब महिलाओं को कपड़े प्रदान करते हुए डॉ. के. रवीन्द्रनाथ, उप महाप्रबन्धक, नो.क्षे.का., विजयवाड़ा.

'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत 3 डबल डेकर बैटरी चालित वाहन खरीद हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै द्वारा श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की उपस्थिति में कमिश्नर, मदुरै कॉर्पोरेशन को ₹ 5,70,000/– का चेक भेंट किया गया. इस अवसर पर श्री अनीस शेखर, आईएएस, मदुरै; श्री श्रीनिवास वंगला, क्षेत्र प्रमुख, मदुरै एवं श्री बेन्नी स्टीफन, उप क्षेत्र प्रमुख उपस्थित थे.

नोक्षेका, विजयवाड़ा में दिनांक 8.4.2018 को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री राजकिरण रै जी. द्वारा स्टाफ मीटिंग के दौरान विजयवाड़ा नो. क्षे. का. तथा शहर की स्थानीय शाखाओं के स्टाफ सदस्यों को संबोधित किया गया. चित्र में महिला स्टाफ सदस्यों के साथ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री राजकिरण रै जी.; श्री के. पी आचार्य, क्षेत्र महा प्रबन्धक, बेंगलुरू एवं डॉ. के. रवीन्द्रनाथ, उप महाप्रबन्धक, नो.क्षे. का., विजयवाड़ा.

श्री एस.एन. कौशिक, अंचल प्रमुख, बेंगलुरु के प्रथम नेल्लूर आगमन के अवसर पर बैंक द्वारा क्षेत्रीय सुब्बा राय स्टेडियम को एक वॉटर कूलर प्रदान किया गया, जिसका औपचारिक उदघाटन दिनांक 08.06.2018 को फीता काटकर करते हुए श्री एस.एन. कौशिक (दायें से द्वितीय) तथा श्री अब्दुल अज़ीज़, मेयर, नगर निगम, नेल्लूर (बाएँ से द्वितीय); साथ में हैं श्री एस. जवाहर, क्षेत्र प्रमुख, नेल्लूर (बाएँ से प्रथम).

दिनांक 24.6.18 को कुरुमद्दाली गाँव में यूनियन बैंक सोशल फ़ाउंडेशन की ₹ 2.75 लाख की सहायता से 'बल्लकट्टू' की मरम्मत की गयी, जिसका शुभारंभ श्री के. वीरय्य चौधरी, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के कर कमलों से किया गया. इस अवसर पर साथ में हैं श्री एस.एन. कौशिक, क्षेत्र महाप्रबन्धक, बेंगलूरु; श्रीमती ज़ी. अनुराधा, चेयर पर्सन, जेड्पीटीसी; श्रीमती यू. कल्पना, स्थानिक एमएलए.

इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में अपने निजी प्रयासों द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने पर श्री आर्को चक्रवर्ती, सहायक प्रबंधक को श्री श्रीनिवास वांग्ला, क्षेत्र प्रमुख, मदुरै और श्री आई. विश्वनाथन उप महाप्रबंधक, सीएएनआईडी सम्मानित करते हुए.

दिनांक 08.06.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, नेल्लूर के अंतर्गत 'सरल लाइट शाखा' का औपचारिक उद्घाटन श्री एस.एन. कौशिक, क्षे.म.प्र., बेंगलुरु (मध्य में) द्वारा किया गया. इस अवसर पर (बाएँ से) श्री एस. जवाहर, क्षेत्र प्रमुख, नेल्लूर (बाएँ से द्वितीय) और श्री जी. श्रीनिवास, प्रमुख, सरल लाइट शाखा (दायें से प्रथम) के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, नेल्लूर एवं सरल लाइट के सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित थें.

हेल्थ टिप्स

# रसीली लीची

दिखने में बेहद आकर्षक और बारिश के शुरूआती दिनों में बाजारों की रौनक बढ़ाने वाला फल है 'लीची'! ऊँचे पेड़ों, घनी हरी पत्तियों के बीच गहरे लाल रंग के बड़े-बड़े गुच्छों में लटके लीची के फल देखते ही बनते हैं. लीची का मूल स्थान दक्षिण चीन माना जाता है. भारतवर्ष में लीची का आगमन सत्रहवीं शताब्दी के अंत में म्यांमार होते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ. भारत में इसकी बागबानी सबसे ज्यादा बिहार के मुजफ्फरपुर में की जाती है. गर्मी के मौसम में आने वाली सुर्ख रंग की लीची स्वाद में तो रसीली और मजेदार है ही, सेहत के मामले में भी इसके फायदे बेमिसाल हैं.

- ❖ लीची में पानी की मात्रा भी काफी होती है. इसमें विटामिन सी, पोटैशियम और नैसर्गिक शक्कर की भरमार होती है. गरमी में खाने से यह शरीर में पानी के अनुपात को संतुलित रखते हुए ठंडक भी पहुँचाता है.
- ❖ विटामिन सी, फ्लेवोनॉयड, क्यूरसीटीन जैसे तत्वों से भरपूर लीची में कैंसर, खासतौर पर स्तन कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के गुण पाए जाते हैं.
- ❖ लीची एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है. इसमें मौजूद विटामिन सी हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं के निर्माण और लोहे के अवशोषण में भी मदद करता है, जो एक प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए जरूरी है.
- ❖ लीची हमारी सेहत के साथ ही फिगर का भी ध्यान रखती है. इसमें घुलनशील फाइबर बड़ी मात्रा में मिलता है, जो मोटापा कम करने का अच्छा विकल्प है. साथ ही यह वायरस और संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. इसमें सैच्युरेटेड फैट या संतृप्त वसा बिल्कुल भी नहीं होता. बी- कॉम्प्लेक्स और बीटा कैरोटीन से भरपूर लीची, फ्री रेडिकल्स से रक्षा करती है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करता है. इसमें मौजूद फोलेट हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखता है. इसके सेवन से आपको कब्ज से राहत भी मिलती है.
- ❖ थकान और कमजोरी महसूस करने वालों के लिए लीची ऊर्जा का स्त्रोत है.
- ❖ लीची का रस एक पौष्टिक तरल है. यह गर्मी के मौसम से संबंधित समस्याओं को दूर कर शरीर को ठंडक पहुंचाता है. यह कब्ज या पेट में हानिकारक टॉक्सिन के प्रभाव को कम करती है. गुर्दे की पथरी से होने वाले पेट दर्द से आराम पहुंचाती है. मधुमेह के रोगियों के तंत्रिका तंत्र को होने वाली क्षति को रोकने में मदद करती है.
- ❖ लीची विटामिन सी का बहुत अच्छा स्त्रोत होने के कारण खांसी-जुकाम, बुखार और गले के संक्रमण को फैलने से रोकती है.
- ❖ लीची में सूरज की अल्ट्रावॉयलेट यूवी किरणों से त्वचा और शरीर का बचाव करने की खासियत होती है.
- ❖ लीची में पाए जाने वाले कैल्शियम, फॉसफोरस और मैग्नीशियम तत्व बच्चों के शारीरिक गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये मिनरल्स अस्थि घनत्व को बनाए रखते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करते हैं.
- ❖ लीची में मौजूद पोटेशियम दिल की बीमारियों से बचाव करता है.
- ❖ लीची का फल ही नहीं बल्कि बीज और छिलका भी फायदेमंद है. लीची के बीज के पाउडर में दर्द से राहत पहुंचाने के गुण हैं. पाचन संबंधी विकारों को दूर करने के लिए बीज के पाउडर की चाय पीना फायदेमंद है.

लेकिन हाँ, इसका सेवन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में इसका सेवन नुकसानदेह हो सकता है. एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक कटोरी या 10-11 लीची का सेवन हितकर है. ज्यादा खाने से नकसीर या सिर दर्द या एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. तो सावधानी बरतते हुए लीची का लुत्फ उठाएँ, सेहत बनायें!

*सुप्रिया नाडकर्णी*
*यूनियन धारा, कें.का.*

व्यंजन

# शीर ख़ुरमा

**शीर ख़ुरमा के लिए आवश्यक सामग्री :** आधा कप भुनी हुई सेवइयाँ, 1 लीटर दूध, ड्राइ फ्रूट - काजू, बादाम, चारुले, पिस्ता, तथा इलायची, खोया एवं घी.

शीर ख़ुरमा बनाने के लिए दो-तीन दिन पूर्व बादाम, चारुले एवं पिस्ता को थोड़े गरम पानी में आधे घंटे भीगोकर रखें ताकि इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे. चारुले एवं पिस्ता के छिलके निकालने के लिए एक सूती के सफ़ेद रुमाल में इसे रखें और दोनों हाथों से रगड़े. पाँच मिनट में सारे छिलके निकल जाएंगे. फिर इन्हें लंबे आकार में काट लें और प्लेट में सुखाने के लिए रखें. काजू को भी काट कर रखें. सूखने के बाद सभी ड्राइ फ्रूट को अच्छी तरह से घी में भून लें.

**विधि :** सबसे पहले हांडी में घी डालें, घी गरम हो जाने के बाद उसमें स्वादानुसार शक्कर, इलायची, गुलाब जामुन का खोया (या दूध की मलाई फ्रिज में बचाकर रखी हो तो खोया के एवज़ में लें) और दूध डालें. दूध को अच्छा उबलने के बाद उसमें भुनी हुई सेवइयों को तोड़कर डालें. 10 मिनट के बाद गैस को बंद करें तथा उसमें सभी भुना हुआ ड्राइ फ्रूट डालें. इस तरह से आपका शीर ख़ुरमा तैयार है, अब गरमा-गरमा शीर ख़ुरमे का स्वाद लें.

*शमा शिकलगर*
*कें. का., मुंबई*

# आपकी पाती
# Opinion Gallery

"It is a wonderful 'Womens' Special' Of Union Dhara brought out by Union Bank of India under your dynamic, thoughtful Editorial support with the guidance of the enterprising MD & CEO Sri Rai. After taking VRS from the Bank while working with you all as General Manager (Retail Banking) in May 2006 to join as ED of Dhanalakshmi Bank, now I came across this Magazine which covered a variety of topics not only focusing on women, but even developing individuals. My heartfelt congratulations for bringing out this 92 page unique issue. My special appreciation to GM (HR) and MD & CMD for getting success in this effort."

**– VSR Murthy**
MD, Quantum Group of Companies
KL Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia

"The special feature titled "Role of Leaders in fostering excellence in Banking" appearing in the December 2017 issue of Union Dhara made an absorbing reading. Six valuable tips for fostering excellence are vividly and nicely spelt out with total clarity. Team work is critical for overall success in any business organization creating a feeling of togetherness. Trust is an important component in the process without which the delegation will possibly not achieve its true purpose. Attitude determines our altitude which is borne out of motivation. Learning is a continuous process and age is no bar to it constant updation of skills and knowledge will help us to stay ahead of curve and gain the winning edge. Striving to benchmark with the best helps us to deliver the best and stay afloat. It was so nice to have quoted the words of Mother Teresa "You can do what I cannot do. I can do what you cannot do. Together we can do great things" which is pertinent in the context. As always, the other articles on Bitcoin, Meditation, Law and Lawyers, Exploring within, etc. provide deep insights and knowledge additions. Thanks to the editorial team for an excellent issue."

**– Srinivasan Umashankar**
Bank of Maharashtra, Nagpur

"यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गृह पत्रिका 'यूनियन धारा' प्राप्त हुई, पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि 'यूनियन धारा' अन्य गृह पत्रिकाओं की भांति रस्म अदायगी से कोसों दूर है. पत्रिका का बहुरंगी कलेवर और सौन्दर्यपूर्ण प्रकाशन अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है. जे एस तोमर का लेख 'ईमानदारी और भ्रष्टाचार क्या है' में जन भागीदारी, आर टी आई के अवलोकन द्वारा बात कहना प्रभावशाली प्रस्तुति है. अजय कुमार का लेख बैंकिंग जीविका के रूप में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बैंक कर्मियों के जीवन का यथार्थ दर्शाता है. पत्रिका की सम्पूर्ण टीम को बहुत–बहुत शुभकामनाएँ! उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी पत्रिका पढ़ने का लाभ मिलता रहेगा."

**– शक्तिवीर सिंह**
राजभाषा अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै

"'Mahila Vishesh' Union dhara was a nice treat with variety of views on the progress of women. Being the first of its kind, it shall motivate the staff for sure ..Your writings, on banking, health and food culture has elevated to appreiable heights. Keep going!... My sincere wishes to you all."

**– Naina Kulkarni**
Retd. Staff, Navi Mumbai

"यूनियन धारा का महिला विशेषांक प्राप्त हुआ. अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में स्त्री विषयक अच्छी सामग्री पत्रिका में संयोजित की गई है. कृष्णा सोबती के बारे में संक्षेप में अच्छी जानकारी प्रस्तुत की गई है. पत्रिका के इस अंक के लिए बधाई स्वीकारें."

**– डॉ./प्रोफे. (श्रीमती) बीनय षडंगी राजाराम**
संस्थापक निदेशक, सप्तवर्णी कला–साहित्य सृजन–शोध पीठ, भोपाल
एवं उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास, दिल्ली

"यूनियन धारा का 'महिला विशेष' अंक प्राप्त हुआ. अंक में प्रकाशित सामग्री बहुत ही सुंदर बन पड़ी है – विशेषतः लेख 'धर्म और नारी' एवं 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास! मुख पृष्ठ भी बहुत ही सुंदर बन पड़ा है. आपके दिसंबर 2017 अंक में प्रकाशित 'ऋणवसूली एवं सतर्कता' विशेष के लेख बहुत अच्छे लगे. इस अंक की सामग्री लाजवाब है. आपको बहुत बहुत बधाई!"

**– एस.सी. सिंहल**
सेवा निवृत्त अधिकारी, मेरठ

"'यूनियन धारा' का महिला विशेषांक एक संग्रहणीय अंक है. इसमें प्रकाशित लेखों से जहां एक ओर यह जानकारी प्राप्त होती है कि 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला दिवस का प्रारम्भ हुआ वहीं 'Success stories of Women' जैसे लेखों से महिलाओं के विशिष्ट योगदान की एक झलक मिलती है. महिलाओं के लिए बैंक के विविध कार्यालयों द्वारा आयोजित विशेष कार्यशालाओं/सम्मेलनों से बैंक की नारी शक्ति का समृद्ध परिदृश्य पाठकों के मन में स्थापित हुआ है. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज बैंक की हर शाखा में महिलाएं बेहतरीन ग्राहक सेवा प्रदान कर रही है, इतना ही नहीं कार्य के बोझ को वे हँसते–खेलते हल्का कर देती हैं और इससे customer satisfaction' के साथ साथ 'customer delight' की स्थिति से बैंक जनता की निगाह में बैंकिंग उद्योग में अग्रणी बन चुका है. 'यूनियन धारा' के संपादक मण्डल को अनेक अभिनंदन और आगामी अंकों को इसी की श्रृंखला में उत्कृष्टता से प्रकाशित करने के लिए शुभकामनायें!"

**– हेमंत कुमार भट्ट,** सेवानिवृत्त

**Union Dhara, R. N. 27989/76**

*छायाचित्र : पी. अभिलाष, क्षे.का. त्रिवेंद्रम*

*काले बादलों से ढंका आसमान और समुंदर की उफनती लहरें*
*यह समय है, जब आसमान की पिघलती हुई स्वर्णिम आभा*
*धीरे धीरे तब्दील होती जाएगी, स्याह अंधेरी रात में*
*तब माँ का साथ पाकर एक बचपन खड़ा है, समुंदर किनारें*
*आज उसके साथ भरोसे का हाथ है औ' उसे कल का इंतजार है.*

*– डॉ. सुलभा कोरे*

Printed and published by Dr. Sulabha Kore on behalf of Union Bank of India and printed at SAP PRINT SOLUTIONS PVT. LTD. Lower Parel, Mumbai-400013 and published at Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhawan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021. Editor -Dr. Sulabha Kore.